<u>भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1, खंड-1 में प्रकाशनार्थ</u>

फा. संख्या 6/25/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांकः 28.03.2025

अंतिम जांच परिणाम
मामला संख्याः सीवीडी(ओआई)-03/2023

विषय: चीन जन.गण. और ताइवान के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (डीओपीपी) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी जांच।

1. मैसर्स टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड (जिसे आगे **"घरेलू उद्योग"** कहा गया है) सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे **"सीमा प्रशुल्क अधिनियम"** कहा गया है) और सीमा प्रशुल्क (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे **"सीवीडी नियमावली"** कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे **"प्राधिकारी"** कहा गया है) के समक्ष चीन जन.गण. और ताइवान ("संबद्ध देश") के मूल के अथवा वहां ये निर्यात किए गए "**डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स"** ("विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "डिजिल प्लेट्स" अथवा **"डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स"**) के आयातों के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी जांच आरंभ करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 6/25/2023-डीजीटीआर दिनांक 29.09.2023 के अंतर्गत सीवीडी नियमावली के नियम 6 के अनुसार कथित सब्सिडी और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे की जांच शुरू की है, ताकि कथित सब्सिडी के मौजूद होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके

और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि लगाई जाए, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

क. <u>प्रक्रिया</u>

3. जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने सी.वी.डी. नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार जांच आरंभ करने से पूर्व भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान प्रतिसंतुलनकारी आवेदन प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात के संबंध में प्रतिसंतुलनकारी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 29 सितंबर 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

iii. सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते ("एएससीएम") के अनुच्छेद 13 के अनुसार, प्राधिकरण ने संबंधित देश की सरकार को परामर्श के लिए आमंत्रित किया ताकि उन्हें आवेदन में संदर्भित मामलों के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

iv. प्राधिकरण ने नोट किया कि चीन और ताइवान की सरकारों को लिखित संचार और परामर्श के माध्यम से आवेदकों द्वारा दावा की गई विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के अस्तित्व, संचालन और प्रशासन, डब्ल्यूटीओ एएससीएम और भारतीय नियमों के संदर्भ में उनकी प्रतिसंतुलनशीलता और इन योजनाओं के तहत संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। चीन पीआर और ताइवान की सरकारों द्वारा दायर किए गए उत्तरों को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड में लिया गया है और उनकी जांच की गई है।

v. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, संबद्ध आयातों के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 09.11.2023 को जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचनाओं में निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं और जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने अनुरोधों से लिखित रूप में अवगत कराएं।

vi. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 6(5) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को दिनांक 09.11.2023 के अपने ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराई।

vii. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली के उत्तर जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें। संबद्ध देशों के दूतावासों को संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी भेजी गई थी।

viii. प्राधिकारी ने सीवीडी नियमावली, 1995 के नियम 7(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी:

i झेजियांग जिनरुइटाई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

ii हुआंगशान जिनरुइटाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

iii अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

iv चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड

v लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड

vi कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड

vii फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड

viii फुजीफिल्म (चीन) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

ix. 1 दिसंबर, 2023 को, प्राधिकारी ने संबद्ध जांच में उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति पर चर्चा की। तदनुसार, प्राधिकारी ने 12 जनवरी, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से संबद्ध जांच में पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया। इसके बाद, हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा परिचालित प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी, 2024 तक का समय दिया गया था। निर्यातकों के अनुरोध पर, प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 15 फरवरी, 2024 तक का समय विस्तार दिया।

x. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

l झेजियांग जिनरुइटाई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

ii हुआंगशान जिनरुइटाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

iii अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

iv चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड

v लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड

vi कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड

vii फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड

viii फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन, जापान

ix फुजीफिल्म (चीन) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड

x ईस्टमैन कोडक कंपनी

xi. संबद्ध देशों के जिन उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जांच में असहयोगी माना गया है।

xii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भी भेजी जिसमें सी.वी.डी. नियमावली, 1995 के नियम 7(5) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई थी।

xiii. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत या कानूनी प्रस्तुतियों के साथ समय पर जवाब किए:

i. कपूर इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
ii. फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iv. निप्पॉन कलर
v. प्रिंटच
vi. स्क्रीन पॉइंट सिस्टम
vii. ट्रायो प्लेट सिस्टम
viii. श्री प्रियन ग्राफिक्स
ix. वीपीआर डिजिटल और कार्ड्स

x. ब्लू स्टार प्रिंटर्स
xi. सुदर्शन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xii. प्रिंटलाइन सिस्टम - सीटीपी ब्यूरो
xiii. माँ इमेजेस
xiv. स्कैन ग्राफिक सिस्टम
xv. भाग्यम बाइंडिंग वर्क्स
xvi. एम/एस कलर सॉल्यूशंस
xvii. कल पब्लिकेशन्स
xviii. थॉमसन प्रेस

xiv. इसके अतिरिक्त, भारत से एक संघ, अर्थात्, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स ("एआईएफएमपी") ने जांच में भाग लिया।

xv. प्राधिकारी ने वाणिज्यिक सूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से जांच अवधि और क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के लिए लेनदेनवार आयात आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा करने पर पाया गया कि एक प्रविष्टि बिल के अंतर्गत कई लाइन आइटम को 1 आयात लेनदेन में मिला दिया गया था। दूसरी ओर, आवेदक ने दावा किया कि उत्पादों के आयामों के आधार पर प्रत्येक लाइन आइटम के लिए मात्रात्मक सूचना की गणना की जा सकती है। इसलिए, प्राधिकारी जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर भरोसा नहीं कर सके और उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा किया है। हालांकि, जांच के दौरान, सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात का लेनदेनवार ब्यौरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। वह प्राधिकारी को प्राप्त हो गया था और वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से उस पर विचार कर लिया गया था।

xvi. सी.वी.डी. नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 17 जनवरी, 2025 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से संबद्ध जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें, उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, तो उसे प्रस्तुत करें। हितबद्ध पक्षकारों को यह भी निर्देश दिया गया

कि था कि वे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ अपने द्वारा प्रस्तुत लिखित अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर साझा करें।

xvii. क्षति रहित कीमत (जिसे आगे "एनआईपी" कहा गया है) का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध III के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सब्सिडी मार्जिन से कमतर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

xviii. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और सत्यापन मौके पर सत्यापन के दौरान उस सीमा तक किया गया है, जिस सीमा तक उसे माना गया तथा वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के लिए उस पर भरोसा किया गया है।

xix. संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और सत्यापन भी जहां तक आवश्यक समझा गया, किया गया तथा वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के उद्देश्य से उस पर भरोसा किया गया है।

xx. जांच के आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, 20 मार्च, 2025 को इच्छुक पक्षों को जारी किया गया था, और इच्छुक पक्षों को इस पर टिप्पणी करने के लिए 25 मार्च, 2025 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में, इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर, प्रासंगिक और गैर-दोहराव वाली सीमा तक विचार किया गया है।

xxi. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति जांच अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और जांच की अवधि है।

xxii. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आपसी आधार पर प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के माध्यम से निर्धारित तरीके से उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना/अनुरोधों की जांच गोपनीयता के ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीयता के दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने ऐसी सूचना/अनुरोधों को गोपनीय माना है। गोपनीयता के दावों को स्वीकार न करने की स्थिति में, हितबद्ध पक्षकारों को उसी का अगोपनीय रूपांतर प्रस्तुत करने और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित करने के निर्देश दिए गए थे।

xxiii. प्राधिकारी ने इस स्तर पर सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए सभी तर्कों और उपलब्ध कराई गई सूचना पर इस सीमा तक विचार किया है जिस सीमा तक वे साक्ष्य से समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने जाते हैं।

xxiv. इस अंतिम निष्कर्ष में '***' एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को दर्शाता है तथा प्राधिकारी द्वारा सी.वी.डी. नियमावली, 1995 के नियम 8 के अंतर्गत उस पर विचार किया गया है।

xxv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की अवधि हेतु विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 80.29 भारतीय रुपए है।

ख. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

4. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद तीन प्रकार के होते हैं: i. थर्मल प्लेट्स; ii. वायलेट प्लेट्स; और iii. सीटीसीपी/यूवी सीटीपी प्लेट्स । प्राधिकारी ने लागत और कीमत में अंतर के आधार पर इन तीन प्रकारों को अलग-अलग पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) के रूप में वर्गीकृत किया है।

ii. मूल जांच में, हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग कुछ उत्पाद प्रकारों का उत्पादन नहीं करता है: i. डबल लेयर सीटीसीपी प्लेट्स; ii. नेगेटिव वर्किंग यूवी सीटीपी प्लेट्स; iii. वाणिज्यिक पैमाने पर प्रक्रिया रहित प्लेट्स के अन्य प्रकार (अर्थात्, वायलेट और यूवी सीटीपी); iv. वाणिज्यिक पैमाने पर केम-मुक्त यूवी सीटीपी प्लेट्स । समानांतर निर्णायक समीक्षा में, प्राधिकारी ने इन उत्पादों को बाहर रखा। तदनुसार, उन्हें वर्तमान जांच में बाहर रखा ही जाना चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

5. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. डिजिटल प्लेट्स का उपयोग मुद्रण उद्योग में डेटा को एक छवि (डॉट पैटर्न या पाठ) के रूप में कागज पर या टिन शीट, पॉली फिल्म आदि जैसे गैर-शोषक सब्सट्रेट पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग करके मुद्रण प्रक्रिया में, डिजिटल वर्कफ़्लो एक छवि को 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) में लेजर का उपयोग करके सीधे स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है, एनालॉग वर्कफ़्लो के विपरीत जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है।

ii. विचाराधीन उत्पाद भारत में स्वतंत्र रूप से आयात योग्य है और किसी भी आयात प्रतिबंध के अधीन नहीं है।

iii. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स उच्च शुद्धता वाले लिथो-ग्रेड एल्युमीनियम कॉइल से बनाई जाती हैं, जिन पर रासायनिक कोटिंग की जाती है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स या तो सकारात्मक (बिना उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) वर्किंग प्लेट्स हो सकती हैं।

iv. कोटिंग घटक, जिन्हें 'सेंसिटाइज़र' के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रकार की प्लेट्स के लिए अलग-अलग होते हैं। कोटिंग घटकों और लेजर प्रकार के प्लेट सेटर्स के आधार पर, डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स को उनके अनुप्रयोग के आधार पर मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्: i. थर्मल, ii. वायलेट, और iii. सीटीसीपी/यूवी सीटीपी (कंप्यूटर-टू-कन्वेंशनल प्लेट)।

v. सभी प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, सभी आयामों में, विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र के भीतर आती हैं, सिवाय वाटरलेस सीटीपी प्लेट्स के।

vi. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों, उत्पाद के आयात तथा घरेलू और आयातित उत्पादों के अंतिम उपयोग और प्रतिस्थापना का आकलन करने के बाद उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप दिया।

vii. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पादों, उत्पाद के आयात और घरेलू और आयातित उत्पादों के अंतिम उपयोग और प्रतिस्थापन क्षमता का आकलन करने के बाद उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप दिया। यह एक निर्णायक समीक्षा है, इसलिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बनाए रखा जाना चाहिए, जैसा कि पाटनरोधी जांच में इसकी पुष्टि की गई थी।

viii. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, आयातित संबद्ध वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं हैं।

ix. इसलिए, भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के सभी मामलों में समान हैं।

x. घरेलू उद्योग का तर्क है कि उठाए गए मुद्दों को मूल जांच और समानांतर निर्णायक समीक्षा में पहले ही सुलझा लिया गया है। अपवर्जन के दावों का समर्थन करने के लिए कोई नया उत्पाद विनिर्देश या साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए मूल दायरे पर ही भरोसा किया जाना चाहिए।

xi. घरेलू उद्योग डबल लेयर - थर्मल (एलीट) और वायलेट प्लेट्स का निर्माण कर सकता है और मूल जांच के दौरान पुष्टि की गई डबल लेयर यूवी सीटीसीपी प्लेट्स का उत्पादन करने की क्षमता रखता है।

xii. घरेलू उद्योग नेगेटिव वर्किंग यूवी सीटीसीपी प्लेट्स का निर्माण करता है, जैसा कि पहले सिद्ध किया जा चुका है।

xiii. घरेलू उद्योग स्पष्ट करता है कि वह वायलेट केम-फ्री प्लेट्स का उत्पादन करता है लेकिन नोट करता है कि बाजार में कोई भी उद्योग, जिसमें वह स्वयं भी शामिल है, वायलेट प्रोसेस-फ्री प्लेट्स या प्रोसेस-फ्री यूवी सीटीसीपी प्लेट्स का निर्माण नहीं करता है। घरेलू उद्योग केम-फ्री यूवी सीटीपी प्लेट्स का उत्पादन कर सकता है, हालांकि लागत काफी अधिक है, जिससे भारत में वाणिज्यिक मांग कम हो रही है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

6. विचाराधीन उत्पाद "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग प्रिंटिंग उद्योग में आंकड़ों को छवि के रूप में कागज़ पर या टिन शीट, पॉली फ़िल्म आदि जैसे गैर-शोषक सब्सट्रेट पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग करके प्रिंटिंग प्रक्रिया में, डिजिटल वर्कफ़्लो लेजर का उपयोग करके 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) तक छवि के सीधे स्थानांतरण को सक्षम बनाता है, एनालॉग वर्कफ़्लो के विपरीत जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए एक मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है।

7. डिजिटल प्लेट्स रासायनिक कोटिंग के साथ लेपित उच्च शुद्धता वाले लिथोग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बने होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स या तो सकारात्मक (गैर-उजागर क्षेत्र छवि बनाता है) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र छवि बनाता

है) कार्यशील प्लेट्स हो सकती हैं। इस श्रेणी में वे प्लेट्स शामिल हैं जिन्हें प्रसंस्करण के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है और पर्यावरण के अनुकूल वे प्लेट्स जिन्हें प्रसंस्करण के लिए किसी रसायन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न प्रकार की प्ले प्लेट्स के लिए कोटिंग फॉर्मूलेशन अलग-अलग होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स के तीन प्रकार हैं, नामत:

i. थर्मल प्लेट्स;
ii. वायलेट प्लेट्स;
iii. सीटीसीपी/यूवीसीटीपी प्लेट्स।

8. सभी प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स सभी आयामों और मोटाई में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आती हैं। हालाँकि, वाटरलेस सीटीपी प्लेट्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

9. प्राधिकारी द्वारा 1 दिसंबर, 2023 को विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन के क्षेत्र पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जांच के क्षेत्र से उत्पादों को बाहर रखने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त अनुरोधों के अनुसरण में, प्राधिकारी ने 12 जनवरी, 2024 के अपने पत्र के माध्यम से वर्तमान जांच के लिए अपनाई जाने वाली विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन पद्धति के क्षेत्र को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

क्र.सं.	पीसीएन मापदंड	कोड
1	कंप्यूटर-टू-कन्वेंशनल प्लेट (सीटीसीपी)/यूवी कंप्यूटर-टू-प्लेट (यूवी सीटीपी)	सी
2	थर्मल प्लेट्स	टी
3	वायलेट प्लेट्स	वी

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मूल जांच में, प्राधिकारी ने डबल लेयर सीटीसीपी प्लेट्स, नेगेटिव वर्किंग यूवी सीटीपी प्लेट्स, प्रोसेस-लेस प्लेट्स के अन्य प्रकार (अर्थात्, वायलेट और यूवी सीटीपी) और केम-फ्री यूवी सीटीपी प्लेट्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया था क्योंकि घरेलू उद्योग ने इन उत्पादों के लिए कोई वाणिज्यिक मांग नहीं दिखाई थी। हालाँकि, उन्हें

विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अब बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग इन उत्पादों का उत्पादन नहीं कर रहा है, और उन्हें समानांतर निर्णायक समीक्षा में भी प्राधिकारी द्वारा बाहर रखा गया था।

11. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क की समानांतर निर्णायक समीक्षा में डबल लेयर सीटीसीपी प्लेट्स, नेगेटिव वर्किंग यूवी सीटीपी प्लेट्स, प्रोसेस-लेस प्लेट्स के अन्य प्रकार (अर्थत्, वायलेट और यूवी सीटीपी) और केम-फ्री यूवी सीटीपी प्लेट्स को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर नहीं रखने का फैसला किया है। इसने पाया:

> *प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं कि ये उत्पाद घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के समान नहीं हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने मूल जांच में जांच के दायरे से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाहर रखने के मुद्दों की जांच की है, और हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध करने के लिए कोई नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि आवेदक ऐसे किसी भी उत्पाद का निर्माण नहीं करता है। इसको देखते प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए उत्पाद को बाहर करने के इन दावों की जांच करना उपयुक्त नहीं मानते हैं।*

12. हितबद्ध पक्षकार यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं कि ये उत्पाद घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों के समान नहीं हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन, और वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता भी इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं। प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद संबद्ध देशों से भारत में आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है।

13. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के प्रशुल्क मद 8442.50 के अंतर्गत आता है। विचाराधीन उत्पाद को अन्य सीमा प्रशुल्क मदों के अंतर्गत भी आयात किया जा रहा है, जिसमें 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, और 7606.9290 शामिल हैं। क्षति आकलन के उद्देश्य से सभी विभिन्न एचएस कोड के अंतर्गत किए गए विचाराधीन उत्पाद के आयातों को

ध्यान में रखा गया है। सीमा प्रशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

ग. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

14. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक, टेक्नोवा इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आवेदन में स्वीकार किया कि उन्होंने पाटनरोधी संरक्षण होने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान संबद्ध और असंबद्ध दोनों देशों से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया, लेकिन ऐसे आयातों के कारणों के बारे में नहीं बताया।

ii. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि टेक्नोवा नियम 2(ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" माने जाने के लिए अपात्र है क्योंकि यह जांच के अंतर्गत देशों से संबद्ध वस्तुओं का एक बड़ा और अभ्यस्त आयातक है। जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई, जिससे इसे घरेलू उद्योग के रूप में माना जाने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तर्क का समर्थन करने के लिए चीन जन.गण. (2017) से एल्युमिनियम फॉयल, चीन जन.गण. (2018) से फ्लैक्स यार्न, और चीन जन.गण. (2017) से ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइल्स सहित कई विगत मामलों का हवाला दिया गया है।

iii. टेक्नोवा के नियमित आयात इस दावे का खंडन करते हैं कि ऐसे आयात अस्थायी हैं, जैसा कि पिछली जांच में उल्लेख किया गया था जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मुख्य ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अस्थायी आयात की अनुमति दी थी। हालांकि, वर्तमान आयात आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि कि टेक्नोवा ने न केवल जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान बल्कि जांच की अवधि से पहले और बाद में भी निरंतर रूप से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है। यह पैटर्न नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की पात्रता को चुनौती देता है।

iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह प्रावधान है कि संबद्ध वस्तुओं के नियमित आयातकों को "घरेलू उद्योग" नहीं माना जा सकता है। प्रतिवादी

अनुरोध करते हैं कि टेक्नोवा का आयात वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच की अवधि के दौरान 354 सूचकांक अंक हो गया, जो इसे नियम 2(ख) के अंतर्गत अयोग्य ठहराता है।

v. व्यापार उपचार जांच के लिए प्रचलित प्रथाओं के मैनुअल (पैरा 4.9.20 (v)) में याचिकाकर्ताओं द्वारा आयात के मुद्दे पर महानिदेशक से एक विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने इन आयातों के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बताई हैं, और ऐसे आयातों के कारणों को गोपनीय रखा गया है।

vi. प्राधिकारी को नियम 2(ख) के अनुपालन का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि आवेदक द्वारा किए जाने वाले नियमित आयात, भले ही अस्थायी होने का दावा किया गया हो, घरेलू उद्योग के रूप में उसकी स्थिति के विपरीत हैं। आवेदक द्वारा संबद्ध तथा असंबद्ध दोनों देशों से किए गए पर्याप्त आयात, उसकी पात्रता के बारे में प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि इसी प्रकार के उत्पादकों को तुर्की तथा यूएसए से सोडा ऐश जैसे पूर्ववर्ती मामलों में अयोग्य ठहराया जा चुका है।

vii. टेक्नोवा द्वारा किए जाने वाले लगातार आयात, जैसा कि दावा किया गया है, नगण्य नहीं हैं, तथा साक्ष्य दर्शाते हैं कि ये आयात नियमित थे, जो क्षति अवधि, जांच अवधि तथा जांच की अवधि के पश्चात हुए थे। आवेदक द्वारा किए गए आयात न तो अस्थायी थे, न ही शुल्क-मुक्त योजना के अंतर्गत किए गए थे।

viii. मूल जांच के दौरान, घरेलू उद्योग के आयात कुल आयातों के 7% थे, लेकिन प्राधिकारी ने इन्हें अस्थायी माना। घरेलू उद्योग आयातों विशेषकर चीन और जापान जैसे संबद्ध देशों से आयातों पर निर्भर बने हुए हैं।

ix. टेक्नोवा ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध और असंबद्ध दोनों देशों से नियमित रूप से वस्तुओं का आयात किया है, जो दर्शाता है कि घरेलू उत्पादन और बिक्री में किसी भी गिरावट को केवल संबद्ध वस्तुओं के कारण नहीं माना जा सकता है।

x. घरेलू उद्योग सभी ग्राहकों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से समर्थ नहीं है, पर्याप्त तकनीक का अभाव है, और मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, जो इसके आत्मनिर्भर उत्पादक होने के दावों का खंडन करता है।

xi. हितबद्ध पक्षकारों ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने 2020-21 और 2021-22 के आयात आंकड़ों के संबंध में झूठे दावे किए हैं। फलस्वरूप, उन्होंने एक डेटासेट प्रस्तुत किया है जो दर्शाता है कि 2019-20 और 2020-22 के दौरान, घरेलू उद्योग ने कुल 115,873 वर्ग मीटर का आयात किया।

xii. याचिकाकर्ता द्वारा आयात की गई मात्रा अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए आयात करने के लिए बहुत अधिक है।

ख. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

15. घरेलू उद्योग के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. कुल घरेलू उत्पादन में से, घरेलू उत्पादक का उत्पादन हिस्सा 96% है। इसको देखते हुए, घरेलू उत्पादक वर्तमान आवेदन के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग होने के लिए अपेक्षित सीमा को पूरा करता है।

ii. "घरेलू उद्योग" के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, घरेलू उत्पादक के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन पात्र घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। घरेलू उत्पादक का उत्पादन सीमा की आवश्यकता को पूरा करता है।

iii. जबकि घरेलू उत्पादक को जांच की अवधि के दौरान कुछ आयात करने के लिए बाध्य किया गया था, ये आयात घरेलू उत्पादक के कुल उत्पादन, भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयात और विचाराधीन उत्पाद के संबद्ध आयात की तुलना में नगण्य हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने अपने दो संयंत्रों में से प्रत्येक के अलग-अलग नियमित रखरखाव बंद होने के कारण संबद्ध और असंबद्ध दोनों देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

v. यह नोट किया जाए कि दोनों में से कोई भी संयंत्र एक ही समय में बंद नहीं हुआ थ। परिणामस्वरूप, मौजूदा ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, घरेलू उद्योग ने अस्थायी समाधान के रूप में विचाराधीन उत्पाद का आयात किया।

vi. इसके अलावा, कोविड-19 के बाद, विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि देखी गई, जो इसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री से स्पष्ट

है। अपने मौजूदा ग्राहकों की मांग में अचानक वृद्धि को पूरा करने के लिए, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क सहित लागू शुल्कों का भुगतान करते हुए विचाराधीन उत्पाद की सीमित मात्रा का आयात किया।

vii. घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि उपरोक्त कारणों से संबद्ध देशों से आयात उसके उत्पादन का केवल 1.8% और जांच की अवधि में संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग का 1.2% है।

viii. घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है और अपने मौजूदा ग्राहकों की सेवा करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में विचाराधीन उत्पाद का आयात करने के लिए बाध्य था। इससे घरेलू उद्योग के व्यवसाय की वास्तविक विशेषता, अर्थात् विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण और अपने ग्राहकों को इसकी आपूर्ति, में कोई बदलाव नहीं होता है।

ix. असंबद्ध देशों (अर्थात् यूरोपीय संघ) से आयात के संबंध में, आयात परीक्षण और बाजार बीजारोपण के उद्देश्य से अपने पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकी साझेदार से किया गया है।

x. चूंकि घरेलू उत्पादक द्वारा संबद्ध देशों से आयात जांच की अवधि के उसके कुल उत्पादन का केवल 1.8%, कुल मांग का 1.2% और संबद्ध देशों से आयात का 3.5% है, ऐसे कमतर आयात से आवेदक को कोई अनुचित लाभ नहीं मिल सकता था।

xi. भारतीय न्यायालयों ने माना है कि जहां उत्पादक का मुख्य व्यवसाय आयात नहीं है, उसे घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। एक उत्पादक जो अपने कुल उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा आयात करता है, और वह भी उत्पादन में व्यवधान के दौरान, उसे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत आयातक नहीं माना जाना चाहिए।

xii. याचिकाकर्ता भारत में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में संबद्ध वस्तुओं का विनिर्माण करता है और एक निर्माता की सभी आवश्यक विशेषताएं रखता है। याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग 67% है।

xiii. याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल घरेलू उत्पादन का 96% हिस्सा है।

xiv. याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है, जिससे भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाया जा सके और घरेलू ग्राहकों की सेवा करने के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करके उसे जारी रखा जा सके।

xv. घरेलू उद्योग का तर्क है कि "अस्थायी" आयात को "गैर-आवर्ती" के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कभी-कभार होने वाले छोटे आयात यह संकेत नहीं देते हैं कि उद्योग एक आदतन आयातक है या व्यापारिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है। ये आयात अल्पकालिक जरूरतों से प्रेरित हैं, और प्राथमिक ध्यान घरेलू उत्पादन पर रहता है।

xvi. प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांचों में न्यूनतम आयात वाले घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग की स्थिति के लिए पात्र माना है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक अभ्रक-आधारित पिगमेंट, फ्लैक्स यार्न और कैप्रोलेक्टम मामले शामिल हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. नियमावली के नियम 2(ख) में निम्नलिखित प्रावधान हैः

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदन मेसर्स टेकनोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किया गया है। टेकनोवा के अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं का केवल एक अन्य उत्पादक है, नामत: एचएल प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसने उक्त जांच में समर्थन पत्र प्रस्तुत किया है।

18. आवेदक ने अनुरोध किया कि वह संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के किसी भी निर्यातक या संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातकों से संबंधित नहीं है।

हालांकि, आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों में से एक से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में यह प्रावधान है कि घरेलू उत्पादक जो निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या जो स्वयं कथित रूप से पाटित वस्तु के आयातक हैं, उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। नियम 2(ख) के अंतर्गत "हो सकता है" शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि निर्यातकों या आयातकों से संबंधित उत्पादकों के साथ-साथ आयात करने वाले उत्पादकों को भी घरेलू उद्योग का हिस्सा होने से स्वतः बाहर नहीं रखा जाता है। प्राधिकारी के पास इस संबंध में सभी उचित विचार करने के पश्चात मामला-दर-मामला आधार पर ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल करने या बाहर रखने का निर्धारण करने का विवेकाधिकार है। विशेष रूप से, प्राधिकारी द्वारा यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का आयात इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया है जो आवेदक को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र बनाएगा।

20. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया है, जिसमें कहा गया है कि आवेदक द्वारा किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात को 'अस्थायी' नहीं कहा जा सकता है, यह देखते हुए कि आवेदक ने मूल जांच की अवधि के दौरान भी संबद्ध वस्तुओं का आयात किया था। उत्तर में घरेलू उद्योग (डीआई) का तर्क है कि 'अस्थायी' शब्द को 'गैर-आवर्ती' के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादकों द्वारा अप्रत्याशित मांग में उछाल या उत्पादन में व्यवधान जैसी विशिष्ट और अल्पकालिक जरूरतों से प्रेरित होकर किए गए कभी-कभार आयात से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आयात 'आदतन' हैं या 'अस्थायी' नहीं हैं, जब तक कि ऐसे आयात घरेलू निर्माता के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका के लिए संगत हैं और व्यापार की ओर इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव का संकेत नहीं देते हैं।

21. इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा किए गए आयातों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
आवेदक द्वारा संबद्ध देशों से किए गए आयात	एसक्यू एस	***	***	***	***
उत्पादन मात्रा	एसक्यू एस	***	***	***	***
कुल आयात	एसक्यू एस	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
कुल मांग	एसक्यू एस	***	***	***	***
निम्नलिखित के संबंध में आयात:					
- घरेलू उत्पादन	%	0-1%	NIL	NIL	1-2%
- मांग	%	0-1%	NIL	NIL	1-2%
- संबद्ध आयात	%	1-2%	NIL	NIL	3-4%

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के आयात की मात्रा कुल आयात, कुल घरेलू उत्पादन या देश की कुल मांग की तुलना में नगण्य है। कुल मांग, इसकी घरेलू बिक्री और उत्पादन के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा 1-2% के दायरे में है। डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से इसका सत्यापन किया गया है।

23. यह नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश में कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 96% है। इसलिए, आवेदक द्वारा किए गए आयात घरेलू उत्पादक के रूप में इसकी भूमिका के अनुरूप हैं और व्यापार या आदतन आयात की ओर बदलाव का संकेत नहीं देते हैं।

24. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक, अर्थात, टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड, नियमावली के नियम 2(ख) की आवश्यकता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से एक पात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है।

25. अभिलेख में उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि में आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 96% है और यह एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में स्थिति के मानदंड को पूरा करता है।

घ. <u>गोपनीयता</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. आवेदक ने ट्रेड नोटिस संख्या 10/2018 दिनांक 7.09.2018 के विशिष्ट प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।

ख. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

27. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग का तर्क है कि हितबद्ध पक्षकारों ने उनके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है, क्योंकि उन्होंने सभी विवरणों को गोपनीय के रूप में चिह्नित किया है, जिससे घरेलू उद्योग के लिए उनके दावों का आकलन करना असंभव हो गया है।

ii. प्रस्तुत किए गए उत्तर या तो पूरी तरह से गोपनीय थे या उनमें सार्थक उत्तरों का अभाव था, जो व्यापार उपाय जांच में पारदर्शिता मानकों का उल्लंघन था। ईसी - फास्टनर्स (चीन) में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने अन्य पक्षों के दावों को समझने और उनका उत्तर देने के लिए सुनिश्चित करने के लिए गगोपनीय सार की आवश्यकता पर बल दिया।

iii. प्राधिकारी की विगत कार्य-पद्धति, जैसे कि फाइबरबोर्ड मामले में, अधूरे या अपर्याप्त अनुरोधों को अस्वीकार करने का समर्थन करता है। घरेलू उद्योग का दावा है कि उत्तरप्रतिवादियों की सार्थक अगोपनीय सार और कार्यक्रम-वार विवरण प्रदान करने में विफलता जांच में बाधा डालती है और उन पक्षों के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन से इनकार करने की मांग करती है जिन्होंने प्रकटन आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन नहीं किया है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में पाटनरोधी नियमावली,1995 के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

29. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम 7 निम्नानुसार पढ़ा जाए:

> *"(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*
>
> *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*
> *(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"*

30. प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी इच्छुक पक्षों को विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया।

31. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया था। उक्त निर्णय के पैरा 3 में यह पुष्टि की गई थी कि:

"3. ... नियम 7 के अंतर्गत गोपनीयता ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वतः ही मान लिया जाना चाहिए। बेशक, ऐसे मामलों में गोपनीयता की आवश्यकता होती है क्योंकि अन्यथा व्यापार प्रतिस्पर्धी गोपनीय सूचना प्राप्त कर लेंगे जो उन्हें अन्यथा नहीं मिल सकती। लेकिन क्या दी गई सूचना को गोपनीय रखना आवश्यक है, इस पर मामले-दर-मामला आधार पर विचार किया जाना है। यह निर्दिष्ट प्राधिकारी को तय करना है कि क्या किसी विशेष सामग्री को गोपनीय रखना आवश्यक है या नहीं।"

32. तदनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच की, ताकि सी.वी.डी. नियमों के नियम 8 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता का पता लगाया जा सके। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया, जहाँ भी आवश्यक था और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है। जहाँ भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर गोपनीय संस्करण प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

33. कच्चे माल के नाम, उत्पादन प्रक्रिया, घरेलू उद्योग द्वारा आयात तथा एनआईपी दायरे पर गोपनीयता के दावों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा याचिका सहित अपने अनुरोध में कच्चे माल का नाम, दायरे में आयात तथा दायरे में क्षति मार्जिन के बारे में बताया गया है। उत्पादन प्रक्रिया पर गोपनीयता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि ऐसी सूचना गोपनीय प्रकृति की होती है तथा ऐसी सूचना के प्रकटन से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ङ. <u>विविध</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

34. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं:

i. टेक्नोवा इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 से लगातार विभिन्न देशों से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पर पाटनरोधी शुल्क और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क सहित व्यापार उपाय सुरक्षा की मांग की है और उसे प्राप्त भी किया है। शुल्क को बार-बार बढ़ाया गया है, हाल ही में चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम के विरुद्ध सितंबर 2023 में चीन और ताइवान के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू की गई है।

ii. हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध है कि याचिकाकर्ता, टेक्नोवा, प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध ढाल के रूप में व्यापार उपायों का उपयोग करते हुए, जांच के लिए प्रतिकूल बाजार वृत्तियों की अवधि को चुनता है।

iii. मूल जांच में, विभिन्न एचएस कोड (3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, और 7606.9290) के अन्तर्गत आयातों पर क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया था, लेकिन वर्तमान जांच में, याचिकाकर्ता ने केवल प्रशुल्क मद 8442.50 पर ध्यान केंद्रित किया है, जो संभावित रूप से अन्य संगत एचएस कोड को छोड़कर क्षति विश्लेषण से बच रहा है। यह चयनात्मक दृष्टिकोण वास्तविक आयात मात्रा को विपठित कर सकता है और क्षति का गलत आकलन प्रदान कर सकता है, जिससे त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वह इस चयनात्मक रिपोर्टिंग की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षति का अाकलन संगत आयात आंकड़ों के पूर्ण कार्य-क्षेत्र को प्रतिबिंबित करता है।

iv. एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्कों का एक साथ अधिरोपण क्षति मार्जिन की सीमा तक ही सीमित होना चाहिए।

v. प्राधिकरण ने हाल ही में संपन्न एंटी-डंपिंग जांच में केसीजीसीसीएल के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन के साथ एक व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया है। पिछली सभी जांचों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई थी। चूंकि वर्तमान सीवीडी जांच की पीओआई हाल ही में संपन्न एंटी-डंपिंग जांच के समान है, इसलिए प्राधिकरण को केसीजीसीसीएल के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन के साथ व्यक्तिगत मार्जिन का निष्कर्ष निकालना चाहिए, जिससे शुल्क की दर शून्य हो जाएगी।

vi. यह प्रस्तुत किया गया है कि इस जांच में कई निर्यात सब्सिडी कार्यक्रम, जिसमें कार्यक्रम 1 भी शामिल है, को चीन पीआर, जापान, कोरिया आरपी, वियतनाम और ताइवान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (डीओपीपी) के आयात के संबंध में डंपिंग विरोधी शुल्क के आयात के संबंध में सूर्यास्त समीक्षा जांच के तहत लगाए गए डंपिंग विरोधी शुल्क की गणना के लिए पहले से ही विचार किया गया है और प्रतिपूरक शुल्क लगाने से डंपिंग और निर्यात सब्सिडी की एक ही स्थिति के लिए दोहरा उपाय हो जाता है।

vii. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता इस जांच की शुरुआत के दौरान उल्लिखित कई सब्सिडी कार्यक्रमों और इस जांच में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित अतिरिक्त कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त और सटीक सबूत देने

में विफल रहा है। याचिकाकर्ता को सब्सिडी के नामों की एक सूची से अधिक प्रदान करना चाहिए था जैसा कि कई कार्यक्रमों के संबंध में किया गया है।

ख. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

i. घरेलू उद्योग का तर्क है कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच शुरू करने की याचिका एससीएम समझौते के अनुच्छेद 11.2 और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली के नियम 6 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

ii. याचिका में सब्सिडी, क्षति और कारणात्मक संबंध के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें सब्सिडी कार्यक्रमों, कार्यान्वयन कानून, वित्तीय योगदान, लाभ और विशिष्टता का विवरण दिया गया है। साक्ष्य में सरकारी अधिसूचनाएं, डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाएं और प्रशासनिक रिपोर्टें शामिल हैं जो सब्सिडी के होने की पुष्टि करता है।

iii. घरेलू उद्योग इन दावों का खंडन करता है कि याचिका में सब्सिडी गणना का अभाव है, जिसमें कहा गया है कि गोपनीय आंकड़ों के कारण इस तरह की विस्तृत गणनाएं पूर्व-आरंभिक चरण में अनुचित हैं। सब्सिडी की सीमा की जांच करने की जिम्मेदारी प्राधिकारी की है, और घरेलू उद्योग ने विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के विपरीत पूर्ण सहयोग किया है।

iv. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया कि घरेलू उद्योग ने आयात आंकड़ों को तोड़-मरोड़कर पेशन करने के लिए चयनित रूप से प्रशुल्क मद 8442.50.20 पर ध्यान केंद्रित किया। घरेलू उद्योग ने उत्तर दिया कि प्राधिकारी इन आंकड़ों को सत्यापित कर सकते हैं और जांच के लिए डीजी सिस्टम या डीजीसीआईएस आंकड़ों पर भरोसा कर सकते हैं।

v. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क दोनों लगाने से दोहरे उपचार के दावे को खारिज करता है। उनका तर्क है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क निर्यात सब्सिडी के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यह मूल जांच के दौरान पूरी तरह से पाटन के आधार पर निर्धारित किया गया था और सब्सिडी के प्रभावों पर ध्यान नहीं देता है। डीएस379 में अपीलीय निकाय ने स्पष्ट किया कि दोहरे उपचार केवल तभी हो सकते हैं जब सब्सिडी निर्यात कीमतों को कम करती है, लेकिन इसके लिए तथ्य-विशिष्ट विश्लेषण की आवश्यकता होती है, जिसे हितबद्ध पक्षकार प्रदान करने में विफल रहे हैं। उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट नहीं किया कि सब्सिडी निर्यात सब्सिडी है या

यह नहीं दिखाया कि ये सब्सिडी निर्यात कीमतों को कैसे प्रभावित करती हैं। इस प्रकार, दोहरे उपचार का दावा निराधार है, और दोनों शुल्कों को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून और एससीएम करार के अनुरूप है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

35. प्राधिकारी ने नोट किया कि कुछ हितबद्ध पक्षों ने तर्क दिया है कि वर्तमान विषयगत जांच गलत तरीके से शुरू की गई है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में सीवीडी नियमों के तहत अपेक्षित पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं। प्राधिकारी ने नोट किया कि आवेदक ने विधिवत प्रमाणित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी। वर्तमान जांच घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों/सूचना के आधार पर और प्राधिकारी की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के बाद शुरू की गई थी कि सब्सिडी, क्षति और कारण संबंध के अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य हैं। आवेदन में जांच शुरू करने के उद्देश्य के लिए सभी प्रासंगिक सूचनाएं शामिल थीं। संयुक्त राज्य अमेरिका से अनाज उन्मुख फ्लैट-रोल्ड इलेक्ट्रिकल स्टील पर चीन-प्रतिपूरक और डंपिंग रोधी शुल्क के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट (डीएस 414) का संदर्भ दिया गया है जिसमें पैनल ने कहा कि हालांकि सब्सिडी, क्षति और कारण संबंध के अस्तित्व और प्रकृति का निश्चित प्रमाण अनुच्छेद 11.3 के प्रयोजनों के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी आवेदन में इन तत्वों के अस्तित्व को दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य आवश्यक हैं। दरअसल, जांच को उचित ठहराए जाने से पहले आवेदन में दिए जाने वाले साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार करते हुए, WTO ने नोट किया कि ASCM के अनुच्छेद 11.2 के अनुसार, जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए 'सब्सिडी के अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य' की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि साक्ष्य को यह संकेत देना चाहिए कि सब्सिडी वास्तव में मौजूद है। इस मामले में, आवेदक ने कार्यक्रम की प्रकृति, कार्यक्रम को प्रशासित करने वाले प्राधिकरण, कानूनी आधार, पात्रता मानदंड, वित्तीय योगदान, विशिष्टता, लाभ, लाभ की प्रकृति, उत्पादकों से जुड़ाव (जहां भी संभव हो) और ऐसे मामलों के रूप में साक्ष्य प्रदान किए, जहां उनके आवेदन में योजना को प्रतिसंतुलन योग्य माना गया था। प्राधिकरण आवेदक द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य को जांच शुरू करने को उचित ठहराने के लिए 'सब्सिडी के अस्तित्व के पर्याप्त साक्ष्य' के रूप में मानता है।

36. साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच और आरंभ को उचित ठहराने के लिए साक्ष्य की पर्याप्तता के संबंध में प्राधिकरण की संतुष्टि के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि आवेदक ने जांच अधिकारियों के निर्णयों के रूप में साक्ष्य प्रदान किए

जहां कथित कार्यक्रम प्रतिपूरक थे। इसके अलावा, आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में अन्य प्रासंगिक साक्ष्य प्रदान किए। प्राधिकरण ने इस संबंध में नोट किया कि *"पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उत्पन्न कुछ कार्बनिक लेपित स्टील उत्पादों के आयात पर प्रतिपूरक शुल्क"* के मामले में ईसी ने कुछ योजनाओं के बारे में अंतिम निर्धारण केवल सर्कुलर वेल्डेड कार्बन क्वालिटी स्टील लाइन पाइप के मामले में यूएस निर्णय ज्ञापन द्वारा किए गए निर्धारण पर आधारित किया। इन परिस्थितियों में, प्राधिकरण का मानना है कि आरंभ के चरण में, यह केवल साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता और प्राधिकरण की प्रथम दृष्टया संतुष्टि का प्रश्न है। प्राधिकरण का मानना है कि यह तर्क देना उचित नहीं है कि आवेदन में 32 कार्यक्रमों के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। प्राधिकरण ने मेक्सिको से पोर्टलैंड सीमेंट के संबंध में *ग्वाटेमाला एंटी-डंपिंग जांच (डब्ल्यूटी/डीएस60/आर) के मामले में डब्ल्यूटीओ* के निर्णय को भी नोट किया है, जिसमें यह माना गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राधिकरण आवेदक द्वारा अपनी याचिका में लाए गए साक्ष्य तक ही सीमित रहे। प्राधिकरण याचिका में उपलब्ध अन्य साक्ष्यों पर विचार कर सकता है, भले ही आवेदक द्वारा उन पर भरोसा न किया गया हो।

37. प्राधिकारी मूल जांच में विचाराधीन के दायरे में शामिल कुछ एचएस प्रशुल्क मदों को शामिल नहीं करने के संबंध में हितबद्ध पक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं को नोट करते हैं। इस संबंध में, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देशों से किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा निर्धारित करने के लिए डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों की जांच की है और उन पर भरोसा किया है। डीजी प्रणाली से आयात आंकड़ों की जांच उन सभी एचएस प्रशुल्क मदों के लिए की गई है जिन्हें मूल जांच में शामिल किया गया था और जिनकी सूचना आवेदक द्वारा याचिका में दी गई है। आयात आंकड़ों को उत्पाद विवरण तथा संगत एचएस प्रशुल्क मदों के आधार पर विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद में अलग अलग रखा गया है।

38. प्रतिपूरक शुल्कों के अधिरोपण को क्षति मार्जिन की सीमा तक सीमित करने के इच्छुक पक्षों के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9बी(1)(ए) के अनुसार, कोई भी वस्तु डंपिंग या निर्यात सब्सिडी की समान स्थिति की भरपाई के लिए प्रतिपूरक शुल्क और प्रतिपाटन शुल्क दोनों के अधीन नहीं होगी। उपर्युक्त प्रावधान पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि विचाराधीन उत्पाद प्रतिपाटन और निर्यात सब्सिडी दोनों के अधीन नहीं होना चाहिए। यह भी नोट किया जाता है कि चूंकि प्रतिपाटन और प्रतिपूरक जांच की जांच अवधि एक ही है, इसलिए प्राधिकारी ने इस तथ्य का पूरा ध्यान रखा है कि डंपिंग

मार्जिन और सब्सिडी मार्जिन के कारण कुल शुल्क जांच अवधि के लिए गणना की गई क्षति मार्जिन के स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए।

39. प्राधिकरण ने नोट किया कि इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि कोडक और लकी के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित किए जाने चाहिए, और कोडक को अपना नकारात्मक क्षति मार्जिन बनाए रखना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि चीन पीआर सहित विभिन्न देशों से डीओपीपी के आयात पर लगाए गए एंटी-डंपिंग शुल्कों के लिए हाल ही में संपन्न सनसेट समीक्षा में भी इस दृष्टिकोण का पालन किया गया है, जिनकी पीओआई समान थी। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि उसने मूल एंटी-डंपिंग जांच और हाल ही में संपन्न सनसेट समीक्षा में कोडक की शेयरधारिता के स्वामित्व में परिवर्तन के मुद्दे पर विचार किया था। प्राधिकरण ने स्वीकार किया है कि लकी ने मूल एंटी-डंपिंग जांच की पीओआई के बाद कोडक चाइना का अधिग्रहण किया और नोट किया कि ***"विलयित इकाई के निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार का मूल्यांकन संबंधित नियमों/प्रक्रिया के अनुसार, जब भी कोई इच्छुक पक्ष द्वारा समीक्षा जांच दायर की जाती है, उसके तहत किया जा सकता है।"*** हाल ही में संपन्न सनसेट समीक्षा में, प्राधिकरण ने जांच अवधि में दोनों संस्थाओं के मूल्य व्यवहार की तुलना की, जो कि विषयगत जांच अवधि के समान थी, और पाया कि लकी और कोडक चाइना के लिए मूल्य व्यवहार मूल एंटी-डंपिंग जांच के समान ही है। उस आधार पर, उसने कोडक चाइना और लकी पर अलग-अलग एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना उचित समझा। इन विशिष्ट तथ्यों के आलोक में, प्राधिकरण ने कोडक चाइना और लकी पर भी विषयगत जांच में अलग-अलग प्रतिपूरक शुल्क लगाना उचित समझा। प्राधिकरण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह विषयगत जांच के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर आधारित है, जिसमें प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और तर्क शामिल हैं।

च. <u>सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण</u>

क. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

40. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. घरेलू उद्योग उन दावों का खंडन करता है कि प्राधिकरण जांच शुरू करने से पहले संबंधित देश की सरकार के साथ परामर्श के संबंध में एससीएम समझौते के अनुच्छेद 13.1 का अनुपालन करने में विफल रहा है। प्राधिकरण ने अनुच्छेद 13.1 के अनुसार संबंधित सरकार के साथ विधिवत

परामर्श किया, जो जांच शुरू करने से पहले एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। एससीएम समझौता केवल पूर्व-आरंभ चरण में सब्सिडी, क्षति और कारण संबंध के पर्याप्त सबूत अनिवार्य करता है, और घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में ऐसे सबूत प्रदान किए हैं।

ii. जांच के दौरान प्रतिवादियों के जवाबों और अमेरिकी वाणिज्य विभाग द्वारा प्रारंभिक निर्धारण के आधार पर अतिरिक्त सब्सिडी योजनाओं की पहचान के लिए नए परामर्श की आवश्यकता नहीं है। जांच की गतिशील प्रकृति अलग-अलग परामर्श की आवश्यकता के बिना नए आरोपों की जांच करने की अनुमति देती है।

iii. पिछले मामले और वैश्विक प्रथाएं पुष्टि करती हैं कि जांच के दौरान खोजे गए हर नए तथ्य या सब्सिडी के लिए परामर्श की आवश्यकता नहीं है।

iv. इसके अलावा, अनुच्छेद 13.2 के तहत, सरकारों को जांच के दौरान परामर्श करने का उचित अवसर मिलता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया।

v. घरेलू उद्योग ने चीन सरकार ("जीओसी") और ताइवान के राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा क्रमशः चीन और ताइवान में डिजिटल प्लेट उद्योग को प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का दस्तावेजीकरण करने के लिए व्यापक शोध किया है।

vi. एएससीएम के अंतर्गत ऐसा करने के अपने दायित्वों के बावजूद, जीओसी अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी की प्रकृति और सीमा का खुलासा करने में आगे नहीं आया है।

vii. जीओसी चीन की आर्थिक वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक औद्योगिक नीतियों को बनाए रखता है, जिन्हें सब्सिडी कार्यक्रमों के माध्यम से लागू किया जाता है जो विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निर्यात सहित चीनी की अर्थव्यवस्था के हर पहलू को प्रभावित करते हैं।

viii. विचाराधीन उत्पाद एल्युमीनियम मूल्य श्रृंखला का एक डाउनस्ट्रीम उत्पाद है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के सभी निर्माता एल्युमीनियम मूल्य श्रृंखला को प्रदान की गई सब्सिडी के लाभार्थी भी हैं।

ix. घरेलू उद्योग ने ओईसीडी रिपोर्ट का हवाला दिया, जो चीन के एल्युमीनियम क्षेत्र की अभेद्य प्रकृति पर प्रकाश डालती है। इनमें से कुछ सब्सिडी में सस्ती कीमतों पर इनपुट और उपयोगिताओं, कर रियायतें, कम ब्याज वाले ऋण और वित्त पोषण, और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं।

x. चीन का प्रशुल्क ढांचा एल्युमीनियम मूल्य श्रृंखला में डाउनस्ट्रीम गतिविधियों का भी पक्षधर है। इसने प्राथमिक एल्युमीनियम निर्यात के लिए उच्च निर्यात शुल्क और मूल्य वर्धित कर ("वैट") की अपूर्ण छूट जैसे उपकरण अपनाए हैं।

xi. चीन, प्राथमिक एल्युमीनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के नाते, दुनिया के लिए कमोडिटी को कम सुलभ बना दिया है, जबकि अपने डाउनस्ट्रीम उद्योग को प्राथमिक एल्युमीनियम की सस्ती आपूर्ति प्रदान कर रहा है।

xii. चीनी के अधिकारियों ने वरीयता प्राप्त ऋण, कर प्रोत्साहन और सब्सिडी वाली ऊर्जा कीमतों जैसी नीतियों को भी लागू किया है, जिसने एल्युमीनियम निर्माताओं और विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत को कृत्रिम रूप से कम कर दिया है। इससे वैश्विक बाजार में एल्युमीनियम की अधिक आपूर्ति और अधिशेष हो गया है, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा है और अन्य देशों के उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

xiii. इन बाजार विकृतियों का वैश्विक एल्युमीनियम उद्योग और विचाराधीन उत्पाद जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए बहुत अधिक प्रभाव हैं।

xiv. घरेलू उद्योग ने आगे प्रथम दृष्टया यह प्रदर्शित किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को ताइवान के प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता, सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 और सी.वी.डी. नियमावली के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडीकरण है।

xv. प्रतिसंतुलन शुल्क नियमों का नियम 7(8) प्राधिकरण को 'उपलब्ध तथ्यों' पर भरोसा करने की अनुमति देता है, जब निर्यातक जांच में सहयोग करने में विफल रहते हैं, जैसे सूचना रोकना या प्रक्रिया में बाधा डालना। इसमें घरेलू उद्योग की याचिका, पिछले निर्धारणों या अन्य विश्वसनीय स्रोतों से डेटा का उपयोग करना शामिल हो सकता है।

xvi. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि चीन पीआर 32 अनुदानों और 13 कर कार्यक्रमों सहित कई प्रकार की प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी प्रदान करता है। सहकारी उत्पादकों के लिए, सब्सिडी मार्जिन की गणना अनुदान राशि के आधार पर की जाती है, जिसमें आवर्ती अनुदान को जांच अवधि के दौरान उत्पादन मात्रा से विभाजित किया जाता है। गैर-आवर्ती अनुदान औसत उपयोगी जीवन (एयूएल) अवधि में आवंटित किए जाते हैं, और यदि अनुदान राशि बिक्री के 1% से कम है, तो इसे प्राप्ति के वर्ष के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। चयनात्मक असहयोग के मामले में,

प्राधिकारी जांच के सहयोगात्मक भागों के लिए उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपलब्ध तथ्य असहयोगी क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

xvii. घरेलू उद्योग पिछले जांचों से प्राप्त कई सब्सिडी मार्जिन पर प्रकाश डालता है, जैसे विदेशी व्यापार विकास निधि, नीति ऋण, अनुसंधान एवं विकास के लिए आयकर कटौती और विभिन्न अन्य के लिए सब्सिडी। ये मार्जिन असहयोगी उत्पादकों या चुनिंदा असहयोगी उत्पादकों के लिए विचार किए जाते हैं, जहां उत्पादकों ने पर्याप्त जानकारी नहीं दी। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है, जिसमें भारत या विदेश में पहले की प्रतिपूरक शुल्क जांच में लिए गए निर्णय शामिल हैं।

xviii. ताइवान के संबंध में, चूंकि ताइवान के किसी भी उत्पादक ने जांच में भाग नहीं लिया, इसलिए सभी ताइवानी निर्यातकों को असहयोगी माना जाता है। घरेलू उद्योग पिछले जांचों और डब्ल्यूटीओ अधिसूचनाओं के आधार पर आयकर क्रेडिट, शुल्क और कर छूट, अनुदान और वित्तीय सहायता सहित विभिन्न ताइवानी सब्सिडी कार्यक्रमों के लिए विस्तृत सब्सिडी मार्जिन प्रदान करता है। ये मार्जिन उपलब्ध जानकारी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि ताइवानी उत्पादक जांच में सहयोग करने में विफल रहे।

xix. घरेलू उद्योग ने इच्छुक पक्षों की ओर से अधूरे या अपर्याप्त प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं के मुद्दे की ओर भी ध्यान दिलाया है। ये पक्ष कार्यक्रम-वार प्रतिक्रियाएँ या गैर-गोपनीय सारांश प्रदान करने में विफल रहे, जो जाँच के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राधिकरण की पिछली प्रथा अधूरे उत्तरों को अस्वीकार करने का समर्थन करती है, जहाँ उचित गैर-गोपनीय सारांश प्रदान नहीं किए जाते हैं, जैसा कि फाइबरबोर्ड्स मामले में उदाहरण दिया गया है, जहाँ प्राधिकरण ने अधूरे प्रस्तुतियों के कारण एस. किजचाई एंटरप्राइज के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन से इनकार कर दिया था। घरेलू उद्योग इस बात पर जोर देता है कि पर्याप्त प्रकटीकरण की कमी सब्सिडी के उचित मूल्यांकन और सटीक सब्सिडी मार्जिन की गणना को रोकती है, इसलिए प्राधिकरण से अधूरे उत्तरों को अस्वीकार करने और सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करने का आग्रह किया जाता है।

xx. फुजीफिल्म यह दावा करता है कि उसे केवल तीन विशिष्ट योजनाओं से लाभ मिला, जिसके बारे में उसका तर्क है कि उन्हें समाप्त कर दिया गया, जिसका घरेलू उद्योग द्वारा खंडन किया गया है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि फुजीफिल्म ने केवल उन तीन योजनाओं से अधिक का लाभ उठाया, अमेरिकी वाणिज्य विभाग (यूएसडीओसी) ने पुष्टि की है कि फुजीफिल्म

को अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों से लाभ मिला, जिसमें अनुदान, नीतिगत ऋण और एल्यूमीनियम के प्रावधान से संबंधित लाभ तथा बाजार से कम दरों पर बिजली शामिल हैं।

xxi. सब्सिडी कार्यक्रमों पर जीओसी का अनुरोध भी चीन के उत्पादकों के उत्तरों के विपरीत है, जो असहयोग को और भी स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, जीओसी ने दावा किया कि विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान और निर्यात सहायता अनुदान जैसे कुछ कार्यक्रम उत्पादकों पर लागू नहीं होते, लेकिन कोडक, लकी और फुजीफिल्म ने इन कार्यक्रमों को इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के रूप में स्वीकार किया। जीओसी द्वारा पर्याप्त जानकारी प्रदान करने या आवश्यक परिशिष्टों, विशेष रूप से निर्यात सहायता और विदेशी व्यापार विकास कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करना, जांच प्रक्रिया में बाधा डालता है और सब्सिडी निर्धारित करने के लिए उपलब्ध तथ्यों पर निर्भरता को उचित ठहराता है।

ख. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

41. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि जिन कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया गया है, उनका प्राधिकरण द्वारा विषयगत जांच में प्रतिसंतुलन नहीं किया जाना चाहिए।

ii. प्राधिकरण को जांच के इतने विलंबित चरण में घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

iii. यदि प्राधिकरण ने अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच करने का निर्णय लिया था, तो उसे निर्यातक देशों के साथ परामर्श करना चाहिए था।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

42. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन में विषयगत वस्तुओं पर संबद्ध देशों में प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी के अस्तित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किया गया है।

43. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदकों द्वारा दावा की गई विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के अस्तित्व, संचालन और प्रशासन, डब्ल्यूटीओ एएससीएम और भारतीय नियमों के संदर्भ में उनकी प्रतिसंतुलनकारीता और इन योजनाओं के तहत संबद्ध देशों के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्राप्त लाभों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के

लिए लिखित संचार और परामर्श के माध्यम से चीन और ताइवान की सरकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। चीन पीआर और ताइवान की सरकारों द्वारा दायर प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड में लिया गया है और प्राधिकरण द्वारा उनकी जांच की गई है।

44. प्राधिकरण ने निम्नलिखित सीवीडी कार्यक्रमों के लिए जांच शुरू की, जिसमें विचाराधीन उत्पाद के उत्पादकों को संभावित रूप से प्रतिसंतुलनकारी लाभ प्राप्त हुए होंगे।

<u>चीन जन.गण.</u>

I. चीन जन.गण. के संबंध में अनुदान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची।

1. विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान

2. प्रसिद्ध ब्रांडों और चीन के विश्व के शीर्ष ब्रांडों के विकास के लिए सब्सिडी

3. स्थानीय सरकारों द्वारा एंटी-डंपिंग या सीवीडी कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति

4. राज्य प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजना निधि

5. निर्यात सहायता अनुदान

6. ब्याज भुगतान सब्सिडी

7. सुपरस्टार उद्यम अनुदान

8. राष्ट्रीय उच्च प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास अनुदान और निधि

9. नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए विशेष कोष

10. जियांग्सू प्रांत के सूज़ौ औद्योगिक पार्क को हरित विकास के लिए विशेष कोष

11. वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनहुई फंड

12. जिआंगसू प्रांत द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष सरकारी अनुदान

II. चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में कर और वैट प्रोत्साहन के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची।

13. सहक्रियात्मक उपयोग से संसाधन उत्पादों के लिए उद्यम आयकर (ईआईटी) विशेषाधिकार

14.FIE के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिमान्य कर नीतियां

15. प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात शुल्क और मूल्य वर्धित कर छूट

16. सहक्रियात्मक संसाधन उपयोग से उत्पन्न उत्पादों के लिए वैट में कमी/छूट

17. उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए उद्यम आयकर ('ईआईटी') में कटौती

18. अनुसंधान और विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती

19. उच्च तकनीक विकास और उत्पादन के लिए उच्च तकनीक उद्यमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों का त्वरित मूल्यह्रास

20. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट

21. घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों पर वैट छूट

22. घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों की खरीद के लिए आयकर क्रेडिट

23. विशेष उपकरणों की खरीद के संबंध में कर क्रेडिट

24. स्वच्छ विकास तंत्र के लिए अधिमान्य कर नीतियां

25. शंघाई के एसईजेड और पुडोंग न्यू एरिया में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां

III. चीन जनवादी गणराज्य के संबंध में अपर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

26. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकार

27. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान

28. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर कोयला, स्टीम कोयला और कोकिंग कोयले का प्रावधान

29. निर्यातक विक्रेता ऋण कार्यक्रम

30. निर्यातक क्रेता ऋण कार्यक्रम

31. निर्यात ऋण बीमा

32. प्रमुख परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों / माननीय उद्यमों के लिए अधिमान्य ऋण

33. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए अधिमान्य ऋण

34. एलटीएआर में प्राथमिक एल्युमीनियम का प्रावधान

<u>ताइवान</u>

I. ताइवान के संबंध में कर प्रोत्साहन के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

1. अनुसंधान और विकास व्यय के लिए आयकर क्रेडिट

2. इन-ज़ोन उद्यमों के लिए शुल्क और कर छूट

3. उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए शुल्क और कर छूट

4. नए उभरते, महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योगों में निवेश के लिए शेयरधारक निवेश कर क्रेडिट

II. ताइवान के संबंध में अनुदान के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

5. कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान

6. अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान

7. उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम

8. राष्ट्रीय विकास निधि के माध्यम से वित्तीय सहायता

9. नई उत्कृष्ट परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान

10. उत्कृष्ट प्रदर्शन चाहने वाले उद्यमों के लिए स्व-मूल्यांकन सेवा

11. पारंपरिक उद्योग प्रौद्योगिकी विकास निधि

III. ताइवान के संबंध में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम (एलटीएआर) के रूप में पहचाने गए कार्यक्रमों/योजनाओं की सूची

12. औद्योगिक पार्कों में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए सब्सिडी

13. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि का प्रावधान

45. शुरूआत के बाद, विषयगत वस्तुओं के उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए सूचित किया गया था और उन्हें कथित सब्सिडी कार्यक्रम के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव पर सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया गया था ताकि ऐसी सब्सिडी, यदि कोई हो, के अस्तित्व और मात्रा का उचित निर्धारण किया जा सके।

46. जांच की शुरूआत के बाद उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर, जिसमें पक्षों द्वारा दायर किए गए उत्तरों के अगोपनीय सारांश और चीन जनवादी गणराज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका में डीओपीपी के आयात के लिए यूएसडीओसी के प्रतिकारी शुल्क निर्धारण शामिल हैं, घरेलू उद्योग ने जांच की शुरूआत के बाद उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर कुछ 'नई सब्सिडी' का भी आरोप लगाया है:

1. प्रिंटिंग प्लेट उद्योग के लिए नीति ऋण
2. एलटीएआर के लिए एल्युमिनियम शीट का प्रावधान
3. एलटीएआर के लिए एल्युमिनियम फॉयल का प्रावधान
4. विदेशी व्यापार सहायता निधि
5. बाजार और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए एसएमई को सब्सिडी
6. विदेशी व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि
7. 2021 में उच्च तकनीक उद्यमों के लिए सब्सिडी
8. नगर निगम के प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सब्सिडी निधि पोस्ट करें
9. उद्यम अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सब्सिडी
10. वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि परिवर्तन परियोजनाएं
11. तीन सितारा रेटेड उद्यम पुरस्कार
12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार
13. चार सितारा रेटेड करदाता उद्यम पुरस्कार
14. बेरोजगारी बीमा, पदों को स्थिर करने, कौशल में सुधार लाने और बेरोजगारी रोकने में अच्छा काम

15. निर्यात पुरस्कार नीतियां
16. व्यापक बंधुआ क्षेत्र
17. राष्ट्रीय कौशल पुनरोद्धार परियोजनाएँ 2012
18. उन्नत विनिर्माण के लिए निधि
19. उद्यम नवाचार और विकास के लिए वित्तीय सहायता छूट निधि
20. मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो - रोज़गार को स्थिर करने और बेरोज़गारी को रोकने के लिए उद्योगों की सहायता करना
21. हैकांग जिले में औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और उन्नयन को बढ़ावा देने तथा गुणवत्ता और दक्षता में सुधार लाने के लिए कई उपायों के तहत उद्यमों को तेजी से विकास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी
22. 2021 हाईकांग जिले में औद्योगिक उद्यम तकनीकी सुधार सब्सिडी निधि
23. औद्योगिक अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी
24. 2022 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन का स्थिर संचालन
25. औद्योगिक उद्यम का स्थिर विकास
26. बेरोजगारी बीमा, पदों को स्थिर करने, कौशल में सुधार और बेरोजगारी को रोकने में अच्छी नौकरी

47. प्राधिकरण ने चीन पीआर और ताइवान की सरकारों सहित सभी इच्छुक पक्षों को नए सब्सिडी के आरोप और साक्ष्य प्रसारित किए और आरोपों पर टिप्पणियां मांगीं । प्राधिकरण ने नोट किया कि जांच प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त सब्सिडी की पहचान तथ्यों की व्यापक जांच का एक स्वाभाविक परिणाम है और यह व्यापार सुधारात्मक जांच की गतिशील प्रकृति को दर्शाता है। प्राधिकरण को सब्सिडी की सीमा को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए जांच के दौरान उत्पन्न सभी तथ्यों का आकलन करना आवश्यक है।

48. **चीन जन. गण.:** चीन जन. गण. के निम्नलिखित उत्पादकों (अपने निर्यातकों सहित) ने विषयगत जांच में प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया है तथा नीचे उल्लिखित योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ उठाना स्वीकार किया है:

क. कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड.

ख. लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड

ग. फ़ूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड

घ. हुआंगशांग जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

ङ. अनहुइ स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड

च. चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड

<u>कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड.</u>

49. कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. विदेशी व्यापार विकास निधि

ii. अनुसंधान एवं विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती

iii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि-उपयोग अधिकार

iv. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान कार्यक्रम

v. प्राथमिक एल्युमीनियम/एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान

vi. उन्नत विनिर्माण के लिए निधि

vii. उद्यम नवाचार और विकास के लिए वित्तीय सहायता छूट निधि

viii. मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो - रोज़गार को स्थिर करने और बेरोज़गारी को रोकने के लिए उद्योगों की सहायता करना

ix. 2021 हाईकांग जिले में औद्योगिक उद्यम तकनीकी सुधार सब्सिडी निधि

x. 2022 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन का स्थिर संचालन

xi. औद्योगिक उद्यम का स्थिर विकास

xii. बेरोजगारी बीमा, पदों को स्थिर करने, कौशल में सुधार और बेरोजगारी को रोकने में अच्छी नौकरी

50. यह ध्यान देने योग्य है कि कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड ने उपरोक्त कार्यक्रमों की स्वयं रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, इसने अन्य अनुदानों की भी रिपोर्ट की है, जिनका आवेदक द्वारा आरोप नहीं लगाया गया था। प्राधिकरण ने उन अनुदानों की भी जांच की है।

<u>लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड</u>

51. लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. विदेशी व्यापार विकास निधि
ii. स्थानीय सरकारों द्वारा एंटी-डंपिंग या सी.वी.डी. कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति
iii. उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए उद्यम आयकर विशेषाधिकार
iv. अनुसंधान एवं विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती
v. योग्य निवासी उद्यमों के बीच विभाजित छूट
vi. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि-उपयोग अधिकार
vii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान कार्यक्रम
viii. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य ऋण
ix. प्राथमिक एल्युमीनियम/एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान
x. विदेशी व्यापार सहायता निधि
xi. बाजार और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए एसएमई को सब्सिडी
xii. विदेशी व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि
xiii. 2021 में उच्च तकनीक उद्यमों के लिए सब्सिडी
xiv. नगर निगम के प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सब्सिडी निधि पोस्ट करें
xv. उद्यम अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सब्सिडी
xvi. वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि परिवर्तन परियोजनाएं
xvii. तीन सितारा रेटेड उद्यम पुरस्कार
xviii. विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार
xix. चार सितारा रेटेड करदाता उद्यम पुरस्कार
xx. बेरोजगारी बीमा, पदों को स्थिर करने, कौशल में सुधार लाने और बेरोजगारी रोकने में अच्छा काम
xxi. निर्यात पुरस्कार नीतियां
xxii. व्यापक बंधुआ क्षेत्र
xxiii. राष्ट्रीय कौशल पुनरोद्धार परियोजनाएँ 2012
xxiv. उन्नत विनिर्माण के लिए निधि
xxv. उद्यम नवाचार और विकास के लिए वित्तीय सहायता छूट निधि

52. यह ध्यान देने योग्य है कि लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड ने उपरोक्त कार्यक्रमों की प्राप्ति की स्वयं रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, इसने अन्य अनुदानों की प्राप्ति की भी रिपोर्ट की है, जिनका आवेदक ने आरोप नहीं लगाया था। प्राधिकरण ने उन अनुदानों की भी जांच की है।

फूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड

53. फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. जियांग्सू प्रांत के सूज़ौ औद्योगिक पार्क को हरित विकास के लिए विशेष निधि
ii. बेरोजगारी बीमा, पदों को स्थिर करने, कौशल में सुधार और बेरोजगारी को रोकने में अच्छी नौकरी
iii. 2022 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन का स्थिर संचालन
iv. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि-उपयोग अधिकार
v. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान कार्यक्रम
vi. एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान

54. यह ध्यान देने योग्य है कि फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड ने उपरोक्त कार्यक्रमों की प्राप्ति की स्वयं रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, इसने अन्य अनुदानों की प्राप्ति की भी रिपोर्ट की है, जिनका आवेदक द्वारा आरोप नहीं लगाया गया था। प्राधिकरण ने उन अनुदानों की भी जांच की है।

हुआंगशांग जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

55. हुआंगशांग जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. विदेशी व्यापार विकास निधि
ii. उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए उद्यम आयकर विशेषाधिकार
iii. अनुसंधान एवं विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती
iv. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान कार्यक्रम
v. प्राथमिक एल्युमीनियम/एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान

56. यह ध्यान देने योग्य है कि हुआंगशांग जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने उपरोक्त कार्यक्रमों की प्राप्ति की स्वयं रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, इसने अन्य अनुदानों की प्राप्ति की भी रिपोर्ट की है, जिनका आवेदक द्वारा आरोप नहीं लगाया गया था। प्राधिकरण ने उन अनुदानों की भी जांच की है।

अनहुइ स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड

57. अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. विदेशी व्यापार विकास निधि
ii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि-उपयोग अधिकार
iii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान कार्यक्रम
iv. प्राथमिक एल्युमीनियम/एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान
v. राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए अधिमान्य ऋण

58. यह ध्यान देने योग्य है कि एन्हुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने उपरोक्त कार्यक्रमों की प्राप्ति की स्वयं रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, इसने अन्य अनुदानों की प्राप्ति की भी रिपोर्ट की है, जिनका आवेदक द्वारा आरोप नहीं लगाया गया था। प्राधिकरण ने उन अनुदानों की भी जांच की है।

<u>चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड</u>

59. चोंग्किंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दी गई जानकारी के संबंध में, प्राधिकरण ने निम्नलिखित कार्यक्रमों की जांच की है:

i. विदेशी व्यापार विकास निधि
ii. अनुसंधान एवं विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती
iii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि-उपयोग अधिकार
iv. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली का प्रावधान कार्यक्रम
v. प्राथमिक एल्युमीनियम/एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान

60. यह ध्यान देने योग्य है कि चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड ने उपरोक्त कार्यक्रमों की प्राप्ति की स्वयं रिपोर्ट की है। इसके अतिरिक्त, इसने अन्य अनुदानों की प्राप्ति की भी रिपोर्ट की है, जिनका आवेदक द्वारा आरोप नहीं लगाया गया था। प्राधिकरण ने उन अनुदानों की भी जांच की है।

61. निम्नलिखित कार्यक्रमों का लाभ किसी भी प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा नहीं उठाया गया था, इसलिए संबंधित कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी मार्जिन की मात्रा निर्धारित करने और न्यायिक मितव्ययिता के प्रयोजनार्थ किसी विशिष्ट सूचना और साक्ष्य के अभाव में प्राधिकरण द्वारा इनकी जांच नहीं की जा रही है।

i. सहक्रियात्मक उपयोग से संसाधन उत्पादों के लिए उद्यम आयकर (ईआईटी) विशेषाधिकार

ii. FIE के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिमान्य कर नीतियां
iii. प्रोत्साहित उद्योगों में आयातित उपकरणों पर आयात शुल्क और मूल्य वर्धित कर छूट
iv. सहक्रियात्मक संसाधन उपयोग से उत्पन्न उत्पादों के लिए वैट में कमी/छूट
v. अनुसंधान एवं विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती
vi. उच्च तकनीक विकास और उत्पादन के लिए उच्च तकनीक उद्यमों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों का त्वरित मूल्यह्रास
vii. योग्य निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट
viii. घरेलू स्तर पर उत्पादित उपकरणों पर वैट छूट
ix. घरेलू स्तर पर निर्मित उपकरणों की खरीद के लिए आयकर क्रेडिट
x. विशेष उपकरणों की खरीद के संबंध में कर क्रेडिट
xi. स्वच्छ विकास तंत्र के लिए अधिमान्य कर नीतियां
xii. शंघाई के एसईजेड और पुडोंग न्यू एरिया में स्थापित उद्यमों के लिए अधिमान्य कर नीतियां
xiii. कोयला, स्टीम कोयला और कोकिंग कोयले का प्रावधान पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर
xiv. निर्यातक विक्रेता ऋण कार्यक्रम
xv. निर्यातक क्रेता ऋण कार्यक्रम
xvi. निर्यात ऋण बीमा
xvii. प्रमुख परियोजनाओं और प्रौद्योगिकियों / माननीय उद्यमों के लिए अधिमान्य ऋण

62. **ताइवान:** प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ताइवान से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल नहीं किए हैं। तदनुसार, इन उत्पादकों के लिए कोई व्यक्तिगत मार्जिन या शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।

क. कानूनी ढांचा

63. प्रशुल्क और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("जीएटीटी") के अनुच्छेद VI को सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों ("एएससीएम") संबंधी करार के अनुच्छेद 19 के साथ पढ़ा जाए तो आयात करने वाले देशों को सब्सिडी वाले आयातित सामानों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की अनुमति मिलती है।

64. तदनुसार, सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 केंद्र सरकार को सब्सिडी वाले आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने की अनुमति देती है। सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(1) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> *(1) जहां कोई देश या क्षेत्र किसी वस्तु के विनिर्माण या उत्पादन पर या वहां से निर्यात पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्षत रूप से कोई राजसहायता देता है, प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत ऐसी वस्तु के परिवहन पर कोई राजसहायता भी है, वहां भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात पर, चाहे वह विनिर्माण, उत्पादन के देश से सीधे आयात की गई हो या अन्यथा, और चाहे वह उसी स्थिति में आयात की गई हो जैसी विनिर्माण या उत्पादन के देश से निर्यात करते समय थी या विनिर्माण, उत्पादन या अन्यथा द्वारा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया हो, केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सब्सिडी की राशि से अधिक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगा सकती है।*

65. सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(1) के स्पष्टीकरण में एएससीएम के अनुच्छेद 1 की वही भाषा है, जो प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच के प्रयोजनों के लिए 'सब्सिडी' को परिभाषित करती है। इसमें यह उल्लेख है कि सब्सिडी तब मानी जाएगी यदि:

> *(क) निर्यातक या उत्पादक देश या क्षेत्र में सरकार या किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान दिया जाता है, अर्थात, जहां -*
>
> *(i) किसी सरकारी कार्य-पद्धति में निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (अनुदान, ऋण और इक्विटी निवेश सहित) या निधियों या देनदारियों का संभावित प्रत्यक्ष अंतरण, या दोनों शामिल हैं;*
>
> *(ii) अन्यथा देय सरकारी राजस्व को छोड़ दिया जाता है या संग्रहीत नहीं किया जाता है (राजकोषीय प्रोत्साहन सहित);*
>
> *(iii) कोई सरकार सामान्य अवसंरचना के अलावा अन्य वस्तुएं या सेवाएं प्रदान करती है या वस्तुएं खरीदती है;*
>
> *(iv) कोई सरकार किसी वित्तपोषण तंत्र को भुगतान करती है, या किसी निजी निकाय को खंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट एक या अधिक प्रकार के कार्यों को पूरा करने के लिए सौंपती है या निर्देश देती है, जो सामान्य रूप से सरकार में निहित होते हैं और कार्य-पद्धति, किसी भी वास्तविक अर्थ में, सरकारों द्वारा सामान्य रूप से अपनाए जाने वाले कार्य-पद्धतियों से भिन्न नहीं होता है; या*

(ख) सरकार किसी भी प्रकार की आय या कीमत सहायता प्रदान करती है या बनाए रखती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके क्षेत्र से किसी वस्तु के निर्यात को बढ़ाने या उसके आयात को कम करने के लिए संचालित होती है, और इसके द्वारा कोई लाभ प्रदान किया जाता है।

66. इसके अतिरिक्त, सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9(3) में यह उल्लेख है कि किसी सब्सिडी को प्रतिसंतुलनकारणीय बनाने के लिए, यह अवश्य होना चाहिए:

क. वित्तीय योगदान

ख. सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा

ग. जो लाभ प्रदान करता है

घ. वस्तुओं के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात में लगे विशिष्ट व्यक्तियों को, या निर्यात प्रदर्शन या स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं पर आधारित है

67. उपलब्ध तथ्यों पर विश्वास: प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नियमावली का नियम 7(8) प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा जांच में सहयोग न करने की स्थिति में 'उपलब्ध तथ्यों' पर विश्वास करने की अनुमति देता है। इस संबंध में, यह कहा गया है:

*ऐसे मामले में जहां कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है, या **उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं** और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जो वह ऐसी परिस्थिति में उचित समझें।*

ख. प्रतिसंतुलनकारणीय पाए गए कार्यक्रम

- **अनुदान**

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुदान कार्यक्रमों की मौजूदगी की सूचना दी गई है:

i. एफएफपीएस को केवल (ए) जिआंगसू प्रांत के सूज़ौ औद्योगिक पार्क के लिए हरित विकास के लिए विशेष निधि, (बी) बेरोजगारी बीमा में अच्छी नौकरी, पदों को स्थिर करना, कौशल में सुधार और बेरोजगारी को रोकना (सी) 2022

की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन का स्थिर संचालन के तहत लाभ मिला, जिन्हें भी समाप्त कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभ न तो सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों (एएससीएम) के समझौते के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निषिद्ध सब्सिडी है और न ही यह काउंटरवेल करने योग्य है।

ii. लकी ने (i) विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान, (ii) स्थानीय सरकारों द्वारा एंटी-डंपिंग या काउंटरवेलिंग ड्यूटी कानूनी खर्चों की प्रतिपूर्ति, और (iii) अन्य सरकारी अनुदानों के तहत लाभ उठाया है।

iii. कोडक ने (i) विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान और (ii) अन्य सरकारी अनुदानों के तहत लाभ उठाया है।

ख. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

69. घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

i. फुजीफिल्म का दावा है कि उसे केवल तीन विशिष्ट योजनाओं से लाभ हुआ, जिसके बारे में उसका तर्क है कि उन्हें समाप्त कर दिया गया, घरेलू उद्योग द्वारा इसका खंडन किया गया है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि फुजीफिल्म ने केवल उन तीन योजनाओं से अधिक का लाभ उठाया, अमेरिकी वाणिज्य विभाग (यूएसडीओसी) ने पुष्टि की है कि फुजीफिल्म को अनुदान, नीति ऋण और बाजार से कम दरों पर एल्यूमीनियम प्रावधान और बिजली से संबंधित लाभों सहित अतिरिक्त सब्सिडी कार्यक्रमों से लाभ हुआ।

ii. फुजीफिल्म का यह दावा कि कुछ सब्सिडी प्रतिसंतुलन योग्य नहीं हैं, साक्ष्य या स्पष्टीकरण के बिना अपर्याप्त है, और यह प्रदर्शित करने में विफल रहा है कि ये कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य क्यों नहीं हैं।

iii. इसके अलावा, पीओआई के बाद सब्सिडी कार्यक्रमों की समाप्ति अप्रासंगिक है, क्योंकि पीओआई के दौरान प्रदान किए गए लाभों को सब्सिडी मार्जिन गणना में शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए, घरेलू उद्योग का तर्क है कि पीओआई के दौरान फुजीफिल्म को प्राप्त सभी सब्सिडी को उनकी समाप्ति की परवाह किए बिना गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

ग. प्राधिकरण द्वारा जांच

विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान/विदेशी व्यापार सहायता निधि/विदेशी व्यापार और आर्थिक सहयोग के विकास के लिए विशेष निधि

70. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन सरकार ने जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के मौजूदगी से इनकार किया है। दूसरी ओर, चीन के कुछ उत्पादकों और निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाने की पुष्टि की है:

71. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि जीओसी निर्यातक कंपनियों की परियोजनाओं को उनके निर्यातित उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने, निर्यात प्रसंस्करण आधार विकसित करने, विदेशों में ट्रेडमार्क पंजीकृत करने, विदेशी व्यापार पेशेवरों को प्रशिक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए अनुदान प्रदान करता है। उल्लेखनीय रूप से, यूएसडीओसी ने 2024 में चीन से यूएसए में विचाराधीन उत्पाद के आयात के लिए भी इस कार्यक्रम पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया है।

72. घरेलू उद्योग ने कार्यक्रम के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं।

i. विदेशी आर्थिक और व्यापार विकास के लिए विशेष निधियों के प्रशासन के लिए उपाय (वित्त मंत्रालय परिपत्र कै क्यूई संख्या 36, 2014)
ii. 2022 में "तीन विदेशी" विकास परियोजनाओं के समर्थन के लिए सब्सिडी निधि जारी करने की सूचना
iii. पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एल्युमिनियम लिथोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स की काउंटरवेलिंग ड्यूटी जांच में यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स **("यूएसडीओसी")** द्वारा जारी अंतिम निर्धारण

73. ***वित्तीय योगदान:*** प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि कार्यक्रम में धन का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है, इसलिए यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के तात्पर्य से 'वित्तीय योगदान' होता है।

74. ***लाभ:*** अनुदान स्वतः ही लाभ हैं। सीवीडी नियमावली के अनुबंध IV में कहा गया है कि जहां कोई भी धनराशि वापस नहीं की जाती है, सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि होनी चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त अनुदान की संपूर्णता को सब्सिडी माना गया है। किसी भी उत्पादक ने धनराशि का कोई पुनर्भुगतान नहीं दर्शाया है।

75. ***विशिष्टता:*** सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध III के भाग I के पैराग्राफ (क) के अनुसार, निर्यात प्रदर्शन के

आधार पर किसी फर्म को प्रत्यक्ष सब्सिडी का प्रावधान एक निर्यात सब्सिडी है, और उस कारण से, यह विशिष्ट है।

76. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि विदेशी व्यापार विकास निधि अनुदान सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है।

स्थानीय सरकारों द्वारा पाटनरोधी या सी.वी.डी. कानूनी व्यय की प्रतिपूर्ति

77. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि कंपनियाँ पाटनरोधी कार्यवाही में भाग लेने के लिए खर्च की गई कानूनी फीस का 40% रिफंड पाने की पात्र हैं। लकी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाया है।

78. घरेलू उद्योग ने कार्यक्रम के समर्थन में निम्नलिखित पर भरोसा किया है।
i. एंटी-डंपिंग, एंटी-सब्सिडी, सुरक्षा जांच प्रतिवादी के लिए समर्थन नीति के कार्यान्वयन के नियम
ii. झेजियांग प्रांत के निर्यात उत्पादों के संबंध में एंटी-डंपिंग के लिए प्रतिवाद
iii. ब्राजील और दक्षिण कोरिया जैसे विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में पीयूसी के चीनी उत्पादकों के खिलाफ शुरू की गई विभिन्न व्यापार सुधारात्मक जांचों के साक्ष्य

79. ***वित्तीय योगदान:*** प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि कार्यक्रम में धन का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है, इसलिए यह सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के तात्पर्य से 'वित्तीय योगदान' होता है।

80. ***लाभ:*** अनुदान स्वतः ही लाभ है। सीवीडी नियमावली के अनुबंध IV में कहा गया है कि जहां कोई भी धन वापस नहीं किया जाता है, सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि होनी चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त अनुदान की संपूर्णता को सब्सिडी माना गया है।

81. ***विशिष्टता:*** सब्सिडी कार्यक्रम केवल निर्यातकों के लिए उपलब्ध हो सकता है, इस कारण से सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध III के भाग के पैराग्राफ (क) के अनुसार, निर्यात प्रदर्शन के आधार पर यह कार्यक्रम है और यह एक निर्यात सब्सिडी है।

82. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है। लाभ का

परिमाण निर्धारित करने के लिए सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बताई गई लाभ की मात्रा पर विचार किया गया है।

निर्यात सहायता अनुदान

83. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन की कंपनियों को निर्यात बाजारों के विकास में सहायता करने या निर्यात प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए निर्यात सहायता अनुदान प्राप्त होता है। इसने सब्सिडी कार्यक्रम की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य प्रदान किए हैं। हालाँकि, न तो जीओसी और न ही सहयोगी उत्पादकों ने कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोडक ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ उठाया है।

84. घरेलू उद्योग ने "रणनीतिक और भारी उद्योगों को चीन की सब्सिडी का आकलन" नामक एक अध्ययन पर भरोसा किया, जिसमें विभिन्न उत्पादों के चीनी उत्पादकों को दी गई सब्सिडी का विश्लेषण किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राधिकरण ने नोट किया है कि इस कार्यक्रम को नामित प्राधिकरण के साथ-साथ अन्य देशों के जांच अधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलन योग्य माना गया है।

85. प्राधिकरण ने नोट किया है कि यह कार्यक्रम लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास निधि के प्रशासन के लिए उपाय जारी करने के संबंध में सहयोग के परिपत्र (परीक्षण कार्यान्वयन के लिए) (काई क्यूई (2000) संख्या 467) और लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास निधि के प्रशासन के लिए उपायों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम (अनंतिम कार्यान्वयन के लिए) (वाई जिंग माओ जी काई फा (2001) संख्या 270) के तहत शासित था। हालांकि, दोनों विनियमनों को वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकास निधि के लिए प्रशासनिक उपाय जारी करने के नोटिस (काई क्यूई (2010) संख्या 87) दिनांक 24 मई 2010 के साथ प्रतिस्थापित किया गया था और आगे 2014 संशोधन (काई क्यूई (2014) संख्या 36 दिनांक 9 अप्रैल 2014 के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। कार्यक्रम का प्रशासन वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के साथ-साथ चीन पीआर के प्रांतीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

86. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** अनुदान स्वतः ही लाभ प्रदान नहीं करता है। ये अनुदान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) के तात्पर्य से वित्तीय योगदान होता

है क्योंकि वे निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण हैं। सीवीडी नियमावली के अनुबंध IV में कहा गया है कि जहां कोई भी धनराशि वापस नहीं की जाती है, सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि होनी चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त समग्र अनुदान पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया ही जाना चाहिए।

87. ***विशिष्टता:*** सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध III के भाग के पैराग्राफ (क) के अनुसार, निर्यात प्रदर्शन के आधार पर किसी फर्म को दी जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी का प्रावधान एक सब्सिडी है और इस कारण से यह विशिष्ट है।

88. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है। लाभ का परिमाण निर्धारित करने के लिए सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बताई गई लाभ की मात्रा पर विचार किया गया है।

जियांग्सू प्रांत का सूज़ौ औद्योगिक पार्क हरित विकास के लिए विशेष निधि

89. प्राधिकरण ने नोट किया है कि चीन सरकार ने जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अस्तित्व से इनकार किया है। दूसरी ओर, चीनी उत्पादकों और निर्यातकों ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने की पुष्टि की है। विशेष रूप से, फुजीफिल्म ने इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाया है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि चीन सरकार ने 2021 में एससीएम समझौते के अनुच्छेद 25 के तहत आवश्यक रूप से इस कार्यक्रम को डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित किया था।

90. फुजीफिल्म ने तर्क दिया है कि चूंकि कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है, इसलिए इसका प्रतिकार नहीं किया जाना चाहिए। फुजीफिल्म ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि उसे जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम से कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में, उसे जांच अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के तहत धन प्राप्त हुआ है।

91. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** अनुदान स्वतः ही लाभ प्रदान नहीं करता है। ये अनुदान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 (1) के तात्पर्य से वित्तीय योगदान होता है क्योंकि वे निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण हैं। सीवीडी नियमावली के अनुबंध IV में कहा गया है कि जहां कोई भी धनराशि वापस नहीं की जाती है, सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि होनी चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त समग्र अनुदान पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया ही जाना चाहिए।

92. ***विशिष्टता:*** सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध II के भाग के पैराग्राफ 1(क) के अनुसार, अनुदान कानून के रूप में उन उद्योगों तक सीमित है जो जल प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं, और उस कारण से यह विशिष्ट हैं। एससीएम समझौते के करार के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत चीन द्वारा संगत डब्ल्यूटीओ अधिसूचना भी उन परियोजनाओं के लिए पात्रता परीक्षा का संकेत देती है जो इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकती हैं। यह सूज़ौ के भौगोलिक क्षेत्र के लिए भी विशिष्ट है।

93. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है। लाभ का परिमाण निर्धारित करने के लिए सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बताई गई लाभ की मात्रा पर विचार किया गया है।

सूज़ौ औद्योगिक पार्क वाहक निर्माण लाभ

94. फ़ूजीफिल्म ने इस अनुदान की स्वयं रिपोर्ट की है, और इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाया है। सूज़ौ औद्योगिक पार्क में कुछ कंपनियाँ निम्नलिखित लाभों के लिए पात्र हैं:

    क. वाहक निर्माण पर कंपनी के कुल व्यय का 10% तक का अनुदान, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए एक वर्ष में 2 मिलियन युआन तक सीमित है; और
    ख. कंपनी के कुल निवेश का 10% तक का अनुदान, जो 2 वर्ष की अवधि के लिए एक वर्ष में 3 मिलियन युआन तक सीमित है।

95. फ़ूजीफिल्म ने तर्क दिया है कि चूंकि कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है, इसलिए इसका प्रतिपूर्ति नहीं की जानी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि फ़ूजीफिल्म को इस कार्यक्रम के तहत पीओआई के दौरान धन प्राप्त हुआ है।

96. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** अनुदान स्वतः लाभ प्रदान करते हैं। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के अर्थ में अनुदान एक वित्तीय योगदान है क्योंकि वे धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हैं। CVD नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि जहां कोई भी धन वापस नहीं किया जाता है, सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि होनी चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त अनुदान की संपूर्णता का प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए।

97. ***विशिष्टता:*** सूज़ौ औद्योगिक पार्क निवेश संवर्धन समिति ने फ़ूजीफिल्म को अपनी नई परियोजना का समर्थन करने के लिए अनुदान प्रदान किया। परियोजना में कुल 300 मिलियन युआन का निवेश करने की योजना है, जिसमें 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम की अतिरिक्त पंजीकृत पूंजी नहीं है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), CVD नियमों के नियम 11 और अनुलग्नक II के भाग के पैराग्राफ 1(ए) के अनुसार, अनुदान कानून के मामले में कुछ उद्योगों तक सीमित है, और इस प्रकार, विशिष्ट है।

98. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकरण पाता है कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत एक प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी है। लाभ का परिमाण निर्धारित करने के लिए सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा बताई गई लाभ की राशि पर विचार किया गया है।

ऐसे कार्यक्रम जिनके लिए सहयोगी उत्पादकों द्वारा अपर्याप्त जानकारी प्रदान की गई है

99. विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों को जारी प्रश्नावली में स्पष्ट रूप से उनसे उनके द्वारा प्राप्त प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक मानक प्रश्न परिशिष्ट प्रदान करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, निम्नलिखित कार्यक्रमों के लिए, उत्पादक/निर्यातक एक मानक प्रश्न परिशिष्ट प्रदान करने में विफल रहे हैं, और उन्होंने केवल अपने प्रश्नावली के जवाब में एक वित्तीय योगदान के अस्तित्व की सूचना दी है:

क. बाजार और अन्य परियोजनाओं को विकसित करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सब्सिडी

ख. नगर निगम की प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी/वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि परिवर्तन परियोजनाओं/विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार/2018-19 में प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेष परियोजनाओं के बाद वित्त पोषण के लिए सब्सिडी के बाद की निधि

ग. उद्यम अनुसंधान और विकास के लिए वित्तीय सब्सिडी / डिजिटल ऑफसेट प्लेटों के लिए नए कार्यात्मक यौगिकों का अनुसंधान और विकास

घ. तीन सितारा रेटेड उद्यम पुरस्कार / चार सितारा रेटेड करदाता उद्यम पुरस्कार

ङ. बेरोजगारी बीमा में अच्छा काम, पदों को स्थिर करना, कौशल में सुधार और बेरोजगारी को रोकना

च. निर्यात पुरस्कार नीतियां

छ. व्यापक बंधुआ क्षेत्र

ज. राष्ट्रीय कौशल पुनरोद्धार परियोजनाएं 2012

झ. उन्नत विनिर्माण के लिए निधि

ञ. उद्यम नवाचार और विकास के लिए वित्तीय सहायता छूट निधि

ट. मानव संसाधन और सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो - रोजगार को स्थिर करने और बेरोजगारी को रोकने के लिए उद्योगों की सहायता करना

ठ. परिवर्तन को बढ़ावा देने और औद्योगिक अर्थव्यवस्था को उन्नत करने और हैकांग जिले में गुणवत्ता और दक्षता में सुधार के लिए कई उपायों के तहत छलांग विकास को प्राप्त करने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी

ड. हैकांग जिले में 2021 औद्योगिक उद्यम तकनीकी सुधार सब्सिडी निधि

ढ. 2022 की पहली तिमाही में औद्योगिक उत्पादन का स्थिर संचालन / औद्योगिक अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी

ण. औद्योगिक उद्यम का स्थिर विकास

त. 2021 में उच्च तकनीक उद्यमों के लिए सब्सिडी

थ. बेरोजगारी बीमा, पदों को स्थिर करने, कौशल में सुधार और बेरोजगारी को रोकने में अच्छा काम

द. 2021 में उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए क्षेत्रीय वित्तीय सहायता

ध. 2021 में उद्यमों के अनुसंधान एवं विकास के लिए नगरपालिका सब्सिडी

न. 2021 में प्रमुख प्रयोगशालाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार निधि से सम्मानित किया गया

ऩ. व्यक्तिगत आयकर प्रतिपूर्ति

प. नानयांग हैचेंग लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड ने सब्सिडी का भुगतान किया

फ. वोलोंग जिला वित्त ब्यूरो फ़्रंट्स (2022 में उद्यम अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रांतीय वित्तीय सहायता के लिए विशेष निधि)

ब. चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन 18वें अनुसंधान संस्थान परियोजना वित्त पोषण

भ. 2010 के केंद्रीय बजट में प्रमुख उद्योगों (छठे बैच) के पुनरोद्धार और तकनीकी सुधार के लिए निवेश योजना की घोषणा

म. कर्मचारी प्रतिधारण भत्ता

कक. भविष्य निधि केंद्र विस्तारोत्तर लाभ

खख. 2022 नामित प्रमुख औद्योगिक उद्यमों के लिए वार्षिक पुरस्कार (स्थिर विकास और उत्पादन प्रोत्साहन)

100. यह देखा गया है कि उत्पादकों/निर्यातकों ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त विवरण दिए बिना ही सूचना प्रदान की है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकरण ने इन लाभों को प्रतिसंतुलन योग्य माना है और लाभ निर्धारित किए हैं।

101. सहयोगी उत्पादकों द्वारा बताई गई लाभ की राशि को उनके संबंधित लाभ की मात्रा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा गया है।

अनुदानों के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना

102. सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि जहां कोई भी राशि वापस नहीं की जाती है, वहां सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि होनी चाहिए। गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए, प्राधिकरण ने अन्य सहयोगी उत्पादकों के लिए गणना किए गए मार्जिन सहित उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

क्र.सं.	**उत्पादक**	**अनुदान के लिए सब्सिडी मार्जिन**
1	कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	0-10%
2	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0-10%
3	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड	0-10%
4	हुआंगशान जिनरुइटाई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	0-10%
5	चोंग्किंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड	0-10%
6	अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल	0-10%
7	अन्य सभी उत्पादक	0-10%

<u>पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान</u>

एसओई के लिए अधिमान्य ऋण

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

103. इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, पता नंबर 31, पिंग एनली वेस्ट स्ट्रीट, ज़िचेंग जिला, बीजिंग, चीन है। एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है।

ii. लकी को ऋण वित्तीय संस्थान से वाणिज्यिक ऋण के बजाय निजी ऋण के रूप में इसकी संबंधित कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है। ब्याज दरें पीपुल्स बैंक ऑफ़ चाइना (वेबसाइट https://www.chinamoney.com.cn/english/bmklpr/) द्वारा अधिकृत नेशनल इंटरबैंक फंडिंग सेंटर द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित लोन प्राइम रेट (एक वर्षीय ऋण) के अनुसार हैं।

iii. लकी ने अपनी संबंधित कंपनी यानी एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से ऋण लिया है, इसलिए ऐसी कोई पात्रता आवश्यकता नहीं है जिसे कंपनी ने विशेष रूप से पूरा किया हो।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियां

104. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

i. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि केंद्रीय और उप-केंद्रीय स्तर पर चीनी सरकार राज्य पूंजी परिचालन बजट के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को सब्सिडी देती है। एससीओबी को (i) एसओई के कर-पश्चात लाभ; (ii) राज्य के स्वामित्व वाले शेयरों पर भुगतान किए गए पूंजीगत लाभ और लाभांश; (iii) राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण से अर्जित आय; (iv) राज्य के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के परिसमापन से आय; और (v) अन्य राज्य के स्वामित्व वाली पूंजी परिचालन आय से आय प्राप्त होती है।

ii. जीओसी द्वारा तरजीही ऋणों का प्रावधान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ए)(आई) के अर्थ में जीओसी से धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि सरकारी ऋण पर चुकाए गए ब्याज की राशि और जांच अवधि के दौरान तुलनीय वाणिज्यिक ऋण पर सामान्य रूप से देय ब्याज के बीच का अंतर होना चाहिए।

ग. प्राधिकरण द्वारा जांच

105. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि केंद्रीय और उप-केंद्रीय स्तर पर चीनी सरकार राज्य पूंजी परिचालन बजट के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को सब्सिडी देती है। एससीओबी को (i) एसओई के कर-पश्चात लाभ; (ii) राज्य के स्वामित्व वाले शेयरों पर भुगतान किए गए पूंजीगत लाभ और लाभांश; (iii) राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति अधिकारों के हस्तांतरण से अर्जित आय; (iv) राज्य के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों के परिसमापन से आय; और (v) अन्य राज्य के स्वामित्व वाली पूंजी परिचालन आय से आय प्राप्त होती है।

106. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित साक्ष्यों पर भरोसा किया है:

क. वित्त मंत्रालय, केंद्रीय राज्य पूंजी परिचालन बजट के संकलन और रिपोर्टिंग के लिए उपायों के मुद्रण और वितरण पर नोटिस, कै प्री नंबर 133 (26 सितंबर, 2017)
ख. चीनी राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा प्राप्त ऋणों पर रिपोर्ट

107. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** जीओसी का अधिमान्य ऋणों का प्रावधान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(क)(i) के तात्पर्य से जीओसी से निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण है।

108. चीन जन.गण. से कॉमन अलॉय एल्युमिनियम शीट पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आदेश की हाल ही में 2023 में प्रशासनिक समीक्षा में यूएसडीओसी के दृष्टिकोण के अनुरूप, हम प्रस्ताव करते हैं कि 2014 से पहले के वर्षों के लिए, प्राधिकारी ब्लूमबर्ग फेयर वैल्यू उत्पाद (आईडी सी507 (यू.एस. डॉलर) और सी470 (यूरो)) से कॉर्पोरेट बॉन्ड दर आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। इसे 2014 में बंद कर दिया गया था। 2015 और 2016 के लिए, प्राधिकारी ब्लूमबर्ग के बीवीएएल कर्व्स (यू.एस. डॉलर (आईडी बीवीएससी0193) और यूरो (आईडी बीवीएससी0403, बीवीएससी0404, और बीवीएससी0405) से कॉर्पोरेट बॉन्ड दर आंकड़ों पर विश्वास कर सकते हैं। 2017 से, प्राधिकारी ने यू.एस. डॉलर कॉरपोरेट बॉन्ड दर आंकड़ों के लिए ब्लूमबर्ग के बीवीएएल यील्ड कर्व (आईडी आईजीयूयूसी) पर विश्वास किया है। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई अन्य बेंचमार्क प्रस्तुत नहीं किया गया है।

109. सीवीडी नियमावली के अनुबंध IV में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि सरकारी ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि और जांच अवधि के दौरान तुलनीय वाणिज्यिक

ऋण पर सामान्य रूप से देय ब्याज के बीच का अंतर होना चाहिए। इस अंतर को सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण में शामिल किया गया है।

110. ***विशिष्टता:*** चूंकि सब्सिडी केवल राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को दी जाती है, इसलिए सब्सिडी सीवीडी नियमावली के नियम 11 और अनुबंध II के तात्पर्य से विशिष्ट है।

111. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है।

उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि के उपयोग का अधिकार

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

112. अन्य इच्छुक पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम और पता नानयांग का प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय है, जो खेल केंद्र के 200 मीटर पश्चिम में, बिन्हे ईस्ट रोड, नानयांग शहर, हेनान प्रांत में स्थित है।

ii. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बोली, नीलामी या उद्धरण के माध्यम से होती है, <बोली आमंत्रण, नीलामी और उद्धरण के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्माण भूमि उपयोग अधिकार के असाइनमेंट पर भूमि और संसाधन मंत्रालय के भूमि प्रावधान> के विनियमन के अनुसार। राज्य के स्वामित्व वाली निर्माण भूमि का उपयोग करने के अधिकार के असाइनमेंट में बोली, नीलामी या उद्धरण प्रक्रिया का पालन करके खुलेपन और निष्पक्षता को बनाए रखा जाता है। कंपनी भूमि उपयोग अधिकार असाइनमेंट अनुबंध के अनुसार असाइनमेंट शुल्क का भुगतान करती है और भूमि पंजीकरण प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा करती है।

iii. पात्रता मानदंड बोली आमंत्रण, नीलामी या उद्धरण के माध्यम से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र में किसी भी राज्य के स्वामित्व वाली निर्माण भूमि पर, उसके ऊपर या नीचे भूमि-उपयोग अधिकार के असाइनमेंट के लिए आवेदन करना है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पीआरसी में सभी भूमि या तो राज्य या सामूहिक स्वामित्व की है। कंपनियाँ और व्यक्ति हालाँकि 'भूमि उपयोग अधिकार' खरीद सकते हैं। औद्योगिक भूमि के लिए, पट्टा अवधि सामान्यतः 50 वर्ष होती है, जिसे अगले 50 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. चीन सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ए)(iii) के अर्थ में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकार प्रदान करती है।

iii. सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी की राशि, फर्मों द्वारा वस्तुओं या सेवा के लिए भुगतान की गई कीमत और मौजूदा बाजार स्थितियों के संबंध में उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक के बीच का अंतर होना चाहिए, यदि सरकार को भुगतान की गई कीमत इस राशि से कम है। अनुलग्नक IV के (घ) (iii)

iv. चूंकि चीनी सरकार का भूमि पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए भूमि बेंचमार्क उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर निर्भर रहना आवश्यक है।

v. चीन में भूमि-उपयोग अधिकारों के लिए बेंचमार्क पड़ोसी देशों में तुलनीय वाणिज्यिक भूमि मूल्यों पर आधारित है। थाईलैंड, अपने समान आर्थिक विकास स्तर, भौगोलिक निकटता और तुलनीय जनसंख्या घनत्व के साथ, एक उपयुक्त बेंचमार्क प्रदान करता है। विशिष्ट बेंचमार्क थाई औद्योगिक सम्पदा, पार्कों और क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि की कीमतों और उस वर्ष के लिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उत्पादक द्वारा भूमि खरीदी गई थी।

ग. प्राधिकरण द्वारा जांच

113. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि पीआरसी में सभी भूमि या तो राज्य या सामूहिक स्वामित्व की है। हालांकि कंपनियां और व्यक्ति 'भूमि उपयोग अधिकार' खरीद सकते हैं। औद्योगिक भूमि के लिए, लीजहोल्ड सामान्य रूप से 50 वर्ष का होता है, जिसे अगले 50 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। सहयोगी उत्पादकों ने जीओसी

से भूमि खरीदी है। जीओसी ने दावा किया है कि ये लेन-देन बाजार मूल्यों पर किए गए थे, लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।

114. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित साक्ष्यों पर भरोसा किया है:

क. चीन जनवादी गणराज्य का संपत्ति कानून (चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश संख्या 62)
ख. चीन जनवादी गणराज्य का भूमि प्रशासन कानून (चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश संख्या 28)
ग. शहरी अचल संपत्ति प्रशासन पर चीन जनवादी गणराज्य का कानून (चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति का आदेश संख्या 18)
घ. शहरी क्षेत्रों में राज्य के स्वामित्व वाली भूमि के उपयोग के अधिकार के असाइनमेंट और हस्तांतरण के संबंध में चीन जनवादी गणराज्य के अंतरिम विनियम (चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद का आदेश संख्या 55)
ङ. चीन जनवादी गणराज्य के भूमि प्रशासन कानून के कार्यान्वयन पर विनियमन (चीन जनवादी गणराज्य की राज्य परिषद का आदेश [2014] संख्या 653)
च. बोली आमंत्रण, नीलामी और कोटेशन के माध्यम से राज्य के स्वामित्व वाली निर्माण भूमि उपयोग अधिकार के आवंटन पर प्रावधान (सीएसआरसी की घोषणा संख्या 39)
छ. भूमि नियंत्रण को मजबूत करने से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर राज्य परिषद की सूचना (गुओ फा (2006) संख्या 31)।
ज. पीआरसी संविधान

115. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** चीन सरकार सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(क)(iii) के तात्पर्य से उचित से कम पारिश्रमिक पर भूमि के उपयोग का अधिकार देती है।

116. सीवीडी नियमावली के अनुबंध IV में कहा गया है कि सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी की राशि फर्मों द्वारा वस्तुओं या सेवा के लिए भुगतान की गई कीमत और मौजूदा बाजार स्थितियों के संबंध में उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक के बीच का अंतर होना चाहिए, यदि सरकार को भुगतान की गई कीमत इस राशि से कम है। चूंकि भूमि पर सरकार का एकाधिकार है, इसलिए पर्याप्त पारिश्रमिक को 'सामान्य कीमत' माना जाएगा जिस पर ऐसे भूमि उपयोग अधिकार आमतौर पर अनुबंध IV के पैरा (डी)(iii) के अनुसार सौंपे जाते हैं।

117. चूंकि चीनी सरकार का भूमि पर पूर्ण नियंत्रण है, इसलिए भूमि बेंचमार्क उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर विश्वास करना आवश्यक है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से कॉमन अलॉय एल्युमिनियम शीट पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क आदेश की हाल ही में 2023 में प्रशासनिक समीक्षा में यूएसडीओसी के दृष्टिकोण के अनुरूप, चीन में भूमि के उपयोग के अधिकारों के लिए बेंचमार्क पड़ोसी देशों में तुलनीय वाणिज्यिक भूमि मूल्यों पर आधारित है। थाईलैंड, अपने समान स्तर के आर्थिक विकास, भौगोलिक निकटता और तुलनीय जनसंख्या घनत्व के साथ, एक उपयुक्त बेंचमार्क प्रदान करता है। विशिष्ट बेंचमार्क थाई औद्योगिक सम्पदा, पार्कों और क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि की कीमतों और उस वर्ष के लिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उत्पादक द्वारा भूमि खरीदी गई थी।

    क. दोनों देश उच्च मूल्य वाले उद्योगों (ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन) की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की कीमतें प्रभावित हो रही हैं।
    ख. दोनों देशों में, विदेशी निवेश औद्योगिक भूमि की कीमतों को बढ़ाता है, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में एफडीआई सांद्रता के कारण भूमि की लागत अधिक होती है।
    ग. थाईलैंड का संरचित औद्योगिक विकास मॉडल चीन के मॉडल से काफी मिलता-जुलता है, जिससे इस विशिष्ट संदर्भ में उनके आर्थिक विकास स्तर तुलनीय हो जाते हैं।

118. विशिष्ट बेंचमार्क थाई औद्योगिक एस्टेट, पार्कों और क्षेत्रों में औद्योगिक भूमि की कीमतों और उस वर्ष के लिए प्राप्त किया जाता है जिसमें उत्पादक द्वारा भूमि खरीदी गई थी। घरेलू उद्योग ने 2022 के लिए एक नमूना बेंचमार्क प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण ने उत्पादकों द्वारा भूमि की खरीद के वर्षों के लिए इसी तरह की रिपोर्टों पर भरोसा किया है।

119. ***<u>विशिष्टता:</u>*** के डीओपीपी उत्पादकों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिमान्य कीमत निर्धारण पर भूमि के उपयोग का अधिकार प्राप्त हुआ है।

120. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है।

उचित से कम पारिश्रमिक पर विद्युत का प्रावधान

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

121. अन्य इच्छुक पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम और पता चाइना इलेक्ट्रिक इन्वेस्टमेंट हेनान एनर्जी सेल्स कंपनी लिमिटेड है, जो रूम 611, नंबर 10, हुआंगहे ईस्ट रोड, झेंगडोंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, झेंग्झौ सिटी, हेनान प्रांत, चीन में स्थित है।

ii. जैसा कि <कोयला आधारित बिजली उत्पादन के लिए ऑन-ग्रिड टैरिफ के बाजार-उन्मुख सुधार को और आगे बढ़ाने पर राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के परिपत्र> में उल्लेख किया गया है, बिजली की कीमत बाजार उन्मुख है

iii. कार्यक्रम द्वारा समर्थित गतिविधि को प्रदर्शनी कार्यक्रम-27.c में रिपोर्ट किया गया है। बिजली खरीद के लिए अनुबंध, सीधे बिजली वितरण कंपनी और बिजली खुदरा उपयोगकर्ता यानी कंपनी के बीच हस्ताक्षरित होता है। कीमत एक खुदरा बाजार लेनदेन मूल्य है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

i. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीन में बिजली की कीमतें चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के प्रावधानों के आधार पर प्रांतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और कुछ उद्योगों को तरजीही मूल्य प्रदान करती हैं। यह देखते हुए कि जीओसी द्वारा एल्यूमीनियम प्लेटों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है, यह संभावना है कि पीयूसी के निर्माता अन्य फर्मों और क्षेत्रों की तुलना में तरजीही मूल्य निर्धारण से लाभान्वित हों।

ii. चीन सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ए)(iii) के अर्थ में पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली/बिजली प्रदान करती है।

iii. पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान बाजार को काफी विकृत करता है, और उत्पादकों को सस्ते इनपुट के साथ पीयूसी का उत्पादन करने की अनुमति देता है। सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी की राशि फर्मों द्वारा माल या सेवा के लिए भुगतान की गई कीमत और मौजूदा बाजार स्थितियों के संबंध में उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक के बीच का अंतर होना चाहिए

ग. प्राधिकरण द्वारा जांच

122. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि चीन में बिजली की कीमतें चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग के प्रावधानों के आधार पर प्रांतों द्वारा निर्धारित की जाती हैं और कुछ उद्योगों को तरजीही कीमतें प्रदान करती हैं। इसने निम्नलिखित साक्ष्यों पर भरोसा किया है:

क. बाजार-उन्मुख बिजली लेनदेन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और व्यापार तंत्र को और बेहतर बनाने पर राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग और राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन का परिपत्र, फा गुआ यूं जिंग [2018] संख्या 1027, 16 जुलाई 2018 को जारी किया गया

ख. बिजली प्रणाली के सुधार को और गहरा करने पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद की कई राय (झोंग फा [2015] संख्या 9)

ग. वाणिज्यिक रूप से परिचालन उपयोगकर्ताओं के लिए बिजली उत्पादन और खपत योजना को पूरी तरह से उदार बनाने पर नोटिस (राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग [2019] संख्या 1105)

घ. कार्य और उत्पादन विकास और सुधार मूल्य की बहाली का समर्थन करने के लिए उद्यमों की बिजली की लागत को कम करने पर राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग का परिपत्र [2020] संख्या 258।

123. जीओसी ने यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक एलटीएआर के लिए बिजली के कथित प्रावधान के बारे में प्रश्नावली के पूर्ण उत्तर नहीं दिए हैं कि क्या कार्यक्रम प्रतिसंतुलन योग्य है।

124. चीन में एक सार्वजनिक निकाय, राष्ट्रीय विकास सुधार आयोग (एनडीआरसी) चीन के विभिन्न प्रांतों में लागू बिजली की कीमतें निर्धारित करता है। प्रांतों में स्थानीय मूल्य ब्यूरो केवल एनडीआरसी द्वारा केंद्रीय स्तर पर लिए गए निर्णय के कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करते हैं। एनडीआरसी प्रत्येक प्रांत के लिए टैरिफ निर्धारित करने वाले नोटिस जारी करता है। इन नोटिसों को औपचारिक रूप से स्थानीय मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनाए गए स्थानीय नोटिस में बदल दिया जाता है और स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है

125. बिजली के प्रमुख बड़े औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को ग्रिड से खरीदने के बजाय बिजली उत्पादकों के साथ सीधे खरीद अनुबंध करने की अनुमति है। इस तरह के सीधे अनुबंध

करने की संभावना वर्तमान में सभी बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए खुली नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर, जो उद्यम राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के अनुरूप नहीं हैं और जिनके उत्पाद और प्रक्रियाएँ समाप्त हो गई हैं, उन्हें सीधे लेन-देन में भाग नहीं लेना चाहिए।

126. व्यवहार में, प्रत्यक्ष बिजली व्यापार प्रांतों द्वारा निष्पादित किया जाता है। कंपनियों को प्रत्यक्ष बिजली पायलट योजना में भाग लेने के लिए अनुमोदन के लिए प्रांतीय अधिकारियों के पास आवेदन करना होगा, और उन्हें कुछ मानदंडों को पूरा करना होगा। इसलिए प्राधिकरण नोट करता है कि कार्यक्रम को एनडीआरसी के साथ जीओसी द्वारा प्रशासित किया जाता है।

127. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** चीन की सरकार सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(क)(iii) के तात्पर्य से उचित से कम पारिश्रमिक पर विद्युत/बिजली प्रदान करती है।

128. उचित से कम पारिश्रमिक पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान बाजार को काफी विकृत करता है, और उत्पादकों को अपेक्षाकृत सस्ते इनपुट के साथ विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति देता है। सीवीडी नियमावली में कहा गया है कि सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी की राशि, फर्मों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमत और मौजूदा बाजार स्थितियों के संबंध में उत्पाद या सेवा के लिए उचित पारिश्रमिक के बीच का अंतर होनी चाहिए, यदि सरकार को भुगतान की गई कीमत इस राशि से कम है।

129. प्राधिकारी ने बिजली की कीमत के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क के रूप में संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड (यूएन कॉमट्रेड) आंकड़ों को अपनाया है। यह सिफारिश इस तथ्य पर आधारित है कि यू.एस. वाणिज्य विभाग सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राधिकारियों द्वारा पूर्व जांच में यूएन कॉमट्रेड डेटा को उनकी विश्वसनीयता और सटीकता के लिए निरंतर रूप से मान्यता दी गई है।

130. ***विशिष्टता:*** यह तथ्य पर विचार करते हुए कि एल्युमिनियम प्लेटों के निर्माताओं को चीन की सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, इसकी संभावना है कि अन्य फर्मों और क्षेत्र की तुलना में अधिमान्य कीमत निर्धारण से विचाराधीन उत्पाद के निर्माताओं को लाभ मिलता है।

131. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है।

एलटीएआर पर प्राथमिक एल्युमीनियम/एल्युमीनियम शीट/एल्युमीनियम फॉयल का प्रावधान

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

132. अन्य इच्छुक पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. मूल्य निर्धारण शंघाई नॉन-फेरस एसएमएम ए00 एल्युमिनियम, चांगजियांग स्पॉट ए00 एल्युमिनियम और शंघाई वायदा एल्युमिनियम के संदर्भ मूल्य निर्धारण पर आधारित है। संदर्भ मूल्य निर्धारण के निर्धारण में हमारी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संदर्भ मूल्य निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएमएम ए00 एल्युमिनियम, चांगजियांग स्पॉट ए00 एल्युमिनियम और शंघाई वायदा एल्युमिनियम लंदन मेटल एक्सचेंज जैसे मात्र ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं और ट्रेडिंग की पद्धति भी समान है। अनिवार्य रूप से, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आदि की तरह काम करते हैं और वस्तुओं की कीमत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित / नियंत्रित नहीं करते हैं।

ii. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि निर्यात कर अपने आप में सब्सिडी नहीं है। यदि ऐसा होता तो जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि निर्यात कर को केवल सब्सिडी माना जाता।

iii. एलटीएआर पर माल के सरकारी-सौंपे गए/निर्देशित प्रावधान के रूप में निर्यात कर/प्रतिबंध का उपचार डब्ल्यूटीओ-असंगत है क्योंकि सरकार द्वारा "वित्तीय योगदान" के अस्तित्व की कमी है।

iv. कनाडा - विमान (डीएस 70), चीन - विभिन्न कच्चे माल के निर्यात से संबंधित उपाय (डीएस 394, डीएस 395, डीएस 398) के मामलों में अपीलीय निकाय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है।

v. एससीएम समझौते का अनुच्छेद 1.1 जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 में कथित रूप से स्थानांतरित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि यदि सरकार द्वारा वित्तीय योगदान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता को लाभ होता है, तो सब्सिडी मौजूद होती है।

vi. इसके अतिरिक्त, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.2 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 के अनुसार, सब्सिडी का प्रतिकार तभी किया जा सकता है, जब वह "विशिष्ट" हो।

vii. अमेरिका में - निर्यात प्रतिबंध, उस मामले में पैनल ने विशेष रूप से "वित्तीय योगदान" के निर्धारण के लिए प्रभाव-आधारित दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और माना कि "वित्तीय योगदान की धारणा को पेश करके, मसौदा तैयार करने वालों ने किसी भी सरकारी कार्रवाई के उपचार की संभावना को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी के रूप में लाभ हुआ।" इसके अतिरिक्त, पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि "ऐसा नहीं हो सकता है कि एससीएम समझौते के तहत किसी सदस्य सरकार के उपाय की प्रकृति को केवल उन लोगों द्वारा उस उपाय पर प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाए, जो इससे प्रभावित होते हैं। इसके बजाय, सरकार द्वारा वित्तीय योगदान का अस्तित्व सरकार की कार्रवाई के संदर्भ में साबित होना चाहिए।" बाद के प्रस्ताव को कनाडा - एयरक्राफ्ट में एबी द्वारा आगे भी बरकरार रखा गया था।

viii. वर्तमान मामले में, आवेदक उद्योग प्रभाव-आधारित दृष्टिकोण यानी निर्यात कर लगाने के अनुसार वित्तीय योगदान के अस्तित्व को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, एल.टी.ए.आर. पर एल्युमीनियम शीट के सरकारी सौंपे गए या निर्देशित प्रावधान के आवेदक उद्योग के दावे का आधार डब्ल्यू.टी.ओ. विवाद यू.एस. - निर्यात प्रतिबंध में यू.एस. के समान ही है, जिसे उस विवाद में पैनल द्वारा खारिज कर दिया गया था।

ix. यह प्रस्तुत किया गया है कि यू.एस. - डी.आर.ए.एम. (सी.वी.डी.) में ए.बी. ने उल्लेख किया है कि "एस.सी.एम. समझौते का अनुच्छेद 1.1 (ए) (1) स्पष्ट करता है कि सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा "वित्तीय योगदान" एस.सी.एम. समझौते के तहत "सब्सिडी" का एक अनिवार्य घटक है। अनुच्छेद 1.1 (ए) (1) के तहत किसी भी उत्पाद को सब्सिडी प्राप्त नहीं पाया जा सकता है, न ही सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान की अनुपस्थिति में इसे प्रतिपूरक माना जा सकता है।"

x. जैसा कि प्रदर्शित किया गया है, वर्तमान मामले में इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है। आवेदक उद्योग सौंपे जाने या निर्देश की आवश्यकता के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा है।

xi. यू.एस. - डी.आर.ए.एम. (सी.वी.डी.) में ए.बी. ने माना कि "पैराग्राफ (iv) के अनुसार, "सौंपा" तब होता है जब सरकार किसी निजी निकाय को जिम्मेदारी देती है, और "निर्देश" उन स्थितियों को संदर्भित करता है, जहाँ सरकार किसी निजी निकाय पर अपने अधिकार का प्रयोग करती है।" इसलिए, सौंपना और

निर्देश दो अलग-अलग तरीके या तरीके प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से सरकार "वित्तीय योगदान" को प्रभावी बनाने के लिए एक निजी निकाय का उपयोग करती है और दो परस्पर अनन्य और अलग-अलग कानूनी निर्धारण करती है।

xii. आवेदक उद्योग कथित निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग उद्योग को कोई नीतिगत समर्थन प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एल.टी.ए.आर. में एल्युमिनियम शीट का प्रावधान होता है।

xiii. यू.एस. - निर्यात प्रतिबंधों में पैनल ने नोट किया कि "प्रतिनिधिमंडल" या "आदेश" की धारणा में तीन तत्व शामिल हैं: *"(i) एक स्पष्ट और सकारात्मक कार्रवाई, चाहे वह प्रतिनिधिमंडल हो या आदेश; (ii) किसी विशेष पक्ष को संबोधित; और (iii) जिस कार्रवाई का उद्देश्य एक विशेष कार्य या उद्देश्य है।"*[1] यू.एस. - डी.आर.ए.एम. (सी.वी.डी.) में ए.बी. ने माना कि सौंपने को केवल प्रतिनिधिमंडल और निर्देश को कमांड तक सीमित करना संकीर्ण है, लेकिन इसने इन मानदंडों को खारिज नहीं किया। यू.एस. - ए.डी. और सी.वी.डी. के बाद के मामले में, ए.बी. ने इस धारणा को स्पष्ट किया कि सौंपने और निर्देश देने में एक निजी निकाय पर प्रभावी नियंत्रण या जिम्मेदारी का प्रतिनिधिमंडल शामिल है।

xiv. इस प्रकार, किसी विशेष पक्ष को संबोधित सरकार द्वारा सकारात्मक कार्रवाई के लिए अभी भी सबूत प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और जिस कार्रवाई का उद्देश्य यूएस-निर्यात प्रतिबंध पैनल द्वारा उल्लिखित एक विशेष कार्य या उद्देश्य है। वास्तव में, यूएस-डीआरएएम (सीवीडी) में एबी यूएस-निर्यात प्रतिबंध पैनल के साथ सहमत था कि एक निजी निकाय को जिम्मेदारी देने या उस पर अधिकार जताने वाली सरकार की ओर से कुछ सकारात्मक कार्रवाई आवश्यक है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति निजी निकाय को सौंपने या निर्देश देने में किसी प्रकार की धमकी या प्रलोभन की अपेक्षा कर सकता है, जो बदले में सौंपने या निर्देश के सबूत के रूप में काम कर सकता है।"

xv. इसके अलावा, यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि *यूएस-डीआरएएम (सीवीडी) में एबी के अनुसार, ""सौंपना"" शब्द किसी कार्य या वस्तु के लिए किसी को जिम्मेदारी देने की कार्रवाई को दर्शाता है" और निर्देश के लिए कि "पैराग्राफ (iv) के तहत निजी निकाय को एक कार्य "करने" के लिए निर्देशित*

[1] अमेरिका—निर्यात प्रतिबंध, पैनल रिपोर्ट, पैरा 8.29.

किया जाता है, अधिकार की धारणा को रेखांकित करता है"।[2] इस प्रकार, जबकि यह निर्विवाद है कि अधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार की ओर से एक सकारात्मक कार्रवाई मौजूद होनी चाहिए, जिम्मेदारी देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अतिरिक्त कदमों को प्रदर्शित करने की जरूरत है जो निर्यात प्रतिबंधों के मामले में महज नीति घोषणा से परे हैं। यह आकलन यूएस-डीआरएएम (सीवीडी) में पैनल के निर्धारण द्वारा समर्थित है।

xvi. इसके अतिरिक्त, यूएस-डीआरएएम (सीवीडी) में एबी ने यूएस-निर्यात प्रतिबंध पैनल के इस आकलन के पीछे के तर्क का भी समर्थन किया कि लाभ प्रदान करने में सक्षम सभी सरकारी उपाय एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.1(ए) के दायरे में नहीं आते हैं और ऐसी स्थिति जिसमें सरकार किसी तरह से बाजार में हस्तक्षेप करती है, जिसका केवल दी गई तथ्यात्मक परिस्थितियों और उस बाजार में अभिनेताओं द्वारा स्वतंत्र विकल्प के प्रयोग के आधार पर कोई विशेष परिणाम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वह वित्तीय योगदान नहीं है।

xvii. वास्तव में, निजी निकायों को सौंपने या निर्देश देने वाले किसी भी सकारात्मक कार्य की अनुपस्थिति का अर्थ यह होगा कि किसी भी वृहद आर्थिक नीति को सौंपना या निर्देश माना जा सकता है और किसी भी सरकारी नीति के परिणामस्वरूप लाभ को वित्तीय योगदान के बराबर माना जा सकता है, जिसे एबी ने ठीक उसी तरह रेखांकित किया है जैसा कि ऐसा नहीं होना चाहिए।[3]

xviii. पूर्वगामी के आधार पर, यह स्पष्ट है कि यूएस - डीआरएएम (सीवीडी) में एबी ने न तो यूएस - निर्यात प्रतिबंध पैनल द्वारा निर्धारित तीन लंबी आवश्यकताओं को खारिज किया और न ही जांच अधिकारियों को यह पता लगाने की अनुमति देने के लिए मानदंडों को ढीला किया कि सरकार का निर्यात प्रतिबंध या अन्य समान नीति उपाय सौंपने या निर्देश देने के बराबर है। वास्तव में, यूएस - डीआरएएम (सीवीडी) में, जैसा कि एबी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिम्मेदारी देने या अधिकार का प्रयोग करने वाली कुछ सकारात्मक कार्रवाई सरकार की ओर से मौजूद होनी चाहिए, इसका तार्किक रूप से यह भी अर्थ है, जैसा उत्तरदाताओं के विचार में, यह सकारात्मक कार्रवाई से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और इसके अभाव में, सरकार और एक निजी निकाय के आचरण के बीच अपेक्षित संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है।

---

[2] यूएस-डीआरएएम (सीवीडी), एबी रिपोर्ट, पैरा. 108-113.

[3] यूएस - डीआरएएम (सीवीडी), एबी रिपोर्ट, पैरा. 296.

xix. निजी निकायों को सौंपने या निर्देश देने की स्थापना के लिए लागू कानूनी मानकों की इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, उत्तरदाताओं ने नोट किया कि आवेदक उद्योग ने यूएस-निर्यात प्रतिबंध पैनल द्वारा रेखांकित और एबी द्वारा समर्थित तीन तत्वों में से किसी को भी स्थापित नहीं किया है।

xx. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स उद्योग को समर्थन प्रदान करने के लिए चीन पीआर सरकार की कोई नीति नहीं है।

xxi. जैसा कि यूएस-डीआरएएम (सीवीडी) में पैनल द्वारा उल्लेख किया गया है, "सामान्यीकृत इच्छा की अभिव्यक्ति प्रतिनिधिमंडल या आदेश के सकारात्मक कार्य के बराबर नहीं है।"

xxii. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, यह नोट किया जाता है कि आवेदक उद्योग चीनी सरकार की कोई नीति प्रदान करने में सक्षम नहीं है, जिसमें कहा गया है कि निर्यात कर विषय वस्तुओं के उत्पादकों को सब्सिडी देने के लिए लगाया जाता है।

xxiii. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उद्योग चीन पीआर में एल्युमीनियम शीट्स के निर्यात प्रतिबंधों और कीमतों के बीच संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। इसके अलावा, आवेदक उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि चीन पीआर की सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात कर ने एल्युमीनियम शीट्स के चीनी उत्पादकों को चीनी बाजार में अपनी उपज एलटीएआर पर बेचने के लिए मजबूर किया या उनकी कीमतें तय करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया।

xxiv. उपरोक्त के मद्देनजर, यह प्रस्तुत किया गया है कि एल्युमीनियम शीट्स (एलटीएआर) का कथित सब्सिडीकरण भारतीय कानून के साथ-साथ सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौते के तहत प्रतिपूरक नहीं है।

xxv. सब्सिडी मार्जिन और क्षति का मूल्यांकन मासिक आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि एल्युमीनियम, एक प्रमुख कच्चा माल की कीमत में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

xxvi. लकी और कोडक असंबंधित आपूर्तिकर्ताओं से एल्युमीनियम कॉइल खरीदते हैं

ख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

i. फुजीफिल्म का तर्क है कि वह शंघाई नॉन-फेरस एसएमएम और शंघाई वायदा एल्यूमीनियम जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से संदर्भ मूल्य निर्धारण पर भरोसा करते

हुए असंबंधित निजी आपूर्तिकर्ताओं से हाथ की लंबाई की कीमतों पर एल्यूमीनियम खरीदता है, जिसके बारे में उसका दावा है कि वे बाजार की ताकतों द्वारा शासित हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग का तर्क है कि यह दावा चीन सरकार (जीओसी) के नियामक हस्तक्षेपों के कारण होने वाली व्यापक बाजार विकृतियों को नजरअंदाज करता है।

ii. जीओसी के निर्यात प्रतिबंध, जैसे कि प्राथमिक एल्यूमीनियम पर 30% निर्यात शुल्क और अपूर्ण वैट छूट, कृत्रिम रूप से घरेलू एल्यूमीनियम की कीमतों को दबाते हैं, जिससे फुजीफिल्म जैसे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को फायदा होता है। यहां तक कि निजी आपूर्तिकर्ता भी इन राज्य समर्थित उपायों से प्रभावित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फुजीफिल्म के इस दावे के बावजूद कि उसके आपूर्तिकर्ता स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, एल्यूमीनियम की आपूर्ति बाजार से नीचे की दरों (एलटीएआर) पर होती है।

iii. घरेलू उद्योग ने आगे कहा कि जीओसी द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध एससीएम समझौते के तहत वित्तीय योगदान के रूप में योग्य हैं, क्योंकि उनमें सकारात्मक सरकारी कार्रवाई शामिल है जो एल्युमीनियम बाजार को विकृत करती है। ये उपाय निर्यात को प्रतिबंधित करते हैं, घरेलू अधिशेष बनाते हैं, और कीमतों को दबाते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम उद्योगों को अप्रत्यक्ष लाभ मिलता है। निर्यात करों और अपूर्ण वैट छूट सहित जीओसी की कार्रवाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है कि प्राथमिक एल्युमीनियम घरेलू उद्योगों के लिए कम लागत पर उपलब्ध रहे।

iv. ये उपाय एससीएम समझौते में उल्लिखित "सौंपने या निर्देश" के मानदंडों को पूरा करते हैं, जहां सरकार निजी अभिनेताओं को औद्योगिक नीति उद्देश्यों के साथ संरेखित तरीके से व्यवहार करने का निर्देश देती है।

v. घरेलू उद्योग ने यह भी रेखांकित किया कि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना सहित ऐतिहासिक दृष्टिकोण, इन हस्तक्षेपों द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय लाभ को प्रदर्शित करते हैं, जो इस तर्क का समर्थन करते हैं कि जीओसी की कार्रवाइयां प्रतिपूरक सब्सिडी हैं जो प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं।

ग. प्राधिकरण द्वारा जांच

133. घरेलू उद्योग ने कहा है कि चीन में प्राथमिक एल्युमीनियम के अधिकांश उत्पादक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम हैं। उल्लेखनीय रूप से, जीओसी इन संस्थाओं पर

सार्थक नियंत्रण रखता है और समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, संसाधनों का आवंटन करने और राज्य क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को बनाए रखने के अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करता है। चीन अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले प्राथमिक एल्युमीनियम का 99 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है, और घरेलू खपत का लगभग 37 प्रतिशत राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों से आता है।

134. जीओसी ने प्राथमिक एल्युमीनियम पर 30 प्रतिशत निर्यात प्रशुल्क लगाया है। इस तरह के निर्यात प्रतिबंध वस्तु के निर्यात को हतोत्साहित करते हैं, इस प्रकार, घरेलू बाजार में प्राथमिक एल्युमीनियम की आपूर्ति कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है और घरेलू कीमतें कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त, निर्यातकों के लिए वैट की अपूर्ण छूट चीन द्वारा कुछ उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशिष्ट उपाय है। चीन स्थित निर्यातक वैट छूट के लिए पात्र हो सकते हैं जो उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पाद के आधार पर शून्य से लेकर सामान्य 17% वैट दर की पूर्ण वापसी तक हो सकती है। प्राथमिक एल्युमीनियम के निर्यात इस अवधि में शून्य या लगभग शून्य छूट के हकदार हैं।

135. परिणामस्वरूप, प्राथमिक एल्युमीनियम के लिए घरेलू बाजार जीओसी के हस्तक्षेप के माध्यम से विकृत हो गया है, और डीओपीपी के चीन के उत्पादकों को उचित से कम पारिश्रमिक पर प्रदान की जाती है।

136. इस तर्क के संबंध में कि चूंकि एल्युमीनियम निजी आपूर्तिकर्ताओं से खरीदा जाता है, न कि सरकार से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन की सरकार अपने विनियामक तंत्र (जैसा कि पिछले खंडों में बताया गया है) के माध्यम से डाउनस्ट्रीम उद्योगों को सस्ती कीमत पर प्राथमिक एल्युमीनियम प्रदान करने के लिए निजी निकायों पर अपने अधिकार का प्रयोग करती है। विशेष रूप से, जीओसी द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध, जैसे कि प्राथमिक एल्युमीनियम पर 30% टैरिफ और एल्युमीनियम निर्यात के लिए अपूर्ण मूल्य वर्धित कर छूट, चीन में एल्युमीनियम बाजार को काफी हद तक विकृत करते हैं। प्राथमिक एल्युमीनियम के लिए घरेलू कीमतों पर कृत्रिम दबाव बनाकर, ये उपाय विचाराधीन उत्पाद के डाउनस्ट्रीम निर्माताओं को एल्युमीनियम एलटीएआर पर प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप, निजी आपूर्तिकर्ता भी इन राज्य समर्थित उपायों से लाभान्वित होते हैं।

137. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** कुछ निर्यात प्रतिबंध सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के तात्पर्य से वित्तीय योगदान होता है, क्योंकि वे निधियों का अप्रत्यक्ष अंतरण हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से *"संतृप्त वसायुक्त अल्कोहल" और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से "निरंतर कास्ट कॉपर वायर रॉड्स"* जैसे विभिन्न उत्पादों से संबंधित जांच में प्राधिकारी द्वारा इस स्थिति की पुष्टि की गई है।

138. डब्ल्यूटीओ पैनल और अपीलीय निकाय ने *यूएस-निर्यात प्रतिबंध*[4] और *यूएस-*डीआरएएम *(सीवीडी)*[5] जैसे मामलों में सौंपने और निर्देश के लिए कानूनी मानक को स्पष्ट किया है।

क. सौंपने में सरकार द्वारा किसी निजी निकाय को कोई विशिष्ट कार्य करने की जिम्मेदारी देना शामिल है।

ख. निर्देश का अर्थ है सरकार द्वारा किसी निजी निकाय पर अपने अधिकार का प्रयोग करके उसे कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए बाध्य करना।

ग. सरकार की कार्रवाइयां सामान्य नियामक शक्तियों से परे होनी चाहिए और इसमें सकारात्मक कार्य शामिल होने चाहिए जो सरकार के हस्तक्षेप और निजी उद्यमों के व्यवहार के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं।

घ. सौंपने या निर्देश के साक्ष्य में स्पष्ट आदेश, प्रलोभन या अंतर्निहित तंत्र शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि सरकार की कार्रवाइयों और निजी संस्थाओं के परिणामी आचरण के बीच एक स्पष्ट संबंध हो।

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जीओसी के निर्यात प्रतिबंध सकारात्मक सरकारी कार्रवाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उपाय एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अर्थात, घरेलू डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए कम लागत वाले प्राथमिक एल्युमीनियम की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जीओसी या चीन के अन्य उत्पादकों द्वारा इसके विपरीत कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

140. प्राधिकारी ने एल्युमीनियम की कीमत के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क के रूप में संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड (यूएन कॉमट्रेड) आंकड़ों को अपनाया है। यह सिफारिश इस तथ्य पर आधारित है कि यू.एस. वाणिज्य विभाग (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से कॉमन

[4] संयुक्त राज्य अमेरिका में पैनल रिपोर्ट - निर्यात प्रतिबंधों को सब्सिडी के रूप में मानने के उपाय (डब्ल्यूटी/डीएस194/आर)।

[5] संयुक्त राज्य अमेरिका में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट - कोरिया से डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी सेमीकंडक्टर्स (ड्रम) पर प्रतिपूरक शुल्क जांच (डब्ल्यूटी/डीएस296/एबी/आर)।

अलॉय एल्युमीनियम शीट पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की 2023 में प्रशासनिक समीक्षा में संदर्भित) सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राधिकारियों द्वारा पूर्व जांच में यूएन कॉमट्रेड डेटा को उनकी विश्वसनीयता और सटीकता के लिए निरंतर रूप से मान्यता दी गई है। यूएन कॉमट्रेड फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) आधार पर निर्यात कीमतों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जिसमें एल्युमीनियम की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इन आंकड़ों की विस्तृत प्रकृति, जिसमें प्रत्येक देश से वैश्विक बाजार में निर्यात की कुल मात्रा और मूल्य शामिल है।

141. ***विशिष्टता:*** सब्सिडी उन फर्मों को प्रदान की जाती है जो कच्चे माल के रूप में प्राथमिक एल्यूमीनियम/एल्यूमीनियम शीट/एल्यूमीनियम फॉयल का उपयोग करते हैं, और इस प्रकार, यह सीवीडी नियमों के नियमावली के नियम 11 और अनुबंध II के तात्पर्य से विशिष्ट है।

142. उपर्युक्त के आधार पर, प्राधिकारी यह पाते हैं कि यह कार्यक्रम सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारणीय सब्सिडी है।

सब्सिडी मार्जिन की गणना

143. सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के प्रावधान के संबंध में सब्सिडी की राशि फर्मों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की गई कीमत और मौजूदा बाजार स्थितियों के संबंध में उत्पाद या सेवा के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक के बीच का अंतर होना चाहिए, यदि सरकार को भुगतान की गई कीमत इस राशि से कम है। गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए, प्राधिकरण ने अन्य सहयोगी उत्पादकों के लिए गणना किए गए मार्जिन सहित उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

क्र. सं.	**उत्पादक**	**वस्तुएं/सेवाएं**	**सब्सिडी मार्जिन**
1	कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	एल्युमिनियम	0-10%
		विद्युत	0-10%
2	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	एल्युमिनियम	20-30%
		ऋण	0-10%
		भूमि	0-10%

		विद्युत	0-10%
3	फ़ुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड	एल्युमिनियम शीट	0-10%
		एल्युमिनिमय फॉयल	10-20%
		विद्युत	0-10%
4	हुआंगशान जिनरुइटाई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	प्राथमिक एल्युमिनियम	0-10%
		विद्युत	0-10%
5	चोंग्किंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड	प्राथमिक एल्युमिनियम	0-10%
		विद्युत	10-20%
		भूमि	0-10%
6	अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल	एल्युमिनियम	0-10%
		भूमि	20-30%
		ऋण	0-10%
7	अन्य सभी उत्पादक	एल्युमिनियम	0-10%
		विद्युत	20-30%
		भूमि	0-10%
		ऋण	0-10%
		एल्युमिनियम शीट	0-10%
		एल्युमिनिमय फॉयल	10-20%

<u>करों</u>

अनुसंधान एवं विकास व्यय की अधिमान्य कर-पूर्व कटौती

घ. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

144. अन्य इच्छुक पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. कार्यक्रम के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एजेंसी का नाम और पता ज़ियामेन हैकांग जिला कर ब्यूरो है, पता है नंबर 7 बिन्हू नॉर्थ रोड, हैकांग जिला, ज़ियामेन, फ़ुज़ियान प्रांत, चीन।

ii. उद्यम आयकर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कानून के अनुच्छेद 30 के अनुसार, नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादों और नई तकनीकों के विकास में उद्यमों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास व्यय, कर योग्य आय की गणना के समय अतिरिक्त रूप से काटे जा सकते हैं

iii. आवेदन पत्र वार्षिक उद्यम आयकर घोषणा पत्र है जिसे कर रिपोर्टिंग प्रणाली से डाउनलोड किया जाता है। चूंकि कंपनी इन प्रपत्रों को कर ब्यूरो के पास जमा करती है, इसलिए इसे सत्यापित और अनुमोदित किया जाता है। इस प्रकार, उपरोक्त कार्यक्रम के लिए कोई विशिष्ट अनुमोदन दस्तावेज़ नहीं है।

ङ. प्राधिकरण द्वारा जांच

145. कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन द्वारा प्रशासित है और पीआरसी के कॉर्पोरेट आयकर कानून के अनुच्छेद 30.1, उद्यम आयकर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कानून के कार्यान्वयन के लिए विनियमों के अनुच्छेद 95 और अनुसंधान और विकास व्यय के लिए प्रीटैक्स सुपर कटौती नीति में और सुधार करने पर वित्त मंत्रालय और कराधान के राज्य प्रशासन की घोषणा, घोषणा संख्या 7 (2023) के तहत शासित है।

146. इस कार्यक्रम के तहत, कॉर्पोरेट आयकर कानून के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 30.1 के अनुसार, उद्यमों और अन्य संगठनों के संबंध में जिनकी आय है, वे उद्यम आयकर के भुगतानकर्ता होंगे और नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादों और नई तकनीकों के अनुसंधान और विकास से संबंधित खर्चों की कटौती के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन के लिए विनियमों के अनुच्छेद 95 के अनुसार, उद्यम आयकर कानून के अनुच्छेद 30 (1) में उल्लिखित अनुसंधान और विकास व्यय की कटौती, अमूर्त संपत्ति बनाए बिना नई प्रौद्योगिकियों, नए उत्पादों और नई प्रक्रियाओं के विकास के लिए उद्यमों द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास व्यय को संदर्भित करती है।

147. यह कार्यक्रम उद्यमों को नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास में किए गए अनुसंधान व्यय में कटौती करने की अनुमति देता है। यदि पात्र अनुसंधान व्यय "अमूर्त संपत्ति मूल्य का हिस्सा नहीं बनते हैं," तो प्राप्तकर्ता वास्तविक उपार्जित राशि के ऊपर कर योग्य आय से अतिरिक्त 50% कटौती ले सकता है। जहां ये व्यय

कुछ अमूर्त संपत्तियों का मूल्य बनाते हैं, प्राप्तकर्ता अमूर्त संपत्तियों की लागत के 150% के आधार पर व्यय का परिशोधन कर सकता है।

148. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित साक्ष्य पर भरोसा किया है:

क. ईआईटी कानून का अनुच्छेद 30(1)
ख. पीआरसी के उद्यम आयकर कानून के कार्यान्वयन नियमों का अनुच्छेद 95
ग. वित्त मंत्रालय परिपत्र कै शुई संख्या 119, 2015
घ. वित्त मंत्रालय परिपत्र कै शुई संख्या 34, 2017
ङ. वित्त मंत्रालय परिपत्र कै शुई संख्या 64, 2018
च. वित्त मंत्रालय परिपत्र कै शुई संख्या 99, 2018

149. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** चीन सरकार इस कार्यक्रम के तहत कर कटौती प्रदान करती है। कर लाभ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ii) के अर्थ में वित्तीय योगदान का गठन करते हैं क्योंकि कर कटौती सरकारी राजस्व के रूप में होती है। सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि जांच अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि और कर की सामान्य दर पर भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर होना चाहिए।

150. ***विशिष्टता:*** सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सी.वी.डी. नियमों के नियम 11 और अनुलग्नक II के भाग के पैराग्राफ 1(ए) के अनुसार, कर कटौती सीमित है क्योंकि यह पात्र उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास तक सीमित है।

151. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण पाता है कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के तहत एक प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडी है।

<u>उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यम के लिए उद्यम आयकर विशेषाधिकार</u>

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियाँ

152. अन्य इच्छुक पक्षों ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

i. इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए, किसी उद्यम को उच्च तकनीक उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है। उच्च तकनीक उद्यम होने के लिए, किसी उद्यम को विभिन्न शर्तों को पूरा करना होता है।

ii. यह कार्यक्रम प्रतिपूरक सब्सिडी नहीं है क्योंकि यह निर्यात प्रदर्शन, आयातित वस्तुओं की तुलना में घरेलू उपयोग, निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित होना, विशिष्ट होना या किसी अन्य मानदंड पर निर्भर नहीं है।

ख. प्राधिकरण द्वारा जांच

153. आवेदक और चीन पीआर में प्रतिवादी निर्माता/निर्यातक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, यह देखा गया है कि, इस कार्यक्रम के अंतर्गत, उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यम के प्रमाण पत्र के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करने वाली कंपनी को 25% की सामान्य दर की तुलना में 15% की कम आयकर दर का लाभ मिलता है। उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यम के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, किसी उद्यम को उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्यमों के निर्धारण के लिए प्रशासनिक उपायों के अनुच्छेद 10 में उल्लिखित विभिन्न शर्तों को पूरा करना होता है। कई एल्युमीनियम उत्पादों की पहचान उच्च एवं नवीन प्रौद्योगिकी उत्पादों के रूप में की गई है।

154. कार्यक्रम के साक्ष्य के रूप में, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित पर भरोसा किया है:

- उद्यम आयकर पर पीआरसी कानून का अनुच्छेद 28 (2007)।
- उद्यम आयकर पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कानून के कार्यान्वयन के लिए विनियम (2007)।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन की ओर से उच्च तकनीक उद्यमों की पहचान के लिए प्रशासनिक उपायों के संशोधन और जारी करने पर सूचना" (गुओकेफाहुओ [2016] संख्या 32)

155. कार्यक्रम का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राज्य कराधान प्रशासन द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि इस कार्यक्रम की पहले नामित प्राधिकरण और कुछ अन्य जांच प्राधिकरणों द्वारा जांच की गई है और इसे प्रतिसंतुलन योग्य पाया गया है।

156. ***वित्तीय योगदान और लाभ:*** चीन सरकार इस कार्यक्रम के तहत कर में कटौती प्रदान करती है। कर लाभ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ii) के अर्थ

के भीतर एक वित्तीय योगदान का गठन करते हैं क्योंकि कर कटौती सरकारी राजस्व के रूप में होती है। सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि जांच अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा वास्तव में भुगतान किए गए कर की राशि और कर की सामान्य दर पर भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर होनी चाहिए।

157. ***विशिष्टता:*** चूंकि कार्यक्रम के तहत लाभ कुछ विशेष प्रकार के उद्यमों तक सीमित है, इसलिए यह कार्यक्रम सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3) के अर्थ में विशिष्ट है, सीवीडी नियमों का नियम 11।

158. उपरोक्त के आधार पर, प्राधिकरण पाता है कि यह कार्यक्रम सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 के तहत एक प्रतिपूरक सब्सिडी है।

सब्सिडी मार्जिन की गणना

159. सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि कर सब्सिडी के आधार पर, सब्सिडी की राशि जांच अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा वास्तव में भुगतान की गई कर राशि और कर की सामान्य दर पर भुगतान की गई राशि के बीच का अंतर होनी चाहिए। गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए, प्राधिकरण ने अन्य सहयोगी उत्पादकों के लिए गणना किए गए मार्जिन सहित उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है।

क्र. सं.	**उत्पादक**	**अनुदान के लिए उत्पादक सब्सिडी मार्जिन**
1	कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	0-10%
2	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कं., लिमिटेड	शून्य
3	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं., लिमिटेड	शून्य
4	हुआंगशान जिनरुइताई न्यू मटेरियल कं. लिमिटेड	0-10%
5	अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल	शून्य
6	चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कं., लिमिटेड	शून्य

7	अन्य सभी उत्पादक	0-10%

<u>ताइवान</u>

160. घरेलू उद्योग ने ताइवान में विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व, संचालन और प्रतिसंतुलन के बारे में पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें नीति अधिसूचनाएं, सार्वजनिक दस्तावेज, डब्ल्यूटीओ सब्सिडी अधिसूचनाएं और अन्य अधिकार क्षेत्रों में जांच अधिकारियों द्वारा प्रतिसंतुलन शुल्क निर्धारण शामिल हैं।

161. ताइवान सरकार ने विषयगत जांच में विधिवत भाग लिया है और प्रश्नावली तथा अन्य कानूनी प्रस्तुतियों पर उसके जवाब को ध्यान में रखा गया है। प्राधिकरण ने नोट किया है कि ताइवान सरकार ने जांच अवधि के दौरान कुछ कार्यक्रमों के अस्तित्व की पुष्टि की है।

162. ताइवान सरकार ने प्रस्तुत किया है कि निम्नलिखित कार्यक्रम समाप्त हो गए हैं:

i. नए उभरते, महत्वपूर्ण और रणनीतिक उद्योगों में निवेश के लिए शेयरधारक का निवेश कर क्रेडिट
ii. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भागीदारी के लिए शेयरधारक का निवेश कर क्रेडिट

163. इसने यह भी कहा है कि ताइवान में डीओपीपी के निर्माता टॉप हाई इमेज कॉर्प ने इन कार्यक्रमों के तहत कोई लाभ नहीं उठाया है। हालाँकि, ताइवान के किसी भी उत्पादक ने विषयगत जाँच में भाग नहीं लिया है।

164. तदनुसार, प्राधिकरण ताइवान के उत्पादकों द्वारा कथित तौर पर प्राप्त लाभों के लिए उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा कर रहा है। विशेष रूप से, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 25 के तहत ताइवान सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ को अधिसूचित सब्सिडी का प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया गया है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा कथित किसी अन्य कार्यक्रम की प्रतिसंतुलनशीलता का मूल्यांकन नहीं किया है।

इन-ज़ोन उद्यमों के लिए शुल्क और कर छूट

165. घरेलू उद्योग ने कहा है कि सभी 'इन-ज़ोन' उद्यम उद्योग कुछ छूट के हकदार हैं । ताइवान सरकार ने इस कार्यक्रम के अस्तित्व की पुष्टि की है।

166. क्षेत्र के उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों को जब देय क्षेत्रों में भेजा जाएगा तो उन पर सीमा शुल्क, वस्तु कर और व्यवसाय कर लागू होंगे।

167. ताइवान के अधिकारी इस कार्यक्रम के तहत कर की दर में कमी प्रदान करते हैं। कर लाभ सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ii) के अर्थ में वित्तीय योगदान का गठन करते हैं क्योंकि कर में कमी सरकारी राजस्व के परित्याग के रूप में होती है।

168. अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि कर की वह राशि होनी चाहिए जो प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा जांच अवधि के दौरान मानक लागू कर दर पर देय होती।

169. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमों के नियम 11 और अनुलग्नक III के भाग के पैराग्राफ (ए) के अनुसार, सब्सिडी का प्रावधान 'इन-जोन' क्षेत्रों में स्थित उद्यमों तक सीमित है।

170. घरेलू उद्योग ने गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए 3.3% प्रतिशत का सब्सिडी मार्जिन प्रस्तावित किया है। इसने 2023 के लिए ताइवान सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ अधिसूचना पर भरोसा किया है। सब्सिडी मार्जिन का अनुमान अनुदान की कुल राशि को कुल निर्यात मूल्य से विभाजित करके लगाया जाता है। चूंकि किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई अन्य प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकरण गैर-सहयोगी उत्पादकों को यह मार्जिन प्रदान करना उचित समझता है।

उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए शुल्क और कर छूट

171. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि यह कार्यक्रम औद्योगिक प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। "विज्ञान पार्क" की स्थापना परिष्कृत उद्योगों और उन्नत तकनीकी पृष्ठभूमि वाले कर्मियों को निर्दिष्ट क्षेत्र में लाकर की गई है। सभी पार्क उद्यम आयातित मशीनरी और उपकरण, कच्चे माल, वस्तुओं, ईंधन और अर्ध-तैयार उत्पादों पर सीमा शुल्क, वस्तु कर और व्यापार कर से छूट के हकदार हैं। इस कार्यक्रम के अस्तित्व की पुष्टि ताइवान सरकार द्वारा की गई है।

172. ताइवान के अधिकारी इस कार्यक्रम के तहत कर की दर में कमी प्रदान करते हैं। कर लाभ सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ii) के अर्थ में वित्तीय योगदान का गठन करते हैं क्योंकि कर में कमी सरकारी राजस्व के परित्याग के रूप में होती है।

173. सी.वी.डी. नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि सब्सिडी की राशि कर की वह राशि होनी चाहिए जो प्राप्तकर्ता कंपनी द्वारा जांच अवधि के दौरान मानक लागू कर दर पर देय होती।

174. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमों के नियम 11 और अनुलग्नक III के भाग के पैराग्राफ (ए) के अनुसार, सब्सिडी का प्रावधान विज्ञान पार्कों में स्थित 'उच्च प्रौद्योगिकी' उद्यमों तक सीमित है।

175. घरेलू उद्योग ने गैर-सहयोगी उत्पादकों के लिए 3.63% प्रतिशत का सब्सिडी मार्जिन प्रस्तावित किया है। इसने 2023 के लिए ताइवान सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ अधिसूचना पर भरोसा किया है। सब्सिडी मार्जिन का अनुमान अनुदान की कुल राशि को कुल निर्यात मूल्य से विभाजित करके लगाया जाता है। चूंकि किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई अन्य प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकरण गैर-सहयोगी उत्पादकों को यह मार्जिन प्रदान करना उचित समझता है।

कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान; पारंपरिक उद्योग प्रौद्योगिकी विकास निधि

176. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि ताइवान के अधिकारी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान या मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। नौ गतिविधियों को अनुदान के लिए पात्र माना गया है:

i. औद्योगिक नवाचार या अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।
ii. औद्योगिक प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उन्नयन से संबंधित मार्गदर्शन का प्रावधान।
iii. उद्यमों को नवाचार या अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
iv. नवप्रवर्तन या अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की स्थापना में सहायता करना।
v. उद्योगों, शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

vi. विद्यालयों में जनशक्ति संवर्धन में भाग लेने के लिए उद्यमों को प्रोत्साहित करना।

vii. यह सुनिश्चित करना कि औद्योगिक मानव संसाधनों की पर्याप्त आपूर्ति हो।

viii. स्थानीय उद्योगों को नवप्रवर्तन में सहायता करना।

ix. औद्योगिक नवाचार या अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य मामले।

177. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि परम्परागत उद्योग प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत, औद्योगिक विकास ब्यूरो कंपनियों को अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) तथा मौजूदा कौशल और उत्पादों के सुधार के लिए समर्पित उनकी परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए धन प्रदान करता है। पात्र होने के लिए, प्राप्तकर्ता को: (1) ताइवान में निगमित होना चाहिए; और (2) गैर-प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों में काम करना चाहिए। आवेदनों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: (1) उत्पाद विकास; (2) उत्पाद डिजाइन, और (3) संयुक्त विकास। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग चयन मानदंड हैं और प्रत्येक आवेदन के लिए दी जाने वाली अधिकतम राशि NT $10,000,000 है।

178. ताइवान सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों के एक कार्यक्रम के रूप में अस्तित्व की पुष्टि की है।

179. अनुदान *स्वतः ही* लाभ प्रदान करते हैं। अनुदान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के अर्थ में वित्तीय योगदान का गठन करते हैं क्योंकि वे धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हैं।

180. सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि जहां कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाता है, वहां सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि के बराबर होना चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त अनुदान की संपूर्ण राशि का प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए।

181. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सीवीडी नियमों के नियम 11 और अनुलग्नक II के भाग के पैराग्राफ 1(ए) के अनुसार, अनुदान कानून के रूप में कुछ उद्यमों और उद्योगों, यानी अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने वाली कंपनियों तक सीमित है, और इस प्रकार, विशिष्ट है।

182. घरेलू उद्योग ने इन कार्यक्रमों के लिए 0.064% का सब्सिडी मार्जिन प्रस्तावित किया है। इसने 2023 के लिए ताइवान सरकार द्वारा जारी डब्ल्यूटीओ अधिसूचना पर भरोसा किया है। सब्सिडी मार्जिन का अनुमान अनुदान की कुल राशि को कुल निर्यात मूल्य से विभाजित करके लगाया जाता है। चूंकि किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई अन्य प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकरण गैर-सहयोगी उत्पादकों को यह मार्जिन प्रदान करना उचित समझता है।

***नई उत्कृष्ट परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान;* उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम**

183. घरेलू उद्योग ने कहा है कि कोई भी कंपनी नए अग्रणी उत्पाद के विकास से संबंधित सहायता निधि के लिए आवेदन कर सकती है। उत्पाद में 'बड़ी बाजार क्षमता' होनी चाहिए और इसकी 'मुख्य प्रौद्योगिकी घरेलू औद्योगिक प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर से बेहतर होनी चाहिए।' दी जाने वाली सहायता निधि नए अग्रणी उत्पादों के विकास के लिए विशेष रूप से किए गए निम्नलिखित व्यय की राशि का पचास प्रतिशत (50%) से अधिक नहीं है:
    i. पूर्णकालिक अनुसंधान कर्मियों के लिए व्यय की गई लागत;
    ii. उपभोज्य उपकरणों और कच्चे माल की लागत;
    iii. अनुसंधान एवं विकास उपकरणों के उपयोग और रखरखाव की लागत;
    iv. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत.
    v. परियोजना से संबंधित यात्रा शुल्क.

184. अनुदान *स्वतः ही* लाभ प्रदान करते हैं। अनुदान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1) के अर्थ में वित्तीय योगदान का गठन करते हैं क्योंकि वे धन का प्रत्यक्ष हस्तांतरण हैं।

185. घरेलू उद्योग ने उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के बारे में भी विवरण प्रस्तुत किया है। इसने प्रस्तुत किया है कि ताइवान में कंपनी कानून के अनुसार स्थापित कोई भी कंपनी जिसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो और अनुसंधान एवं विकास विभाग हो, जिसने अतीत में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हों और जिसके पास वर्तमान में सक्षम विशेषज्ञ कार्यरत हों, वह निम्नलिखित गतिविधियों की लागतों की भरपाई के लिए इस निधि के लिए आवेदन कर सकती है:
    i. उन्नत प्रौद्योगिकियों का अनुसंधान और विकास, जिन्हें दीर्घावधि में महत्वपूर्ण और नवीन कहा जा सकता है।

ii. प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास जो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज एकीकरण को बढ़ाते हैं और उद्योग श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र या क्लस्टरों के निर्माण को प्रेरित करते हैं।

iii. ताइवान में अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना जो नवीन प्रौद्योगिकियों और सेवाओं का सृजन करेंगे।

iv. लघु एवं मध्यम आकार के व्यवसायों द्वारा नवीन या एकीकृत विनिर्माण प्रौद्योगिकी का विकास।

186. दी जाने वाली सहायता राशि निम्नलिखित व्ययों की कुल राशि के 50% से अधिक नहीं होगी:

i. पूर्णकालिक और/या अंशकालिक अनुसंधान कर्मियों के लिए किए गए खर्च;
ii. उपभोज्य उपकरणों और कच्चे माल की लागत;
iii. अनुसंधान एवं विकास उपकरणों के उपयोग और रखरखाव की लागत;
iv. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की लागत; और
v. घरेलू यात्रा व्यय.
vi. पेटेंट आवेदन के लिए पुरस्कार.

187. ताइवान सरकार ने इन दोनों कार्यक्रमों के एक ही कार्यक्रम के रूप में अस्तित्व की पुष्टि की है।

188. सीवीडी नियमों के अनुलग्नक IV में कहा गया है कि जहां कोई भी पैसा वापस नहीं किया जाता है, वहां सब्सिडी का मूल्य अनुदान की राशि के बराबर होना चाहिए। तदनुसार, उत्पादकों द्वारा प्राप्त अनुदान की संपूर्ण राशि का प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए।

189. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(3), सी.वी.डी. नियमों के नियम 11, तथा अनुलग्नक II के भाग के पैराग्राफ 1(ए) के अनुसार, यह अनुदान कानूनन कुछ उद्यमों और उद्योगों तक ही सीमित है।

190. घरेलू उद्योग ने इन कार्यक्रमों के लिए 0.84% का सब्सिडी मार्जिन प्रस्तावित किया है। इसने 2023 के लिए ताइवान सरकार द्वारा जारी डब्ल्यूटीओ अधिसूचना पर भरोसा किया है। सब्सिडी मार्जिन का अनुमान अनुदान की कुल राशि को कुल निर्यात मूल्य से विभाजित करके लगाया जाता है। चूंकि किसी अन्य पक्ष द्वारा कोई अन्य

प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है, इसलिए प्राधिकरण गैर-सहयोगी उत्पादकों को यह मार्जिन प्रदान करना उचित समझता है।

कार्यक्रम	**सब्सिडी मार्जिन**	
इन-ज़ोन उद्यमों के लिए शुल्क और कर छूट	3.10%	2022 के लिए, ताइवान ने NT$ 101,085 मिलियन मूल्य के व्यापार कर छूट प्रदान किए, और निर्यात बिक्री NT$ 2,784,974 मिलियन मूल्य की थी। सब्सिडी मार्जिन को व्यापार कर छूट की कुल राशि को कुल निर्यात मूल्य से विभाजित करके अनुमानित किया जा सकता है। WTO अधिसूचना 2023 (SCM समझौते के अनुच्छेद 25.1 के तहत)
उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए शुल्क और कर छूट	3.63%	2022 के लिए, ताइवान ने NT$ 1,809,825,000 मूल्य के अनुदान प्रदान किए, और निर्यात बिक्री NT$ 2,784,974 मिलियन मूल्य की थी। सब्सिडी मार्जिन 2022 में निर्यात बिक्री को दिए गए कुल अनुदानों का अनुपात है। WTO अधिसूचना 2023 (SCM समझौते के अनुच्छेद 25.1 के तहत) देखें
कुछ गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान; पारंपरिक उद्योग प्रौद्योगिकी विकास निधि	0.06%	2022 के लिए, ताइवान ने NT$ 4,258,051,000 मूल्य के अनुदान प्रदान किए, और निर्यात बिक्री NT$ 2,784,974 मिलियन मूल्य की थी। सब्सिडी मार्जिन 2022 में निर्यात बिक्री को दिए गए कुल अनुदान का अनुपात है। WTO अधिसूचना 2023 देखें (SCM समझौते के अनुच्छेद 25.1 के तहत)
नई बकाया परियोजनाओं के विकास के लिए अनुदान;	0.15%	2022 के लिए, ताइवान ने NT$ 4,258,051,000 मूल्य के अनुदान प्रदान किए, और निर्यात बिक्री NT$ 2,784,974

कार्यक्रम	सब्सिडी मार्जिन	
उद्यमों के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम		मिलियन मूल्य की थी। सब्सिडी मार्जिन 2022 में निर्यात बिक्री को दिए गए कुल अनुदान का अनुपात है। WTO अधिसूचना 2023 देखें (SCM समझौते के अनुच्छेद 25.1 के तहत)

सब्सिडी मार्जिन

क्र.सं.	उत्पादक	अनुदान के लिए सब्सिडी मार्जिन	निर्यात-आश्रित सब्सिडी मार्जिन (%)	शुद्ध सब्सिडी मार्जिन (%)	शुद्ध सब्सिडी मार्जिन (रेंज)
चीन					
1.	कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	***	***	***	0-10%
2.	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कं, लिमिटेड	***	***	***	30-40%
3.	फ़ूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड	***	***	***	10-20%
4.	हुआंगशान जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	10-20%
5.	चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	20-30%
6.	अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	20-30%
7.	अन्य सभी उत्पादक	***	***	***	40-50%
ताईवान					
8.	अन्य सभी उत्पादक	***	***	***	0-10%

छ. <u>क्षति के आकलन और कारणात्मक संबंध की जांच की पद्धति</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए अनुरोध

191. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. उत्पादक/निर्यातक ने कहा है कि भारतीय प्रिंटिंग प्लेट बाजार की वार्षिक मांग 48 मिलियन वर्ग मीटर है, जबकि घरेलू उत्पादन इस मांग का केवल 50% ही पूरा कर पाता है, जिससे शेष 50% की आपूर्ति के लिए आयात पर भारी निर्भरता बनी रहती है।

ii. आधार वर्ष (2019-20) से जांच अवधि तक संबद्ध देशों से आयात में 5% की गिरावट आई। संबद्ध देशों से टेक्नोवा का अपना आयात लगभग 3-4% था, जो यह दर्शाता है कि आयात से क्षति नहीं हो रही है।

iii. जांच अवधि के दौरान, महामारी वर्षों (2020-21 और 2021-22) के दौरान गिरावट के बाद आयात मात्रा सामान्य हो गई। उत्पादक/निर्यातक ने अनुरोध किया है कि इन महामारी वर्षों को विश्लेषण से बाहर रखा जाए तथा तुलना के लिए 2019-20 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाए।

iv. उत्पादक/निर्यातक ने तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान आयात में किसी भी वृद्धि को वास्तविक वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे महामारी-पूर्व स्तर पर वापसी के रूप में देखा जाना चाहिए।

v. भारत में मांग-आपूर्ति का महत्वपूर्ण अंतर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण पर काफी लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिससे यह संभावना नहीं रह जाती कि सभी निर्यातक पाटन में संलग्न हैं या सब्सिडी विशेष रूप से भारतीय बाजार को ध्यान में रखकर दी जा रही है।

vi. चीन और जापान से आयात की कीमतों में जांच अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई, जबकि आयात की पहुंच कीमत घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए, 2019-20 से 2022-23 तक, चीन से आने वाली कीमतें रु./एमटी*** (सूचकांक 100) से बढ़कर रु./एमटी*** (सूचकांक 145) हो गईं, जबकि घरेलू कीमतें केवल सूचकांक 100 से 133 तक बढ़ीं।

vii. कीमत में कटौती नगण्य है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) सहित पहुंच कीमत घरेलू कीमतों से अधिक है। उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि आयात से मूल्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जिससे घरेलू उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सके।

viii. कीमत कटौती और क्षति मार्जिन एक ही सीमा के भीतर हैं, जो दर्शाता है कि आयात से कोई महत्वपूर्ण क्षति नहीं हो रही है। यदि निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) बराबर हैं, तो इससे ज्ञात होता है कि आयात कीमत का निर्धारण क्षति रहित नहीं है।

ix. घरेलू उद्योग का यह दावा कि आयात के कारण उनकी कीमतें कम हो जाती हैं, आयात की बढ़ती हुई कीमतों से विरोधाभासी है, जो घरेलू कीमत वृद्धि से अधिक हो गई है।

x. आयात की कीमत में 43% से अधिक की वृद्धि और घरेलू कीमत में केवल 32% की वृद्धि को देखते हुए, उद्योग के कीमत कटौती के दावे निराधार प्रतीत होते हैं।

xi. उत्पादक/निर्यातक ने कहा है कि कीमत में क्षति का मूल्यांकन उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न उत्पाद प्रकारों पर व्यापक मूल्यांकन लागू करने के बजाय अधिक विस्तृत मूल्यांकन प्राप्त किया जा सके।

xii. क्रिसिल की रिपोर्ट टेक्नोवा के लिए मजबूत वित्तीय स्थिति दर्शाती है, जिसमें वित्त वर्ष 2023 में 35% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि और 2024 में "स्थिर" से "सकारात्मक" तक का बेहतर दृष्टिकोण है।

xiii. वित्त वर्ष 2022 में टेक्नोवा की 38% की राजस्व वृद्धि को कोविड के बाद बाजार के फिर से खुलने से समर्थन मिला, साथ ही स्थिर लाभ कीमतों और मूल्य निर्धारण लचीलेपन के कारण आगे सुधार की उम्मीद है।

xiv. टेक्नोवा के पास विविधतापूर्ण ग्राहक आधार, मजबूत नकदी संचय, कम ऋण-भार तथा उच्च ब्याज कवरेज है, जो क्षति के दावों का खंडन करता है।

xv. अपने एनएसआर को लगातार बढ़ाने के बावजूद, घरेलू उद्योग घाटे का दावा कर रहा है, जिसके लिए उत्तरदाताओं ने आयात के बजाय कुप्रबंधन या आंतरिक अकुशलता को जिम्मेदार ठहराया है।

xvi. टेक्नोवा का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि क्रिसिल की रिपोर्ट में दर्शाया गया है, यह दर्शाता है कि संभावित क्षति के उसके दावे अतिरंजित हैं, तथा निरंतर संरक्षण का उद्देश्य लाभ मार्जिन को बढ़ाना हो सकता है।

xvii. उत्तरदाताओं का तर्क है कि लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है या उत्पादन संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं किया है, जिसके कारण आयात पर निर्भरता बनी हुई है।

xviii. घरेलू उत्पादन मुद्रण प्लेटों की कुल बाजार मांग का केवल 50% ही पूरा करता है, तथा क्षमता विस्तार योजनाओं के दावों के बावजूद घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है।

xix. उत्पादक/निर्यातक ने नोट किया कि पीयूसी का घरेलू उत्पादन पूर्व वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान काफी बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 93 सूचकांक अंक हो

गया। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग केवल व्यापार सुरक्षा पर निर्भर हुए बिना भी उत्पादन में सुधार करने में सक्षम है।

xx. जांच अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 94 सूचकांक अंक हो गई, जो परिचालन दक्षता को दर्शाता है।

xxi. जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए मालसूची स्तर में लगभग 45% की उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे क्षति के दावों का और अधिक खंडन हुआ।

xxii. क्षमता विस्तार के दावों के बावजूद, घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।

xxiii. उत्तरदाताओं का तर्क है कि क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की गणना में डीजीटीआर द्वारा उपयोग किया गया 22% नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है और यह वर्तमान अंकित मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है।

xxiv. सीईएसटीएटी के निर्णयों ने 22% आरओसीई की तर्कसंगतता के बारे में चिंताएं जताई हैं, तथा सुझाव दिया है कि एनआईपी की गणना के लिए गैर-पाटन अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक लाभ का उपयोग किया जाना चाहिए।

xxv. यूरोपीय संघ गैर-पाटन अवधि के दौरान अर्जित लाभ के आधार पर उचित रिटर्न निर्धारित करने की प्रथा का पालन करता है, जिसे डीजीटीआर को अपनाने पर विचार करना चाहिए।

xxvi. उत्पादक/निर्यातक का कहना है कि ऋण और नियोजित पूंजी के निवल मूल्य दोनों घटकों पर एक समान 22% आरओसीई लागू करने से घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक लाभ मार्जिन उत्पन्न होता है, जिससे क्षति और कम कीमत पर बिक्री की गणना विकृत हो जाती है।

xxvii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों में विसंगतियां हैं, विशेष रूप से चीन से आयात की मात्रा के संबंध में, जो क्षति के दावों को विकृत करती हैं। उत्पादक/निर्यातक अनुरोध करता है कि अधिक सटीक विश्लेषण प्रदान करने के लिए टेक्नोवा के स्वयं के आयात को समग्र आयात मात्रा से बाहर रखा जाए।

xxviii. घरेलू उद्योग का गैर-संबद्ध देशों के माध्यम से धोखाधड़ी का दावा निराधार है, क्योंकि गैर-संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम बना हुआ है।

xxix. घरेलू उद्योग का तर्क है कि शून्य शुल्क वाले आयात से क्षति हो रही है, लेकिन प्रतिवादियों का तर्क है कि अंतिम जांच परिणाम के आधार पर ये आयात क्षति रहित हैं।

xxx. घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि का दावा करता है, लेकिन एल्युमीनियम की कीमतों में गिरावट (उत्पादन का एक प्रमुख घटक) इस दावे का खंडन करती है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

i. आयातों के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए मात्रा क्षति, मूल्य क्षति और आर्थिक मापदंडों पर प्रदर्शन के बारे में प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है।

ii. घरेलू उद्योग यह भी स्पष्ट करता है कि प्राधिकारी ने पीयूसी के संबंध में कंपनी की क्षति और लाभप्रदता के संबंध में प्रासंगिक जानकारी का विधिवत सत्यापन किया है।

iii. आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक आयात की मात्रा में मामूली गिरावट देखी गई है। इस कमी का कारण पाटनरोधी शुल्क को माना जा सकता है, जिसने संबद्ध देशों से आयात को, विशेष रूप से चीन जनवादी गणराज्य और ताइवान के अलावा अन्य देशों से कुछ हद तक रोका है। घरेलू उद्योग का दावा है कि जबकि अन्य देशों से आयात में कमी आई है, चीन जन.गण. और ताइवान से आयात में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

iv. जांच अवधि के दौरान आयात के स्तर में पिछले वर्ष की तुलना में, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2021-22 में, उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

v. घरेलू उद्योग का मानना है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध वस्तुओं का आयात आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में समान रहा है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद उत्पादन के संबंध में आयात में कोई कमी दृष्टिगत नहीं होती।

vi. मांग के संबंध में संबद्ध आयात आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में समान रहे हैं। तथापि, आधार वर्ष में चीन जन.गण. से आयात का हिस्सा 31% से बढ़कर जांच अवधि में 33% हो गया है।

vii. यह ध्यान देने योग्य है कि जांच अवधि में घरेलू उत्पादन और मांग दोनों के संबंध में संबद्ध आयातों में पिछले वर्ष अर्थात 2021-22 की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

viii. यह ध्यान देने योग्य बात है कि उत्पादन के संबंध में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तुओं के आयात में आधार वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में चीन जन.गण. से आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन का लगभग ***% था, जो जांच अवधि में बढ़कर ***% हो गया है।

ix. संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री कीमतसे कम कीमत पर हो रहा है, जिससे बिक्री कीमत में भारी कटौती हो रही है तथा घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। इन कम कीमतों के कारण सीधे तौर पर क्षति बढ़ गयी है।

x. ये आयात क्षतिरहित कीमत कीमत की तुलना में बहुत कम कीमत पर भारत में आ रहे हैं, और इसलिए, घरेलू उद्योग को गंभीर और वास्तविक क्षति हो रही है। इस तरह के कम कीमत वाले आयातों ने घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिससे उसे उचित बिक्री कीमत प्राप्त करने से रोका गया है।

xi. कीमत ह्रास घरेलू उद्योग की लागत में परिवर्तन के प्रभाव को अपनी बिक्री कीमत पर प्रतिबिंबित करने में असमर्थता है। घरेलू बाजार में कीमत ह्रास घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में परिवर्तन की तुलना में लागत में परिवर्तन के बीच का अंतर है।

xii. घरेलू उद्योग के लिए निर्माण और बिक्री की लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है, अर्थात आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में 41 सूचकांक अंकों की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग संबद्ध देशों से आयात के कारण पीयूसी की लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप इसकी बिक्री कीमत में वृद्धि नहीं कर सका। इसके अलावा, जांच अवधि में पाटित आयातों के कारण कीमत ह्रास में काफी वृद्धि हुई।

xiii. आधार वर्ष में चीन जन. गण. से आयात का बाजार हिस्सा 31% से बढ़कर जांच अवधि में 33% हो गया है, तथा पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 12% की वृद्धि हुई है।

xiv. संबद्ध वस्तुओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में ***% तक कम हुआ है।

xv. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी कमी देखी गई है।

xvi. चीन जन.गण. और ताइवान के अलावा अन्य संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है।

xvii. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट की तुलना में बहुत तेज गति से कमी आई। यह स्पष्ट रूप से संबद्ध देशों, विशेषकर चीन जन.गण. से पाटित किए गए आयातों के कारण है।

xviii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में कमी आई।

xix. जांच अवधि में आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में भी कमी आई है।

xx. प्रतिदिन उत्पादकता आधार वर्ष में 100 सूचीबद्ध अंकों से घटकर जांच अवधि में 93 सूचीबद्ध अंक रह गई है। नहीं। कर्मचारियों की संख्या में भी 2 सूचीबद्ध अंकों की कमी आई है।

xxi. इसी समय, आधार वर्ष की तुलना में कर्मचारियों के वेतन में जांच अवधि में 11 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई।

xxii. संबद्ध देशों से निरन्तर एवं लगातार पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के सभी वित्तीय निष्पादन संकेतकों, जैसे पीबीआईटी, नकद लाभ, तथा नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय कमी आई है।

xxiii. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का नुकसान दोगुने से भी अधिक हो गया है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के घाटे में 315 सूचीबद्ध अंकों की वृद्धि हुई है। ऐसा मुख्य रूप से संबद्ध देशों, विशेषकर चीन जन.गण. के निर्यातकों की ओर से मूल्य निर्धारण पर भारी दबाव के कारण हुआ है।

xxiv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को नकद हानि हुई तथा जांच अवधि में यह और बढ़ गया।

xxv. आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में नियोजित पूंजी पर आय में 220 सूचीबद्ध अंकों की गिरावट आई।

xxvi. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में तैयार वस्तु के भंडार का स्तर काफी बढ़ गया है।

xxvii. पाटित किए गए आयातों से स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग के पीयूसी कारोबार के वित्तीय निष्पादन में गिरावट आई है। पीयूसी घरेलू उद्योग के लिए एक बड़े उत्पाद पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट ने प्रतिस्पर्धी दरों पर पूंजी आकर्षित करने की घरेलू उद्योग की समग्र क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

xxviii. चीन के निर्यातकों ने आयात का स्रोत श्रीलंका और स्पेन बताकर पाटनरोधी शुल्क से बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप कम कीमत वाले सामानों का

भारी प्रवाह हुआ, जिसका घरेलू उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इस परिवंचना से शुल्कों का लाभ निरर्थक हो गया।

xxix. घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार योजनाओं में कोविड-19 महामारी के कारण और देरी हुई, जिससे मांग में कमी, लॉकडाउन और वित्तीय दबाव सहित अप्रत्याशित चुनौतियां आईं, जिससे वे लागू शुल्कों का पूरा लाभ नहीं उठा सके।

xxx. इन चुनौतियों के बावजूद, घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क के प्रवर्तन पर निर्भर करते हुए, अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिए निवेश और योजनाएं बनाई हैं। निरंतर शुल्क संरक्षण के बिना, उद्योग को पाटित किए गए आयातों से नए सिरे से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे इसकी वृद्धि और स्थिरता को खतरा होगा।

xxxi. कुछ पक्षों ने तर्क दिया कि वे क्षति रहित कीमत (एनआईपी) से अधिक कीमत पर उत्पाद की बिक्री कर रहे हैं और इसे घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारक नहीं माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि उचित कीम पर आयात हानिकारक नहीं है, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला कि संबद्ध देशों से आयात की एक बड़ी मात्रा को एनआईपी से कम कीमतों पर पाटित किया जा रहा है, जिससे काफी क्षति हो रही है।

xxxii. यद्यपि क्षति रहित आयात मौजूद हैं, घरेलू उद्योग ने इस बात पर बल दिया कि क्षति कीमतों पर पाटित किए गए आयात कीमतों में कटौती, बाजार हिस्सेदारी को कम करने और लाभप्रदता को कम करके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्राधिकारी को इन क्षतिकारी आयातों के प्रभाव को पहचानना होगा।

xxxiii. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि वर्तमान जांच में कोई मात्रा प्रभाव नहीं है और उन्होंने कोविड-19 के कारण वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के आंकड़ों को खारिज करते हुए जांच अवधि (पीओआई) में आयात मात्रा की तुलना वित्त वर्ष 2019-20 से करने का सुझाव दिया है। घरेलू उद्योग का कहना है कि इस तरह के विश्लेषण से मूल्यांकन गलत हो जाएगा, क्योंकि पाटन रोधी शुल्कों ने आयात को रोका है और जांच की अवधि के दौरान आयात की मात्रा वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में काफी बढ़ गई है।

xxxiv. कुछ पक्षों का तर्क है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध आयातों का 3-4% आयात करके स्वयं को क्षति पहुंचाई है। घरेलू उद्योग ने इस दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि आयात मात्रा की गणना उसके स्वयं के आयात को छोड़कर की जाती है।

xxxv. हितबद्ध पक्षकारों का तर्क है कि आयात से कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा है। तथापि, घरेलू उद्योग ने दर्शाया है कि चीनी आयात कीमतें लगातार उसकी निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही हैं, जिसके कारण कीमतों में भारी गिरावट आई है। यद्यपि घरेलू लागत में 23% की वृद्धि हुई, लेकिन घरेलू कीमतों में केवल 17% की वृद्धि हुई, जिससे दबी हुई चीन की कीमतों का प्रभाव उजागर हुआ।

xxxvi. कपूर ने लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) एल्युमीनियम की कीमतों में कमी का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में 26% की वृद्धि पर विवाद किया। घरेलू उद्योग का कहना है कि (i) प्रदान की गई जानकारी अविश्वसनीय है, (ii) एलएमई पर एल्युमीनियम की सीएसपी में वृद्धि हुई है, और (iii) लागत में वृद्धि प्रीमियम और खरीद लागत के कारण हुई है, जिसका सत्यापन प्राधिकारी द्वारा ऑन-साइट निरीक्षण के दौरान किया गया है।

xxxvii. कपूर टेक्नोवा के वित्तीय प्रदर्शन को दर्शाने वाली क्रिसिल रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन घरेलू उद्योग का तर्क है कि रिपोर्ट में टेक्नोवा के समग्र कारोबार को शामिल किया गया है, न कि केवल डीओपीपी को। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क हटाने से आयात और प्रतिस्पर्धा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान की पुष्टि होती है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

192. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने संबद्ध देश से सब्सिडीयुक्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

193. सब्सिडी नियमावली का नियम 13 क्षति के निर्धारित को शासित करने वाले सिद्धांतों से संबंधित है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं:

> *निर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में, निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे यह निष्कर्ष देंगे कि भारत में ऐसे उत्पाद के आयात से भारत में स्थापित किसी उद्योग को भौतिक क्षति होती है या क्षति होने का खतरा है, या भारत में स्थापित उद्योग को बाधित करता है और उद्योग को भौतिक रूप से बाधित करता है। (2) उप-नियम (3) के अंतर्गत क्षति का निष्कर्ष निकाले जाने के सिवाय, निर्दिष्ट*

प्राधिकारी क्षति, क्षति की धमकी, उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा तथा सब्सिडीयुक्त आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण, अन्य बातों के साथ-साथ, नियम के अनुबंध-1 में दिए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए करेगा। (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी, अपवादात्मक मामलों में, क्षति के अस्तित्व के संबंध में निष्कर्ष दे सकते हैं, भले ही घरेलू उद्योग का पर्याप्त भाग क्षतिग्रस्त न हुआ हो, यदि - (i) सब्सिडीयुक्त आयातों का एक पृथक बाजार में संकेन्द्रण हो, और (ii) सब्सिडीयुक्त आयातों से उत्पादक बाजार के सभी उत्पादकों को क्षति हो रही हो, जिसमें घरेलू उद्योग का पर्याप्त भाग क्षतिग्रस्त न हुआ हो।

194. प्राधिकरण नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी मापदण्ड गिरावट दर्शाते हों। कुछ मापदंडों में गिरावट दिख सकती है, जबकि कुछ में नहीं। प्राधिकारी घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों का आकलन करने के लिए सभी क्षति मापदंडों पर विचार करते हैं । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति मापदंडों की निष्पक्ष रूप से जांच की है।

195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयात विभिन्न माप इकाइयों में किया गया है, जिनमें वर्गमीटर, किलोग्राम, नग और केस शामिल हैं। आयात मात्रा का निर्धारण मानक रूपांतरण मानदंड अर्थात *** वर्गमीटर प्रति किलोग्राम के आधार पर वर्गमीटर में किया गया है। एसक्यूएम या किलोग्राम में नहीं किए गए आयातों के संबंध में, उनकी मात्रा को उत्पादों के आयात लेनदेन विवरण में दर्शाई गई जानकारी (मात्रा, आयाम आदि) के आधार पर परिवर्तित किया गया है। वर्तमान अंतिम निष्कर्ष में क्षति के आकलन के प्रयोजनार्थ क्रमबद्ध डीजी सिस्टम्स आंकड़ों पर विचार किया गया है।

196. प्राधिकरण ने नीचे पैराग्राफों में घरेलू उद्योग की स्थिति पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव की जांच की है।

मांग का आकलन

197. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार मूल्यांकित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	एसक्यूएम	12,236,508	4,785,772	5,420,780	12,308,861
	सूचीबद्ध	100	39	44	101
असंबद्ध देशों से आयात	एसक्यूएम	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
	सूचीबद्ध	100	165	299	292
उन देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	एसक्यूएम	1,612,110	1,498,953	1,306,937	76,842
	सूचीबद्ध	100	93	81	5
कुल आयात	एसक्यूएम	**1,45,05,334**	**73,67,190**	**86,88,785**	**1,43,03,156**
	सूचीबद्ध	100	51	60	99
घरेलू उद्योग की बिक्री	एसक्यूएम	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	73	95	94
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एसक्यूएम	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	23,100	1,73,463	1,67,345
कुल मांग/खपत	एसक्यूएम	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	66	86	98

198. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कम हुई, लेकिन उसके बाद 2021-22 और जांच की अवधि में इसमें वृद्धि हुई। हालाँकि, जांच अवधि के दौरान मांग मोटे तौर पर स्थिर रही है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है।

संबद्ध देशों से आयातों की प्रभावित मात्रा

199. आयात की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयात में, चाहे निरपेक्ष रूप से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी प्रणालियों से प्राप्त लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है।

<u>आयात में सापेक्ष वृद्धि</u>

200. घरेलू उद्योग के उत्पादन और संबद्ध वस्तुओं की मांग के संबंध में क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
याचिकाकर्ता के उत्पादन के संबंध में आयात					
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	रेंज	40-50	20-30	10-20	40-50
असंबद्ध देश	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10
एडीडी आकर्षित करने वाले देश	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल आयात	**%**	***	***	***	***
	रेंज	40-50	30-40	30-40	40-50
देश में मांग के सापेक्ष आयात					
संबद्ध देश	%	***	***	***	***
	रेंज	20-30	20-30	20-30	30-40
एडीडी आकर्षित करने वाले देश	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10
असंबद्ध देश	%	***	***	***	***
	रेंज	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल आयात	%	***	***	***	***
	रेंज	30-40	30-40	30-40	30-40

आयात में पूर्ण वृद्धि

201. क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात की मात्रा संबद्ध वस्तुओं के संबंध में निरपेक्ष रूप से निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	एसक्यूएम	12,236,508	4,785,772	5,420,780	12,308,861
- चीन	एसक्यूएम	1,20,02,862	46,81,170	52,84,813	1,16,11,633

- ताईवान	एसक्यूएम	233,646	104,602	135,967	697,228
देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	एसक्यूएम	1,612,110	1,498,953	1,306,937	76,842
- जापान	एसक्यूएम	1,044,526	636,933	138,105	25,889
- दक्षिण कोरिया	एसक्यूएम	553,851	862,020	1,168,832	50,953
- वियतनाम	एसक्यूएम	13,733	-	-	-
असंबद्ध देशों से आयात	एसक्यूएम	656,716	1,082,465	1,961,068	1,917,453
कुल आयात	**एसक्यूएम**	**14,505,334**	**7,367,190**	**8,688,785**	**14,303,156**

202. यह देखा गया है कि:

क. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है।

ख. घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है।

संबद्ध देशों से आयातों का कीमत प्रभाव

203. संबद्ध देशों से आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों द्वारा मूल्य में महत्वपूर्ण कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से भारत में समान उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई होगी, या सामान्य क्रम में अन्यथा वृद्धि हुई होगी। संबद्ध देशों से आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रासऔर कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है।

<u>कीमत कटौती</u>

204. कीमत कटौती का निर्धारण करने के लिए, समान व्यापार स्तर पर, उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री कीमत, सभी छूटों और करों को घटाकर, के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित की गईं:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग का एनएसआर	आईएनआर/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	114	133
संबद्ध देशों से पहुंच कीमत	आईएनआर/एसक्यूएम	208	244	292	298
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	140	143
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	26	4	67
कीमत कटौती	% - रेंज	10-20%	0-10%	0-10%	10-20%

205. यह देखा गया है कि संपूर्ण क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान सकारात्मक मूल्य कटौती हुई है।

<u>कीमत ह्रास/न्यूनीकरण</u>

206. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करता है या मूल्य वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा सामान्य रूप से होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लागतों और कीमतों में (प्रत्यक्ष बिक्री उपरिव्ययों को छोड़कर कारखाना-द्वार स्तर पर) परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
निर्माण और बिक्री की लागत	आईएनआर/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	96	115	142
घरेलू बिक्री कीमत	आईएनआर/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	114	133

पहुंच कीमत	आईएनआर/एसक्यूएम	208	244	292	298
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	117	140	143

207. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण मूल्य दबाव का सामना करना पड़ा। जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लगातार निर्माण एवं बिक्री लागत से कम रही है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निर्माण एवं बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत के बीच का अंतर बढ़ गया है।

208. कुछ हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग की कच्चे माल की लागत लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) के अनुसार एल्युमीनियम की कीमतों में परिवर्तन के अनुरूप नहीं बढ़ी है, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि एलएमई पर उद्धृत कीमतें आधार धातु की कीमतें हैं। लिथोग्राफिक एल्युमीनियम कॉयल में रूपांतरण लागत, धातु प्रीमियम, ऊर्जा अधिभार आदि जैसे अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा एल्युमीनियम की खरीद की लागत का सत्यापन किया है।

घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

209. सी.वी.डी. नियमों में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर संबद्ध आयातों के परिणामस्वरूप हुई क्षति की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में, सीवीडी नियम आगे यह प्रावधान करते हैं कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडी वाले आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर असर डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुपरक मूल्यांकन शामिल होगा, जिसमें मुनाफे, बाजार रिटर्न, आउटपुट, उत्पाद या क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। तदनुसार, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच की गई है।

<u>उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा</u>

210. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
पीयूसी का उत्पादन	एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	68	91	96
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	68	89	93
घरेलू बिक्री - पीयूसी	एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	73	95	94

211. यह देखा गया है कि :

i. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में पीयूसी के उत्पादन में गिरावट आई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 में उत्पादन की तुलना में जांच अवधि में पीयूसी के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ii. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 100% से अधिक है, तथापि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वह निरंतर प्रक्रिया सुधार और अवरोधों को दूर करके अपने उत्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है।

iii. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसी अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में वृद्धि हुई है।

बाजार हिस्सा

212. आयात और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से की जांच निम्नानुसार की गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात					
- चीन	एसक्यूएम	12,002,862	4,681,170	5,284,813	11,611,633
- ताईवान	एसक्यूएम	233,646	104,602	135,967	697,228

देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है					
- जापान	एसक्यूएम	1,044,526	636,933	138,105	25,889
- दक्षिण अफ्रीका	एसक्यूएम	553,851	862,020	1,168,832	50,953
- वियतनाम	एसक्यूएम	13,733	-	-	-
असंबद्ध देशों से आयात	एसक्यूएम	656,716	1,082,465	1,961,068	1,917,453
कुल आयात	एसक्यूएम	**14,505,334**	**7,367,190**	**8,688,785**	**14,303,156**
घरेलू उद्योग	एसक्यूएम	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की बिक्री	एसक्यूएम	***	***	***	***
कुल मांग	**एसक्यूएम**	***	***	***	***
कुल मांग	सूचीबद्ध	100	66	86	98
बाजार जिस्सा					
संबद्ध देशों से आयात	%				
- चीन	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	59	51	99
संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	68	68	305
देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू है	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	141	95	5
असंबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	250	348	298
कुल आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	77	70	101
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	110	96
सहयोगियों की बिक्री	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	35019	202198	170765
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

213. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपना बाजार हिस्सा खो दिया है, जिस पर अन्य घरेलू उत्पादकों का कब्जा है। इसके अलावा, कुल आयात में बाजार हिस्सेदारी स्थिर बनी हुई है, जबकि चीन जन.गण. और ताइवान की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 28% से 31% और 1% से 2% तक बढ़ गई है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध

देशों (विशेष रूप से चीन जन.गण. और ताइवान से) से आयात में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

<u>मालसूची</u>

214. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	एसक्यूएम	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एसक्यूएम	***	***	***	***
औसत मालसूचियां	एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	91	55	55

215. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के भंडार में गिरावट आई है।

<u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>

216. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	POI
कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	आईएनआर लाख में	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	(146)	(216)	(391)
कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	आईएनआर/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	(200)	(228)	(417)
नकद लाभ/(हानियां)	आईएनआर लाख में	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	(280)	(597)	(2,010)
नकद लाभ/(हानियां)	आईएनआर/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	(384)	(632)	(2,142)
नियोजित आय	आईएनआर लाख में	***	***	***	***
प्रवृति	सूचीबद्ध	100	101	104	129
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***

प्रवृति	सूचीबद्ध	(100)	(144)	(208)	(302)

217. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में और कमी आई है। यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के भंडार में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में लाभ, नकद लाभ और पूंजी पर आय में और गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को नकद घाटा हो रहा है तथा नियोजित पूंजी पर आय नकारात्मक हो रही है।

<u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

218. प्राधिकारी ने नीचे दिए गए अनुसार रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है:

विवरण	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**जांच की अवधि**
दैनिक उत्पादकता	एसक्यूएम/दैनिक	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	68	89	93
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	102	98
मजदूरी	भारतीय रुपए लाख में	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	105	114

219. यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या स्थिर बनी रही है। क्षति अवधि में प्रतिदिन उत्पादकता में गिरावट आई है तथापि, जांच की अवधि में मजदूरियों में वृद्धि हुई है।

<u>पूंजी निवेश को जुटाने की क्षमता</u>

220. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद व्यापार के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने हानियों का सामना किया है तथा नियोजित पूंजी पर आय में ऋणात्मक गिरावट दर्ज की है। इस प्रकार, आयातों ने अपने पूंजी निवेश को जुटाने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर विपरीत प्रभाव डाला है।

क्षति मार्जिन की मात्रा

221. विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत को जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाने के द्वारा निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की संगणना के लिए संबद्ध देशों से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए क्षति रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति-रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। युटिलिटीज के साथ भी समान उपचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर असाधारण अथवा अनावर्ती व्ययों को प्रभारित किया गया है। क्षति रहित कीमत पर पहुंचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल अचल परिसंपतियां तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर पूर्व 22% की दर से) की अनुमति दी गई थी।

222. कुछ विशिष्ट हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए क्षति रहित कीमत और क्षति के निर्धारण के लिए अनुसरित किए गए उत्पादन की लागत और आबंटन कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए तर्क दिया है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति के दावों तथा क्षति रहित कीमत की संगणना करते समय उन्होंने घरेलू उद्योग के अभिलेखों की जांच और सत्यापन किया है जिसमें उसकी संतुष्टि के लिए लागत का आबंटन भी शामिल है किन्तु उस तक सीमित नहीं है। विचाराधीन उत्पाद से गैर-विचाराधीन उत्पाद उत्पादों की आधार संरचनात्मक लागत के आबंटन पर चिन्ता के संबंध में, प्राधिकारी ने किए गए आबंटनों की जांच की है और एनआईपी के परिकलन के लिए लागत को उचित रूप से अनुमति प्रदान की है। प्राधिकारी ने क्षति रहित कीमत की संगणना के लिए अनुबंध-III में निर्धारित किए गए सिद्धांतों का अनुसरण किया है।

223. संबद्ध देशों से सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत को उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर निर्धारित किया गया है। संबद्ध देशों से असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत को निर्धारित किया है।

224. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि हैंडलिंग, लोडिंग, अन-लोडिंग प्रभारों पर पहुंच मूल्य के परिकलन के प्रयोजनार्थ विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के निर्धारणीय मूल्य के आधार पर पहुंच मूल्य की गणना की है जो प्राधिकारी

द्वारा अनुसरित लगातार अभ्यास के अनुरूप है। प्राधिकारी द्वारा परिकलित पहुंच कीमत नीचे तालिका में दर्शायी गई है।

225. प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पीसीएन के लिए उपरोक्त अनुसार निर्धारित पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारांशित औसत क्षति मार्जिन को निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में उपलब्ध कराया गया है:-

<u>क्षति मार्जिन तालिका</u>

क्र.सं.	**उत्पादक**	**एनआईपी**	**पहुंच कीमत**	**क्षति मार्जिन**	**क्षति मार्जिन**	**रेंज**
		यूएसडॉ./एसक्यूएम	**यूएसडॉ./ एसक्यूएम**	**यूएसडॉ./ एसक्यूएम**	**%**	**%**
1	**चीन जन.गण.**					
क	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
ख	कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	नकारात्मक
ग	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
घ	अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
ड.	हुआंगशान जिनरुइटाई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30

च	चोंग्किंग हुआफ़ेंग डिजेट प्रिंटिंग मटीरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
छ	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
4	**ताइवान**					
क	सभी	***	***	***	***	30-40

ज. <u>महत्वपूर्ण क्षति का खतरा</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

i. क्षति की संभावना के संबंध में आवेदक का दावा निराधार है क्योंकि वे त्रुटिपूर्ण तर्क पर आधारित हैं। वैश्विक मांग-आपूर्ति परिप्रेक्ष्य पर विचार किए बिना निर्यातकर्ता देशों में अतिरिक्त क्षमताओं की केवल विद्यमानता स्वत:रूप से क्षति की पुनरावृत्ति के औचित्य को सिद्ध नहीं करती।

ii. आवेदक का दावा कि भारतीय बाजार कीमत आकर्षक है, निम्न आयात कीमतों के इसके दावे के विरोधाभास में है। मांग-आपूर्ति अंतर वाले एक बाजार में, विदेशी विक्रेता तार्किक रूप से प्रीमियम प्रभारित करेगा। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने क्षति संबंधी दावों के समर्थन में मालसूचियों और कीमत परिदृश्य पर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं कराया है।

iii. घरेलू उद्योग का दावा है कि संबद्ध देशों, विशेषकर चीन में उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमता है। हालांकि, अतिरिक्त क्षमता ने अकेले ही पाटन या क्षति की संभावना स्थापित नहीं की है। यह दर्शाना चाहिए कि कैसे यह क्षमता भारतीय बाजार की ओर निदेशित की जाएगी। पिछले मामलों में जैसे कि यूएसए और जापान से एनीलाइन ने दर्शाया है कि बिना किसी अतिरिक्त औचित्य के संभावना के सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त क्षमता अपर्याप्त है।

iv. याचिकाकर्ता ने अन्य देशों जिनमें ब्राजील, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपैई और ई.यू. शामिल हैं, द्वारा चीन पर लागू किए गए पाटनरोधी शुल्कों का संदर्भ दिया है। तथापि, अन्य देशों द्वारा शुल्कों को लागू किया जाना स्वत:रूप से यह स्थापित नहीं करता कि उत्पाद को भारतीय बाजार को निदेशित किया जाएगा।

v. घरेलू उद्योग अपनी लगातार होने वाली क्षति के लिए आयातों को जिम्मेदार ठहराता है किन्तु शुल्कों को लागू किए जाने के बावजूद इसके निष्पादन में

ह्रास हुआ है। यह बताता है कि क्षति संभवत: अन्य कारकों द्वारा की गई है न कि आयातों द्वारा, जैसाकि पिछले अनुरोधों में विस्तार से बताया गया है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

i. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों का पाटित होना जारी है। यह तथ्य कि आयातों का जारी रहना और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचना, पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को स्थापित करने के लिए यह तथ्य पर्याप्त है।

ii. पाटित आयातों का उल्लेखनीय मात्रा में संबद्ध देशों से आना जारी है। यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से अनवरत पाटित आयातों की सुदृढ़ संभावना है।

iii. पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने के बावजूद कीमत और मात्रा क्षति से घरेलू उद्योग का सामना करना जारी है।

iv. पिछले चार वर्षों में वित्तीय और आर्थिक निष्पादन में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

v. घरेलू उद्योग निम्न कीमतों पर उत्पादों की बिक्री करने के लिए विवश है जो उल्लेखनीय रूप से लाभप्रदता को प्रभावित करता है।

vi. पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, सतत लाभप्रदता को अनुरक्षित नहीं किया गया है।

vii. नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई) ऋणात्मक है और 22% की बैंचमार्क दर से बहुत नीचे है।

viii. सकारात्मक कीमत कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत में कमी मौजूद है जैसाकि याचिका के भाग VI में विस्तार से बताया गया है।

ix. यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो क्षति के जारी रहने तथा स्थिति के और अधिक खराब होने की संभावना है।

x. 2018 में प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के विरुद्ध शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी जिस कारण अल्प अवधि में ही घरेलू उद्योग की क्षति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

xi. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन के लिए चीन जन.गण. में महत्वपूर्ण अत्यधिक और निष्क्रिय क्षमताएं विद्यमान हैं।

xii. चीन जन.गण. की स्थापित क्षमताएं 1025 मिलियन एसक्यूएम से अधिक हैं जबकि घरेलू मांग केवल 180-200 मिलियन एसक्यूएम होने का अनुमान है।

xiii. लगभग 825 मिलियन एसक्यूएम की अतिरिक्त क्षमता को निर्यात बाजारों की तरफ निर्देशित किया गया है।

xiv. संबद्ध वस्तुओं के लिए भारत के बाजार का आकार वार्षिक रूप से लगभग 45 मिलियन एसक्यूएम है।

xv. चीन जन.गण. में अतिरिक्त क्षमता भारत की कुल घरेलू मांग से लगभग 20 गुणा अधिक है।

xvi. यदि शुल्कों को वापिस लिया जाता है तो चीन जन.गण. की अतिरिक्त क्षमता को संभवत: भारत को निर्यातों को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाएगा।

xvii. चीन की अल्युमीनियम बाजार सरकार के हस्तक्षेप के कारण विकृत हो गया है जैसा कि 2019 से 2024 तक की ओईसीडी रिपोर्टों में नोट किया गया है।

xviii. चीन ने स्थिर राज्य समर्थन के जरिए उच्च इनपुट लागतों और निम्न अल्युमीनियम कीमतों को व्यवस्थित रखा है।

xix. चीन का टैरिफ ढांचा प्राथमिक अल्युमीनियम निर्यातों पर उच्च निर्यात टैरिफ और अपूर्ण वैट रियायतों के साथ डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम गतिविधियों का समर्थन करता है।

xx. चीन अल्युमीनियम विनिर्माताओं और विचाराधीन उत्पाद उत्पादकों को प्राथमिकता प्राप्त ऋण, कर प्रोत्साहन और सब्सिडी प्राप्त ऊर्जा कीमतें उपलब्ध करता है।

xxi. यह अन्य देशों के उत्पादकों को प्रभावित करते हुए वैश्विक बाजार में उत्पादन की लागतों को कम करता है और अल्युमीनियम की अधिक आपूर्ति करता है।

xxii. इन बाजार विकृतियों ने घरेलू उद्योग के लिए उल्लेखनीय चुनोतियां सृजित की हैं।

xxiii. चीनी निर्यातक व्यापार कदाचारों जैसे ट्रांसशिपमेंट और मूल स्थान की गलत घोषणा (अर्थात चीन जन.गण. के स्थान पर श्री लंका या स्पेन को मूल का स्थान घोषित करना) में संलग्न हैं।

xxiv. इन कदाचारों ने घरेलू उद्योग को कमजोर करते हुए पाटित उत्पादों की भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी है।

xxv. संबद्ध वस्तुओं के आयातों की कीमत घरेलू कीमतों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम निर्धारित की गई हैं।

xxvi. अन्य देशों से बढ़ी हुई मांग और पाटनरोधी उपायों के कारण भारत अन्य देशों से निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है।

xxvii. विभिन्न क्षेत्राधिकार जिनमें ब्राजील, दक्षिण कोरिया, ताइवान, यूएसए और ई.यू. शामिल हैं, ने चीन जन.गण. से डिजिटल प्लेट्स पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए हैं। चीन की पाटन अभ्यासों के वैश्विक रूप से पहचाने जाने तथा यदि शुल्कों को वापिस लिया जाता है तो अतिरिक्त उत्पादन को भारत को पुननिर्देशित किए जाने की बढ़ती हुई संभावना बढ़ जाती है।

xxviii. घरेलू उद्योग ने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि चीन की विचाराधीन उत्पाद के लिए कुल स्थापित क्षमता 1025 मिलियन एसक्यूएम से अधिक है जबकि घरेलू मांग केवल 180-200 मिलियन एसक्यूएम है अत: वह निर्यात बाजारों को समर्पित करने के लिए लगभग 825 मिलियन एसक्यूएम की अतिरिक्त क्षमता को शेष छोड़ता है। इसके विपरीत, भारत का बाजार आकार वार्षिक रूप से केवल 45 मिलियन एसक्यूएम का है जो चीन की अतिरिक्त क्षमता को भारत की कुल मांग का लगभग 20 गुणा ठहराता है।

xxix. हालांकि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित एचएस टैरिफ कोड की कमी है, जो इसे तृतीय देश के निर्यात डेटा को उपलब्ध कराने को कठित बनाता है, घरेलू उद्योग स्थापित करता है कि संबद्ध देश निर्यातोन्मुखी है और वैश्विक रूप से इसने अनुचित पद्धतियां अपनाई हैं। ब्राजील, ताइवान, कोरिया गणराज्य और यूएसए ने चीन से डीओपीपी आयातों पर शुल्क लागू किए हैं।

xxx. चीन की सरकार अपने उत्पादकों को भारत में स्थित उत्पादकों सहित वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को मात देने की अनुमति देने के द्वारा एक अनुचित लाभ देते हुए अल्युमीनियम बाजार को सहायता देती है। इस खतरे को दूर करने के लिए चीनी निर्यातों के विरुद्ध ब्राजील, दक्षिण कोरिया और यूएसए जैसे देशों ने पाटनरोधी उपाय लागू किए हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

226. नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे कारकों के लिए व्यवस्था की गई है जिन पर महत्वपूर्ण क्षति के खतरे को निर्धारित करने के लिए विचार किए जाने की जरूरत है:

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर बढ़ते हुए उल्लेखनीय आयात की संभावना की ओर संकेत करती है।

ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निस्तारणीय अथवा एक आसन्न, पर्याप्त वृद्धि किन्हीं अतिरिक्त आयातों को अविशोषित करने के लिए अन्य

निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों की संभावना की ओर संकेत करती है।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर एक महत्वपूर्ण ह्रासात्मक अथवा दमनकारी प्रभाव पड़ेगा और जिनके कारण और अधिक आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है; और

घ. वस्तु की मालसूचियों की जांच की जा रही है।

227. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ उपर्युक्त अनिवार्यताओं और यह निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित पैरामीटरों पर विचार किया है कि क्या महत्वपूर्ण क्षति का खतरा मौजूद है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की गई सारी संगत जानकारियों की जांच की है।

पाटित किए गए आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर

228. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जहां विचाराधीन उत्पाद के सम्पूर्ण आयात स्थिर बने हुए हैं वहीं वर्ष 2020-21 और 2021-22 में किए गए आयातों की तुलना में जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से आयात नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश	एसक्यूएम	12441030	5789697	7351282	14225726
	सूचीबद्ध	100	47	59	114

229. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के बाद भी आयातों में वृद्धि जारी रही है।

<u>जारी और वर्तमान पाटन और क्षति</u>

230. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात पाटनरोधी शुल्क के मौजूद होने के बावजूद पाटित कीमतों पर हैं। यह भी नोट किया गया है कि लाभों, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में उल्लेखनीय ह्रास हुआ है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

<u>अतिरिक्त एवं निस्तारणीय क्षमताएं</u>

231. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों में (विशेषकर चीन जन.गण. तके) विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए उल्लेखनीय अत्यधिक और निष्क्रिय क्षमताएं मौजूद हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि चीन जन.गण. में कुल संस्थापित क्षमताएं ***मिलियन एसक्यूएम की अधिकता में हैं जबकि देश में कुल मांग केवल ***मिलियन एसक्यूएम होने का अनुमान है। लगभग ***मिलियन एसक्यूएम की अतिरिक्त क्षमताएं निर्यात बाजारों के लिए समर्पित हैं। अतिरिक्त क्षमताएं भारतीय मांग का *** गुणा हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के विपरीत कोई सूचना या साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।

232. इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों से उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर के विश्लेषण को निम्नानुसार दर्शाया गया है:-

विवरण	**यूनिट**	**चीन जन.गण. से निर्यातक**
संस्थापित क्षमता	एसक्यूएम	***
उत्पादन	एसक्यूएम	***
क्षमता उपयोग	%	***
कुल बिक्रियां	एसक्यूएम	***
निर्यात बिक्रियां	एसक्यूएम	***
अतिरिक्त क्षमताएं	एसक्यूएम	***
निर्यात उन्मुखीकरण - कुल बिक्रियों की तुलना में निर्यात् बिक्रियों का अनुपात	%	40-50%

233. जैसाकि उपर्युक्त से देखा जा सकता है:-

क. उत्पादकों और निर्यातकों के पास कुल भारतीय मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमताएं हैं। इसके अलावा, प्रतिभागी उत्पादक और निर्यातक के पास उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमताएं भारतीय मांग का लगभग 40% हैं।

ख. कुल बिक्रियों के लगभग 49%-54% के साथ उच्च निर्यातोन्मुखी उत्पादक और निर्यातक संबंधित देशों से निर्यात करते हैं। इन निर्यातों को भारत की ओर मोड़ा जा सकता है।

विभिन्न देशों द्वारा शुल्कों को लागू करना

234. आवेदक ने अनुरोध किया है कि विभिन्न देशों ने चीन जन.गण. और अन्य देशों के विरुद्ध विचाराधीन उत्पादन पर पाटनरोधी शुल्क लागू किए हैं। इनके विवरण निम्नानुसार उपलब्ध कराए गए हैं:-

क. <u>ब्राजील:</u> ब्राजील ने 4 मई, 2021 को चीन जन.गण., चीनी ताइपैई, यूएसए, ईयू और यूके से आयातित पीयूसी पर पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चित पाटनरोधी शुल्क विस्तारित किया है। शुल्कों का दायरा 0.19 यूएस डॉ. से 2.38/कि.ग्रा. है।

ख. <u>दक्षिण कोरिया</u> - दक्षिण कोरिया ने 25 अक्तूबर, 2022 को चीन जन.गण. से आयातित विचाराधीन उत्पाद पर पांच वर्षों की अवधि के लिए एक पाटनरोधी शुल्क विस्तारित किया है। शुल्क का दायरा 8.78 - 10.32% है।

ग. <u>चीनी ताइपैई</u> - 25 मई, 2023 को चीनी ताइपैई के वित्त मंत्रालय ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से आयातित विचाराधीन उत्पादों पर एक पाटनरोधी जांच आरंभ की है। जून, 2024 में चीनी ताइपैई ने चीन जन.गण. से आयातों पर शुल्क लागू किए। शुल्क रेंज 13.52% - 76.89%. है।

घ. <u>संयुक्त राज्य अमेरिका</u> - संयुक्त राज्य ने निश्चित रूप से यह निर्धारित किया है कि यूएस को किए गए डीओपीपी के चीनी निर्यात पाटित और सब्सिडी प्राप्त, दोनों हैं। सीवीडी शुल्कों की रेंज 38.5 - 231.98% तथा पाटनरोधी शुल्कों की रेंज 164.30-477.59%. है।

235. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातक और उत्पादक पाटनरोधी शुल्क के प्रवृत्त होने के बावजूद संबद्ध देशों से निर्यातक और उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद को पाटित कर रहे हैं।

आयातों का ह्रासकारी और दमनकारी प्रभाव

236. जैसाकि क्षति संबंधी आकलन से देखा जा सकता है, संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास कर रहे हैं साथ ही घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि

उत्पाद तथा बिक्री की लागत	भारतीय रुपए/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	96	115	142
घरेलू बिक्री कीमत	भारतीय रुपए/एसक्यूएम	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	114	133
पहुंच कीमत	भारतीय रुपए/एसक्यूएम	208	244	292	298
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	140	143

237. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत से कम है।

झ. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

238. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

i. आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण: क्षति आवेदक द्वारा झेली गई किसी क्षति का वास्तविक कारण आंतरिक प्रतिस्पर्धा है।

ii. एक नए उत्पादक, एचएल प्रिंटेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ किया है।

iii. एचएल प्रिंटेक सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 3.3 गुणाा वृद्धि दर्शाते हुए, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 100 सूचकांक बिंदु से अपना उत्पादन उल्लेखनीय रूप से बढ़ा कर जांच की अवधि के दौरान 431 सूचकांक बिंदु कर दिया।

iv. अन्य उत्पादकों की घेरलू बिक्रियां आधार वर्ष में 100 सूचकांक बिंदुओं से उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर जांच की अवधि के दौरा 167,345 सूचकांक बिंदु हो गई।

v. क्षति, यदि कोई है, तो वह अन्य घरेलू उत्पादकों, विशेषकर नए प्रवेशकर्ता एचएल प्रिंटेक सोल्यूशंस प्रा. लि. की कीमत निर्धारण रणनीति के कारण है।

vi. आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान आवेदक के पीयूसी की निर्यात बिक्रियों में लगभग 22% की गिरावट आई जिससे प्रति यूनिट

निर्धारित लागत में वृद्धि हुई। आवेदक को होने वाली कोई भी क्षति निर्यात बिक्रियों में इस गिरावट के कारण है।

vii. आवेदक दिसंबर, 2012 के बाद से, लगभग 11.5 वर्षों के लिए शुल्क संरक्षण प्राप्त कर रहा है। क्षति, यदि कोई है तो वह आवेदक द्वारा कुप्रबंधन तथा लिए गए गलत व्यापार निर्णयों के कारण है।

viii. उत्तर देने वाले आवेदक ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने चीन जन.गण. और जापान से आयातों को आवेदक द्वारा सामना की जा रही किसी क्षति के लिए उत्तर दायी नहीं ठहराया है क्योंकि अनुभव किए गए किसी नुकसान के लिए अन्य कारक उत्तर दायी हैं।

ix. मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वह विचाराधीन उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है और निर्यात बाजारों में कीमत प्रतिस्पर्धी है।

x. यह भारत में घरेलू उद्योग के निष्पादन के बारे में चिन्ता उत्पन्न करता है जहां यह निर्यात बाजारों में कीमत प्रतिस्पधी होते हुए भी पाटित आयातों के कारण क्षति का दावा करता है।

xi. घरेलू उद्योग को यह बताना चाहिए कि क्यों वह निर्यात बाजारों में तो प्रतिस्पर्धी है किन्तु अपने स्वयं के स्वदेशी बाजार में संघर्ष कर रहा है।

xii. चीनी पाटन और उसकी विशाल उत्पादन क्षमता का दावा करने वाले घरेलू उद्योग की वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर प्रश्न खड़ा होता है जबकि यह अपने देश में क्षति का दावा कर रहा है।

xiii. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना क्षति अवधि के दौरान निर्यात मात्रा में गिरावट को दर्शाती है।

xiv. पूरी क्षति अवधि के दौरान घरेलू बिक्री कीमत और निर्यात बिक्री कीमत में प्रवृत्ति समान बनी रही हैं।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

i. यह दावा कि टेकनोवा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए संपूर्ण आधारभ्लूत संरचना से लागत को प्राप्त कर रहा है, गलत है। केवल पीयूसी के उत्पादन के साथ सीधे संबद्ध लागतों को ही रिपोर्ट किया गया है।

ii. यह तर्क कि नए उत्पादक जैसे कि एचएल प्रिंटेक, घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा सृजित कर रहे हैं, खारिज कर दिया गया है। एचएल प्रिंटेक का बाजार हिस्सा न्यूनतम है और इसका घरेलू उद्योग के निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं है।

iii. यह दावा कि घरेलू उद्योग को निर्यात हानियों के कारण क्षति हुई है, अप्रासंगिक है क्योंकि क्षति संबंधी विश्लेषण विशेष रूप से घरेलू बिक्रियों से संबंधित है। टेकनोवा की निर्यात बिक्रियां इसके समग्र व्यापार के छोटे से भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसका, इसके वित्तीय निष्पादन पर बहुत कम प्रभाव है।

iv. जहां महामारी के दौरान मांग में गिरावट आई थी, संबद्ध देशों से आयातों में कमी के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन में मामूली सी कमी आई है। हालांकि, जैसे-जैसे स्थितियां सामान्य हो गई हैं, पाटित आयातों में फिर से उछाल आया है, जिस कारण जांच की अवधि के दौरान बिक्रियों में गिरावट आई।

v. कुप्रबंधन और खराब व्यापार निर्णयों के कारण हुई क्षति के दावों का साक्ष्य द्वारा समर्थन नहीं किया गया है। घरेलू उद्योग ने प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने के लिए लगातार विवेकपूर्ण निर्णय लिए हैं और क्षति प्रत्यक्ष रूप से गहन पाटन के कारण है।

vi. विवाद ने आपूर्ति श्रृंखला को विघटित कर दिया है और कीमतों में वैश्विक रूप से वृद्धि की है किन्तु इसने जांच में सभी पक्षकारों को समान रूप से प्रभावित किया है। विवाद ने पाटन पैटर्न को प्रभावित नहीं किया क्योंकि आयात कीमतें उसी दर से नहीं बढ़ी हैं जिस दर से उत्पादन लागतें बढ़ी हैं, जो भू-राजनीतिक मुद्दों के बावजूद पाटन के जारी रहने की ओर संकेत करता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

239. नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ-साथ, सब्सिडी वाले आयातों के अलावा किसी भी ज्ञात कारकों की जांच करना आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि इन अन्य कारकों से होने वाली क्षति को सब्सिडी वाले आयातों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके-

240. <u>तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य:</u> प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों के अलावा अन्य देशों से आयात नगण्य है। इसलिए, तीसरे देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता।

241. <u>मांग में संकुचलन और खपत का पैटर्न</u> - प्राधिकारी नोट करते हैं कि मामूली गिरावट के साथ संबद्ध वस्तुओं की मांग स्थिर बनी हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन से

आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकते। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है कि जिसे घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही क्षति का कारण माना जा सके।

242. <u>प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां-</u> ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धति अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके। घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग सहित घरेलू उत्पादकों ने संबद्ध देशों से आयातों में प्रतिस्पर्धा का सामना किया है।

243. <u>प्रौद्योगिकी का विकास</u> - किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सके।

244. <u>कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन-</u> प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का एक संभव कारण प्रतीत नहीं होता। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी ने केवल क्षति के आकलन के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि के निष्पादन पर विचार किया है।

245. <u>निर्यात निष्पादन</u>: प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के केवल क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू प्रचालनों के निष्पादन पर विचार किया है।

246. घरेलू उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण रणनीति और अन्य प्रबंधन निर्णय: प्राधिकरण ने नोट किया है कि इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने खराब मूल्य निर्धारण रणनीति अपनाई है जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता में कमी आई है। इस संबंध में, प्राधिकरण क्षति के लिए ऐसे किसी भी कारण की पहचान करने में असमर्थ है।

ञ. <u>भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे</u>

क. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

247. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग, विशेषकर टेकनोवा नियमित गुणवत्ता और आपूर्ति विघटन संबंधी मुद्दों का सामना कर रहा है। समस्याएं जैसे स्पॉट संबंधी मुद्दे, लाइनिंग संबंधी मुद्दे और संवेदनशीलता संबंधी भिन्नता टेक्नोवा की प्लेट्स के संबंध में रिपोर्ट की गई है। इसके विपरीत, आयातित प्लेट्स सतत गुणवत्ता प्रस्तुत करती हैं जिससे वे विश्वसनीय प्रिंटिंग आउटपुट की मांग करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए बेहतर बन जाती हैं। इन मुद्दों तथा स्पष्ट मांग-आपूर्ति अंतर के बावजूद, टेकनोवा सहित घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन को बढ़ाने अथवा उत्पाद गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए हैं।

ii. टेकनोवा, आग्फा के साथ भागीदारी में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता को बनाए रखने अथवा उत्पादन को पर्याप्त रूप से विस्तार करने में असफल रहा है जबकि प्रतिबंध चीन जैसे देशों से उत्पादकों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोकते हैं।

iii. पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने से आयातों की लागत को बढ़ाने से विचाराधीन उत्पाद पर निर्भर उद्योगों के लिए लागतों में वृद्धि हो सकती है। यह लागत वृद्धि प्रिंटेड सामग्री, पैकेजिंग और संबंधित उत्पादों के लिए कीमतों में वृद्धि कर सकती है, जिसका बोझ अंतत: प्रयोक्ताओं पर पड़ेगा।

iv. उच्च कीमतें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों रूपों में पब्लिशिंग क्षेत्र और भारतीय प्रिंटिंग उद्योग की प्रतिस्पर्धा में कमी कर सकती हैं और ऐसे उद्योगों के लाभ-मार्जिन को नुकसान पहुंचा सकती हैं जो बहुत कम मार्जिन पर काम करते हैं।

v. यदि घरेलू उत्पादन मांग को पूरा नहीं कर पाते तो शुल्क आपूर्ति श्रृंखला को विघटित कर सकते हैं, विशेषकर ऐसी कंपनियों के लिए जिन का मार्जिन बहुत कम है और डीओपीपी की सस्ती और स्थिर आपूर्ति पर निर्भर करते हैं।

vi. यदि घरेलू उत्पादन मांग कोपूरा नहीं कर सकते तो पाटनरोधी शुल्क के कारण बढ़ी हुई लागत की वजह से उत्पादन में विलंब, आउटपुट में कमी अथवा प्रयोक्ता उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आ सकती है। इसके वृहत आर्थिक प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए क्योंकि प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग भारत में रोजगार तथा अधीनस्थ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। एसमएसएमई को विशेषरूप से उच्च इनपुट लागत के साथ संघर्ष करना होगा जो उनकी वित्तीय स्थिरता और संवृद्धि पहलुओं के लिए संकट पैदा करेगा।

vii. शुल्कों को जारी रखने से डीओपीपी पर निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए प्रचालन संबंधी लागतों में वृद्धि होगी जो सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा और वृहत अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भरता को जारी रखना जरूरी है और पाटनरोधी शुल्क को लागू किया जाना घरेलू उद्योग के संघर्ष के मूल कारण का पता लगाए बिना डाउनस्ट्रीम उद्योग को हानि पहुंचाएगा।

viii. चीनी विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित डिजीटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स उत्तम क्वालिटी की हैं। टेकनोवा के उत्पादों में आने वाली तकनीकी समस्याओं का सामना किए बिना जिसमें पुरानी तकनीक का प्रयोग किया गया था।

ix. प्रिंटिंग उद्योग में रन-लैंथ पर आधारित प्रचालनों के विभिन्न प्रकार शामिल हैं। बड़ी मात्रा (उदा. समाचार पत्र) के लिए लांग-रन जहां प्लेट लागत संचालन संबंधी व्यय का एक बहुत छोटा भाग है। ब्रोशर्स और केटेलॉग जैसी प्रिंट मात्राओं के लिए मीडियम रन्स, जो संभवत: पारंपरिक ऑफसेट प्रिंटिंग की उच्च स्थापना लागत का औचित्य सिद्ध नहीं कर सकती। iii. मांग पर या सीमित मात्राओं (जैसे बिजनेस कार्ड्स) के लिए मांग पर शॉर्ट रन्स, जहां प्लेट की लागत कुल व्यय का 85% तक हो सकती है जिससे प्रक्रिया परिवर्तन प्रभावशाली हो जाता है।

x. डिजीटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने से कच्चे माल की लागतों में वृद्धि और एक पहले से कीमत-संवेदनशील बाजार में लाभ मार्जिन को और अधिक कम करने के द्वारा पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करेगा।

xi. बढ़ी हुई लागत प्लेट ब्यूरोज और प्रि-प्रेस हाउसिस को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी जो डिजीटल ऑफसेट प्लेट्स पर अत्यधिक भरोसा करते हैं। शुल्कों को लगाने से उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है।

xii. स्थानीय विनिर्माताओं की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है किन्तु यह दावा कि इस क्षेत्र में भारत की आत्म-निर्भरता के लिए पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना महत्वपूर्ण है, निराधार है।

xiii. xiii. घरेलू उद्योग को पहले से ही काफी समय तक एंटी-डंपिंग ड्यूटी के माध्यम से संरक्षण प्राप्त है। मांग-आपूर्ति के अंतर को देखते हुए, डाउनस्ट्रीम उद्योग के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

i. पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने का डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि औसत शुल्क 20% है जो समाचार पत्र, व्यापारिक और पैकेजिंग प्रिंटिंग जैसे खंडों में प्रिंट जॉब की औसत लागत को केवल 0.5% से 1.5% में बदल सकता है। शुल्क का विरोध करने वाले किसी भी उपभोक्ता ने शुल्कों से किसी सार्वजनिक हित के विपरीत प्रभाव को नहीं दर्शाया है।

ii. शुल्कों को समाप्त कर देने से घरेलू उद्योग को बन्द करना पड़ेगा, जो कि प्रिंटिंग क्षेत्र में भारत की आत्म-निर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है, मीडिया, पब्लिशिंग और पैकेजिंग जैसे उद्योगों के लिए अनिवार्य है।

iii. डीओपीपी बाजार में प्राय: माल की तत्काल आवश्यकता होती है विशेषकर समाचार पत्र और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में। आयातों पर निर्भरता, विलंब, गुणवत्ता संबंधी मुद्दों और कीमत में अस्थिरता के जोखिमों को जन्म देती हैं जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अस्वीकार्य हैं।

iv. घरेलू उद्योग ने अत्यावश्यक मांगो को कुशलतापूर्वक पूरा करने की अपनी क्षमता को सिद्ध किया है जैसा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखा गया है।

v. लॉकडाउन के दौरान, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं विघटित हो गई थी किन्तु भारतीय समाचार पत्र ने घरेलू रूप से उत्पादित डीओपीपी की उपलब्धता के कारण कार्य करना जारी रखा।

vi. आयातों के अनुपलब्ध होने के कारण, राष्ट्र घरेलू विनिर्माताओं पर निर्भर था जो राष्ट्रीय सुरक्षा और अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने के लिए एक सुदृढ़ घरेलू उद्योग के महत्व को दर्शाता है।

vii. डीओपीपी के सामरिक महत्व के बावजूद, घरेलू उद्योग कृत्रिम रूप से निम्न कीमतों पर बेचे जा रहे पाटित आयातों के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।

viii. आयात घरेलू विनिर्माताओं की कीमतों में उल्लेखनीय रूप से कटौती कर रहे हैं और घरेलू उद्योग के लिए प्रचालन को जारी रखने को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बना रहे हैं।

ix. घरेलू संयंत्रों को बंद करने के परिणामस्वरूप नौकरियों की महत्वपूर्ण हानि होगी और यह भारत को आयातों पर पूर्ण रूप से निर्भर बनाएगा।

x. यह भारत को भविष्य की आपात स्थितियों का उत्तर देने की क्षमता को संकट में डालेगा जिसमें त्वरित और विश्वसनीय आपूर्ति की जरूरत होती है।

xi. पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उत्तम गुणवत्ता के कारण आयातित प्लेट्स को प्राथमिकता दी जाती है जबकि घरेलू प्लेट्स में प्राय: गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उत्पन्न हो जाते हैं। घरेलू उद्योग ने नोट किया है कि टेकनोवा की अस्वीकृति दर सबसे कम है और जोर दिया है कि पाटनरोधी शुल्कों का अभिप्राय उचित कीमत निर्धारण को सुनिश्चित करना है न कि उत्पाद गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धा को सीमित करना।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

248. प्राधिकारी ने विचार किया है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने से सार्वजनिक हित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राकधिकारी ने जांच की है कि क्या जांचाधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार वृहत सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। यह निर्धारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के विचार तथा विभिन्न पक्षकारों, जिनमें घरेलू उद्योग, आयातक और उत्पाद के उपभोक्ता शामिल हैं, के संबंध में किए गए विचार पर आधारित है।

249. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मत को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की है जिसमें आयातक, उपभोक्ता ओर अन्य हितबद्ध पक्षकार शामिल हैं। प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें उनके संचालनों पर पाटनरोधी शुल्कों के संभावित प्रभाव शामिल हैं, उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर विनिमेयता, उपभोक्ताओं की स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव, कारक जिनके द्वारा पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने के कारण उत्पन्न हुई नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित अथवा विलंबित करने की संभावना है, पर सूचना की मांग की है।

250. यह नोट किया जाता है कि सामान्य रूप से पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी ने माना है कि पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने से विचाराधीन उत्पाद तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग करके विनिर्मित किए गए अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में पाटनरोधी उपायों को लागू करने से उचित

प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखना घरेलू उद्योग की गिरावट को रोकेगा जो संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप घटित हो सकती है और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं को चयन की विस्तृत उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

251. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की है जिसे इस समीक्षा जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग और कोडक समूह ने ही आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के साथ ही प्रयोक्ता उद्योग से संबंधित सूचना की आपूर्ति की है।

252. यह भी दावा किया गया है कि देश में एक मांग और आपूर्ति अंतर विद्यमान है। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को न्यायसंगत सिद्ध नहीं करता। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों को आयातों को अवरुद्ध करने के लिए लागू नहीं किया गया बल्कि घरेलू बाजार में समान स्तर पर व्यापार करने की स्थिति को सृजित करने के लिए शुल्क लागू किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ता उद्योग उचित कीमतों पर आयात को जारी रख सकते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों पर अत्यधिक निर्भर रहने को उपेक्षित करने के लिए प्रयोक्ता उद्योग के लिए एक व्यवहार्य घरेलू उद्योग की उपस्थिति जरूरी है (घरेलू उत्पादन के 95% से अधिक के लिए उत्तरदायी एकमात्र बड़ा उत्पादक होने के कारण) जिस कारण आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की संभावना बढ़ गई है।

253. इच्छुक पक्षों ने दावा किया है कि घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों में स्पॉट इश्यू, लाइनिंग इश्यू और संवेदनशीलता भिन्नता आदि जैसे गुणवत्ता संबंधी मुद्दे हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उद्योग में अस्वीकृति दर सबसे कम है और इस संबंध में प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत किया है। प्राधिकरण ने नोट किया कि व्यापार सुधारात्मक उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उत्पाद, चाहे वे घरेलू हों या आयातित, उचित मूल्य पर हों और अनुचित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से घरेलू उद्योग को नुकसान न पहुँचाएँ।

254. प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि कैसे संबद्ध वस्तुओं ने उपभोक्ताओं को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने मात्रा संबंधी जानकारी प्रस्तुत की है, यह दर्शाते हुए कि प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि वर्तमान लागू पाटनरोधी शुल्क (20% की औसत दर मानते हुए) प्रमुख अंतिम प्रयोग

खंड जैसे समाचार पत्र, प्रिंटिंग खंड, व्यापारिक प्रिंटिंग खंड और पैकेजिंग प्रिंटिंग खंड, में एक प्रिंट जॉब की औसत लागत के केवल 0.5% से 1.5% की लागत वृद्धि में बदल जाता है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव न्यूनतम है।

255. घरेलू उद्योग अपनी विनिर्माण क्षमता की सीमा तक हिन्दालकों से प्रमुख कच्चा माल (लिथे ग्रेड एल्यूमीनियम कॉयल) की अधिप्राप्ति करता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में कोई भी गिरावट लिथो ग्रेड एल्युमीनियम कॉयल्स के लिए हिन्दालको के प्रचालनों को विपरीत रूप से प्रभावित करेगी क्योंकि घरेलू उद्योग देश में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र बड़ा विनिर्माता है।

256. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पहले से ही पर्याप्त अवधि के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क के माध्यम से संरक्षण प्राप्त है, और इसलिए, प्रतिपूर्ति शुल्क की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिपूर्ति शुल्क का अधिरोपण केवल घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा तक ही होगा, अर्थात, जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग के लिए गणना की गई क्षति मार्जिन। इसलिए, शुल्कों का समानांतर अधिरोपण कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण हुई क्षति की भरपाई करता है।

257. कई इच्छुक पक्ष, जो जांच में पंजीकृत भी नहीं हैं, ने इस विलम्बित चरण में पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि डीओपीपी की लागत उनके अंतिम उत्पाद लागत का 30-40% है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने सबसे पहले यह नोट किया कि इस तरह के विलंबित प्रस्तुतीकरणों को स्वीकार करना उचित नहीं है, विशेष रूप से वे जो नए तथ्यात्मक दावे पेश करते हैं, क्योंकि इससे अन्य इच्छुक पक्षों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी, प्राधिकारी ने इन प्रस्तुतीकरणों की समीक्षा की है और पाया है कि उपयोगकर्ताओं ने केवल अपने लागत ढांचे में डीओपीपी के हिस्से का दावा किया है, इसके वास्तविक प्रभाव का कोई परिमाणीकरण प्रदान किए बिना।

ट. <u>प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियाँ</u>

क. अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुतियां

258. इच्छुक पक्षों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी हैं:

i. प्राधिकरण ने कोडक चाइना के लिए नकारात्मक क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। तदनुसार, कम शुल्क नियम के अनुसार, कोडक चाइना के लिए शून्य प्रतिपूरक शुल्क की सिफारिश की जानी चाहिए।

ii. चूंकि वर्तमान सी.वी.डी. जांच की पी.ओ.आई. हाल ही में संपन्न एंटी-डंपिंग सनसेट समीक्षा जांच के समान है, इसलिए प्राधिकारी को सुसंगत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा सी.वी.डी. जांच के अंतिम निष्कर्षों में लकी एच.जी. तथा के.सी.जी.सी.एल. के लिए अलग-अलग मार्जिन निर्धारित करना चाहिए।

iii. प्राधिकरण ने सही ढंग से निर्धारित किया है कि लकी और कोडक शुल्क की अलग-अलग दरों के हकदार हैं। लकी और कोडक अलग-अलग कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं, जिनके स्वतंत्र संचालन और अलग-अलग निर्यात हैं। कोडक के स्वामित्व में परिवर्तन को पिछली जांचों में ध्यान में रखा गया था और अलग-अलग शुल्क लगाए गए थे। चूंकि तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है और निष्पक्षता और WTO सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए, इस जांच में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

iv. ईकेसी और केआईपीएल ने निर्धारित समय सीमा के भीतर गोपनीय और अगोपनीय आर्थिक हित प्रश्नावली का जवाब दाखिल कर दिया है।

v. लकी के लिए गणना की गई सब्सिडी और क्षति मार्जिन अत्यधिक उच्च है तथा प्राप्त वास्तविक लाभ से अधिक है।

vi. लकी को मिले निर्यात अनुदान (योजना 1 और 3) को एंटी-डंपिंग ड्यूटी में शामिल किया गया है। प्रतिकारी शुल्क से वही लाभ नहीं मिलना चाहिए।

vii. एल.टी.ए.आर. में एल्युमीनियम मूल्य बेंचमार्क बहुत अधिक है। लकी ने चीन में बाजार दरों पर एल्युमीनियम खरीदा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया जाए, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ($3600-$3700) के डेटा पर आधारित होना चाहिए। थोक खरीद के कारण लकी को छूट भी प्रदान की जाती है। यह एक व्यावसायिक रणनीति है और इसे लकी के नुकसान के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

viii. इस माननीय प्राधिकारी ने सही पाया कि कर और वैट प्रोत्साहन के लिए कोई सब्सिडी मार्जिन नहीं है क्योंकि लकी को इन योजनाओं के तहत लाभ नहीं मिला

ix. चूंकि गैर-हानिकारक मूल्य और शुद्ध बिक्री प्राप्ति मेल खाते हैं, इसलिए आयात कीमतें घरेलू उत्पादकों को नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं।

x. बाजार की स्थितियों में परिवर्तन, जैसे कम ब्याज और कॉर्पोरेट कर की दरें, को देखते हुए 22% नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) अनुचित है।

xi. याचिका और प्रकटीकरण विवरण में लागत डेटा के बीच विसंगतियां याचिकाकर्ता की डेटा अखंडता पर सवाल उठाती हैं।

xii. अन्य आर्थिक कारक, जैसे आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे, महामारी के बाद की रिकवरी और याचिकाकर्ता के अपने व्यावसायिक निर्णय, किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार हैं। क्षति को केवल आयात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

xiii. फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("FFIN") फुजीफिल्म प्लेटों का ब्रांड मालिक है और चीन पीआर से आयातित थर्मल और वायलेट प्लेटों के व्यापार में लगा हुआ है। FFIN का बिक्री मूल्य औसतन TechNova की तुलना में 10%-15% प्रति वर्गमीटर अधिक है। FFIN और Technova के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है जो दोनों कंपनियों की बिक्री मात्रा में भी दिखाई देती है। इसके अलावा, FFIN की प्लेटों की गुणवत्ता Technova से कहीं बेहतर है जिसके लिए FFIN बाजार में प्रीमियम मूल्य वसूलता है।

xiv. आवेदक प्रतिसंतुलन शुल्क नियमों के तहत "घरेलू उद्योग" के रूप में योग्य नहीं है। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक विषयगत वस्तुओं का नियमित आयातक है।

xv. आवेदक को चीन जन.गण. से विषयगत वस्तुओं के आयात के कारण कोई भौतिक क्षति नहीं हो रही है।

xvi. यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच की अवधि के लिए आवेदक के वित्तीय विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उन्होंने उचित लाभ अर्जित किया है।

xvii. बाजार आसूचना के अनुसार, आवेदक के कुल कारोबार में पीयूसी की घरेलू बिक्री का हिस्सा लगभग 95% है।

xviii. यह प्रस्तुत किया गया है कि चीन जन. गण. से आयात कीमतें क्षति की पूरी अवधि के दौरान काफी बढ़ गईं, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि आवेदक को चीन जन. गण. से विषयगत वस्तुओं के आयात के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

xix. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उद्योग का पीयूसी उत्पादन पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच अवधि में काफी बढ़ गया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आवेदक का पीयूसी उत्पादन वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 93 सूचकांक अंक हो गया।

xx. यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उद्योग के घरेलू विक्रय मूल्य में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में 32% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

xxi. आवेदक उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता में तत्काल पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में जांच अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

xxii. आधार वर्ष की तुलना में आवेदक की औसत इन्वेंट्री में जांच अवधि में लगभग 45% की उल्लेखनीय गिरावट आई।

xxiii. एचएल प्रिंटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक नए उत्पादक ने वित्त वर्ष 2020-21 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया। एचएल प्रिंटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का उत्पादन वित्त वर्ष 2020-21 में 100 सूचकांक अंकों से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 431 सूचकांक अंकों तक पहुंच गया, यानी लगभग 3.3 गुना की वृद्धि हुई। अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से जांच अवधि के दौरान 167345 सूचकांक अंकों तक बढ़ गई। अन्य भारतीय उत्पादकों, मुख्य रूप से नए घरेलू उत्पादक (एचएल प्रिंटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा मूल्य निर्धारण नीति में भेदन करना आवेदक को हुई क्षति, यदि कोई हो, का वास्तविक कारण है।

xxiv. आवेदक उद्योग की पीयूसी की निर्यात बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में लगभग 22% की उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे प्रति इकाई स्थिर लागत में वृद्धि हुई। आवेदक उद्योग को यदि कोई क्षति हुई है, तो वह निर्यात बिक्री में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुई है।

xxv. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि एफएफपीएस को केवल उन योजनाओं के तहत लाभ मिला है जो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। एफएफपीएस को किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं मिला है। इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभ न तो एएससीएम के अनुच्छेद 3 के अनुसार निषिद्ध सब्सिडी है और न ही यह प्रतिसंतुलन योग्य है।

xxvi. यह भी पाया गया है कि योजनावार मार्जिन भी प्रदान नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों में, प्रतिवादी प्रकटीकरण विवरण में प्रस्तावित सब्सिडी मार्जिन पर अपनी पूरी टिप्पणी दर्ज करने में सक्षम नहीं हैं।

xxvii. संयुक्त राष्ट्र के औसत COMTRADE मूल्य पर विचार करना न केवल अतार्किक है, बल्कि निम्नलिखित कारणों से पूरी तरह अप्रासंगिक और अवैध है: औसत विश्व मूल्यों को बेंचमार्क नहीं माना जा सकता है; एक उपयुक्त देश पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कथित LTAR वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री की वही स्थितियाँ हों, जो चीन पीआर में प्रचलित हैं; अमेरिका की कार्यप्रणाली कानून, अभ्यास और प्रक्रिया के संदर्भ में पूरी तरह से अलग है। इसलिए हमें लागू की गई वास्तविक कार्यप्रणाली का विवरण दिए बिना इसे अपनाना स्वीकार्य नहीं होगा।

xxviii. विस्तृत कार्यप्रणाली हमें उपलब्ध कराए जाने के बाद प्राधिकरण का यह दायित्व होगा कि वह हमें उचित सुनवाई का अवसर दे। यह दोहराया जा सकता है कि आवेदक ने बिना किसी विवरण के केवल अमेरिकी निष्कर्षों का संदर्भ दिया है।

xxix. यह भी ध्यान देने योग्य है कि एलटीएआर स्थापित करने की जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से आवेदक पर है। इसके अलावा, चीन के लिए कानून की कठोर आवश्यकता डब्ल्यूटीओ के किसी भी अन्य सदस्य के लिए समान है क्योंकि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का सिद्धांत सब्सिडी और प्रतिपूरक उपायों पर समझौते के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होता है।

xxx. एफएफपीएस ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक एल्युमीनियम नहीं खरीदा है। एफएफपीएस ने केवल एल्युमीनियम शीट और फॉयल ही खरीदा है।

xxxi. एफएफपीएस ने असंबद्ध निजी आपूर्तिकर्ताओं से आर्म्स लेंथ मूल्य पर एल्युमीनियम कॉइल खरीदे हैं। मूल्य निर्धारण शंघाई नॉन-फेरस एसएमएम ए00 एल्युमीनियम, चांगियांग स्पॉट ए00 एल्युमीनियम और शंघाई फ्यूचर एल्युमीनियम के संदर्भ मूल्य निर्धारण पर आधारित है। संदर्भ मूल्य निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है।

xxxii. निर्यात कर अपने आप में सब्सिडी नहीं है। अगर ऐसा है तो जांच की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि निर्यात कर को केवल सब्सिडी माना जाएगा।

xxxiii. एलटीएआर पर माल के सरकार द्वारा सौंपे गए/निर्देशित प्रावधान के रूप में निर्यात कर/प्रतिबंध का उपचार डब्ल्यूटीओ-असंगत है क्योंकि सरकार द्वारा "वित्तीय योगदान" के अस्तित्व की कमी है, जैसा कि पैनल ने यूएस - निर्यात प्रतिबंधों में उल्लेख किया है ।

xxxiv. पैनल ने विशेष रूप से "वित्तीय योगदान" के निर्धारण के लिए प्रभाव-आधारित दृष्टिकोण को खारिज कर दिया और कहा कि "वित्तीय योगदान की धारणा को पेश करके, मसौदा तैयार करने वालों ने किसी भी सरकारी कार्रवाई के उपचार की संभावना को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप सब्सिडी के रूप में लाभ हुआ ।" इसके अतिरिक्त, पैनल ने इस बात पर जोर दिया कि " ऐसा नहीं हो सकता कि एससीएम समझौते के तहत किसी सदस्य सरकार के उपाय की प्रकृति केवल उन लोगों द्वारा उस उपाय पर की गई प्रतिक्रिया के आधार पर निर्धारित की जाए जो इससे प्रभावित हैं। इसके बजाय, सरकार द्वारा वित्तीय योगदान के अस्तित्व को सरकार की कार्रवाई के संदर्भ में साबित किया जाना चाहिए ।" बाद के प्रस्ताव को 6कनाडा - एयरक्राफ्ट में एबी द्वारा आगे भी बरकरार रखा गया ।

---

[6]यू.एस. - *निर्यात प्रतिबंध*, पैनल रिपोर्ट, पैरा 8.34.

xxxv. कनाडा - एयरक्राफ्ट (डीएस 70), चीन - विभिन्न कच्चे माल के निर्यात से संबंधित उपाय (डीएस 394, डीएस 395, डीएस 398) के मामले में अपीलीय निकाय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है ।

xxxvi. अपीलीय निकाय के निर्णयों से पता चलता है कि निर्यात करों पर विचार किया जा सकता है यदि: कर निर्यातकों को वित्तीय लाभ प्रदान करके बाजार को विकृत करता है; कर विशेष रूप से निर्यात को प्रोत्साहित करने और विदेशों में बेची जाने वाली वस्तुओं की प्रभावी कीमत को कम करने के लिए बनाया गया है; निर्यात कर का उपयोग अन्य उपायों (जैसे निर्यात वित्तपोषण या छूट) के संयोजन में किया जाता है जो इसके सब्सिडी जैसे प्रभावों को बढ़ा सकते हैं।

xxxvii. एससीएम समझौते का अनुच्छेद 1.1 जिसे कथित तौर पर सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9 में स्थानांतरित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि यदि सरकार द्वारा वित्तीय योगदान दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता को लाभ होता है, तो सब्सिडी मौजूद होती है। यूएस - सॉफ्टवुड लम्बर IV में अपीलीय निकाय ["एबी"] ने उल्लेख किया कि सब्सिडी मौजूद होने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय योगदान होना चाहिए और उस वित्तीय योगदान से लाभ मिलना चाहिए।

xxxviii. इसके अतिरिक्त, एससीएम समझौते के अनुच्छेद 1.2 और सीमा शुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9 के अनुसार, सब्सिडी का प्रतिकार केवल तभी किया जा सकता है जब वह "विशिष्ट" हो।

xxxix. प्रभाव-आधारित दृष्टिकोण अर्थात निर्यात कर लगाने के अनुसार वित्तीय योगदान के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है । वास्तव में, आवेदक उद्योग का एल.टी.ए.आर. पर एल्युमीनियम शीट के सरकारी सौंपे गए या निर्देशित प्रावधान का दावा, डब्ल्यू.टी.ओ. विवाद यू.एस. - निर्यात प्रतिबंध में यू.एस. के समान आधारों पर आधारित है, जिसे उस विवाद में पैनल द्वारा खारिज कर दिया गया था।

xl. यह प्रस्तुत किया गया है कि यू.एस.-डीआरएएम (सी.वी.डी.) में ए.बी. ने उल्लेख किया है कि "अनुच्छेद 1.1(ए)(1) [एससीएम समझौते का] स्पष्ट करता है कि सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा "वित्तीय योगदान" एससीएम समझौते के तहत "सब्सिडी" का एक अनिवार्य घटक है। अनुच्छेद 1.1(ए)(1) के तहत किसी भी उत्पाद को सब्सिडी नहीं दी जा सकती है, न ही सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय योगदान की अनुपस्थिति में इसे प्रतिपूर्ति की जा सकती है।"

xli. यह प्रस्तुत किया गया है कि यूएस - निर्यात प्रतिबंधों में पैनल ने नोट किया कि अनुच्छेद 1.1 (ए) (1) (iv) में उल्लिखित पांच संचयी तत्वों को "वित्तीय योगदान" के अस्तित्व का पता लगाने के लिए प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

xlii. जैसा कि दर्शाया गया है, वर्तमान मामले में इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया है। आवेदक उद्योग सौंपे जाने या निर्देश देने की आवश्यकता के अस्तित्व को स्थापित करने में विफल रहा है।

xliii. आवेदक उद्योग, कथित निर्यात प्रतिबंधों के माध्यम से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग उद्योग को कोई नीतिगत समर्थन प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप एल.टी.ए.आर. में एल्युमीनियम शीट्स का प्रावधान है।

xliv. निजी निकायों को सौंपने या निर्देश देने वाले किसी भी सकारात्मक कार्य की अनुपस्थिति का तात्पर्य यह होगा कि किसी भी वृहद आर्थिक नीति को सौंपना या निर्देश देना माना जा सकता है और किसी भी सरकारी नीति के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ को वित्तीय योगदान के बराबर माना जा सकता है, जिसे एबी ने स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

xlv. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उद्योग चीन पीआर में एल्युमीनियम शीट्स के निर्यात प्रतिबंधों और कीमतों के बीच संबंध स्थापित करने में विफल रहा है। इसके अलावा, आवेदक उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि चीन पीआर की सरकार द्वारा लगाए गए निर्यात कर ने एल्युमीनियम शीट्स के चीनी उत्पादकों को चीनी बाजार में एलटीएआर पर अपना उत्पाद बेचने के लिए मजबूर किया या उनकी कीमतें तय करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया।

xlvi. आवेदक व्यापार सुधारात्मक उपायों का दुरुपयोग कर रहा है, जिसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि दिसंबर 2012 से यानी लगभग 11.5 वर्षों से शुल्क लागू हैं और फिर भी वे आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, एसएसआर शुल्क को पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि उन्हें कोई नुकसान हुआ है, तो वह उनके आंतरिक कुप्रबंधन के कारण है। ऐसे मामले में, सीवीडी शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

xlvii. उत्पादक/निर्यातक ने कहा कि यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 महामारी ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान वैश्विक व्यापार को काफी प्रभावित किया, जिससे आयात मात्रा में असामान्य उतार-चढ़ाव हुआ। विशेष रूप से, महामारी के व्यवधानों के कारण इन वर्षों के दौरान आयात मात्रा में गिरावट आई। हालांकि, पीओआई के दौरान, आयात मात्रा महामारी से पहले

के स्तर पर लौट आई, जिसे वास्तविक वृद्धि के रूप में नहीं बल्कि महामारी की असाधारण स्थितियों के बाद आयात गतिविधि के सामान्यीकरण के रूप में देखा जाना चाहिए।

xlviii. इसके अतिरिक्त, हालांकि चीन से आयात में आधार वर्ष 2019-20 में 14,124,139 वर्गमीटर से जांच अवधि के दौरान 14,455,372 वर्गमीटर तक मामूली वृद्धि देखी गई (2% की वृद्धि), यह वृद्धि न्यूनतम है। दूसरी ओर, अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2019-20 में 100 वर्गमीटर से जांच अवधि के दौरान 167,345 वर्गमीटर हो गई। अन्य उत्पादकों द्वारा बिक्री में इस पर्याप्त वृद्धि ने घरेलू उद्योग की बिक्री को प्रभावित किया हो सकता है, जिसमें 100 वर्गमीटर से 94 वर्गमीटर तक मामूली गिरावट देखी गई।

xlix. प्रकटीकरण वक्तव्य में ताइवान सरकार द्वारा दिए गए तर्कों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है। डीजीटीआर को एससीएम समझौते के अनुच्छेद 22.5 के तहत अपने दायित्व का पालन करना चाहिए और अंतिम निर्धारण के नोटिस में ऐसे कारण बताने चाहिए।

l. डीजीटीआर को वर्तमान जांच में उपलब्ध तथ्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताइवान सरकार ने डीजीटीआर को सी.वी.डी. निर्धारण करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा दी है।

li. यदि डीजीटीआर उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करने का निर्णय भी ले, तो उसे एससीएम समझौते के अनुच्छेद 12.7 और सुस्थापित डब्ल्यूटीओ मामले विनियमों के अनुसार एकत्रित सभी सूचनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक उचित प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए।

lii. ताइवान सरकार के विचार में , इस जांच के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी सर्वोत्तम जानकारी है और इस प्रकार इसे अनुपस्थित जानकारी के लिए सबसे उचित प्रतिस्थापन के रूप में काम करना चाहिए ।

liii. ताइवान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर , विषयगत वस्तुओं के ताइवान उद्योग, जिसमें एक ही कंपनी, टॉप हाई इमेज कॉर्पोरेशन (टॉप हाई) शामिल है, को किसी भी कथित सब्सिडी कार्यक्रम से लाभ नहीं मिला।

liv. अधिक विशेष रूप से, टॉप हाई किसी भी औद्योगिक पार्क या विज्ञान पार्क में स्थित नहीं है जो कथित शुल्क और कर छूट कार्यक्रमों के हकदार हैं। ताइवान सरकार के रिकॉर्ड के आधार पर, टॉप हाई को कथित सरकारी अनुदान कार्यक्रमों के तहत कोई अनुदान भी नहीं मिला।

lv. डीजीटीआर को अपने अंतिम निर्धारण में ताइवान से संबंधित अपने निष्कर्षों को संशोधित करना चाहिए।

lvi. जीओसी ने यह दलील दी है कि प्रकटीकरण वक्तव्य के पैराग्राफ 3(iv) और 43 में प्राधिकरण का दावा, जिसमें दावा किया गया है कि लिखित संचार और परामर्श के माध्यम से चीन की सरकारों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, गलत है। विशेष रूप से, जीओसी का तर्क है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी जांच के लिए पूर्व-आरंभिक परामर्श हुआ है, लेकिन जांच में शामिल किए जाने से पहले नए कथित सब्सिडी कार्यक्रमों के बारे में जीओसी को कोई परामर्श निमंत्रण नहीं दिया गया था।

lvii. जीओसी ने दोहराया कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 9बी(1)(ए) के अनुसार किसी भी उत्पाद पर एक ही डंपिंग या सब्सिडी की स्थिति के लिए प्रतिपूरक और डंपिंग रोधी शुल्क दोनों नहीं लगाए जाएं ।

lviii. जीओसी निर्यातक कंपनियों को सहायता देने के लिए अनुदान के प्रावधान के बारे में याचिकाकर्ता के आरोपों को दृढ़ता से खारिज करता है। ये दावे निराधार और निराधार हैं। ये कार्यक्रम कोई अनुचित लाभ नहीं देते हैं और न ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को विकृत करते हैं।

lix. विभिन्न उपयोगकर्ताओं ने प्राधिकरण को पत्र लिखकर कहा है कि डीओपीपी की लागत अंतिम उत्पाद/प्रिंट कार्य की लागत का 30-40% है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियां

259. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी हैं:

i. घरेलू उद्योग, पीयूसी के दायरे और घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्राधिकरण के आकलन से सहमत है।

ii. घरेलू उद्योग ने फिर से जोर दिया है कि वह वास्तव में हुई क्षति से परे सुरक्षा नहीं चाहता है। इसका उद्देश्य अनुचित लाभ या अधिक मुआवज़ा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और डंपिंग जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण होने वाली क्षति का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए।

iii. घरेलू उद्योग चीन जन.गण. से अनुदान और कर कार्यक्रमों का प्रतिकार करने के लिए प्राधिकरण की स्थिति से सहमत है।

iv. घरेलू उद्योग का कहना है कि प्राधिकरण को घरेलू उद्योग द्वारा आरोपित किसी भी सब्सिडी कार्यक्रम का प्रतिकार करना चाहिए, जिसके लिए सहयोगी पक्षों ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई है।

v. घरेलू उद्योग ने आगे कहा कि प्राधिकरण ने उचित पारिश्रमिक से कम पर भूमि, बिजली और कुछ एल्युमीनियम का प्रावधान करके सही तरीके से प्रतिपूर्ति की है। घरेलू उद्योग का कहना है कि यह दृष्टिकोण सही है और भारतीय कानून और विश्व व्यापार संगठन के न्यायशास्त्र के अनुरूप है।

vi. घरेलू उद्योग प्राधिकरण के इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि भूमि उपयोग अधिकार प्रदान करने की चीन की प्रणाली भारतीय कानून के तहत प्रतिपूरक सब्सिडी का गठन करती है। चूंकि चीन में भूमि राज्य के स्वामित्व वाली है और बाजार तंत्र के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आवंटित की जाती है, इसलिए भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ए)(iii) के तहत सरकार द्वारा प्रदान की गई वस्तु के रूप में योग्य है। प्राधिकरण ने थाईलैंड की औद्योगिक भूमि की कीमतों को बाजार आधारित बेंचमार्क के रूप में उचित रूप से इस्तेमाल किया, जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप एक अभ्यास है। कार्यक्रम धारा 9(3) और नियम 11 के तहत भी विशिष्ट है, क्योंकि भूमि उपयोग अधिकार चुनिंदा रूप से एल्यूमीनियम उत्पादकों और अन्य प्रोत्साहित उद्योगों को दिए जाते हैं। चीन से सीमित सहयोग के कारण, प्राधिकरण ने उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया। प्राधिकरण को 14 साल का औसत उपयोगी जीवन लागू करना चाहिए, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

vii. घरेलू उद्योग प्राधिकरण के इस निष्कर्ष से सहमत है कि चीन में बिजली पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम पर उपलब्ध कराई जाती है, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9(1)(ए)(iii) के तहत प्रतिपूरक सब्सिडी का गठन करती है। चूंकि बिजली की कीमत बाजार तंत्र के माध्यम से तय नहीं की जाती है और कोई आंतरिक बेंचमार्क मौजूद नहीं है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा संदर्भ के रूप में यूएन कॉमट्रेड निर्यात कीमतों का उपयोग उचित है और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप है। सब्सिडी भारतीय कानून और एएससीएम के तहत भी विशिष्ट है, क्योंकि तरजीही दरें केवल चयनित उद्योगों और क्षेत्रों को दी जाती हैं। घरेलू उद्योग गैर-सहकारी निर्यातकों सहित सभी चीनी उत्पादकों पर इस निष्कर्ष के निरंतर अनुप्रयोग का समर्थन करता है।

viii. घरेलू उद्योग प्राधिकरण के इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि चीन के निर्यात प्रतिबंध - जैसे प्राथमिक एल्युमीनियम पर 30% निर्यात शुल्क और अपूर्ण वैट छूट - कृत्रिम रूप से घरेलू एल्युमीनियम की कीमतों को दबाते हैं, जिससे डीओपीपी निर्माताओं जैसे डाउनस्ट्रीम उत्पादकों को लाभ होता है। ये सरकारी कार्रवाइयां बाजार की गतिशीलता को विकृत करती हैं, जिससे एल्युमीनियम पर्याप्त पारिश्रमिक (एलटीएआर) से कम पर उपलब्ध होता है। प्राधिकरण ने

सही ढंग से निष्कर्ष निकाला है कि जब निजी आपूर्तिकर्ता शामिल होते हैं, तब भी सरकार का प्रतिबंध लगाना सीमा शुल्क अधिनियम और एएससीएम की धारा 9(1)(ए)(iv) के तहत वित्तीय योगदान के बराबर होता है, क्योंकि यह निजी अभिनेताओं को रियायती दरों पर एल्युमीनियम बेचने का जिम्मा सौंपता है या निर्देश देता है। ये उपाय विशिष्ट, लक्षित और चीन की औद्योगिक नीति के अनुरूप हैं

ix. चीन में एल.टी.ए.आर. में एल्युमीनियम और अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योगों को भूमि, बिजली और एल्युमीनियम के प्रावधान को विभिन्न जांचों में यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया है।

x. प्राधिकरण ने गैर-सहकारी उत्पादकों के लिए 40-50% का सब्सिडी मार्जिन परिकलित किया है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने नोट किया है कि प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यक्रमों की इस आधार पर जांच नहीं की है कि किसी भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने उनका लाभ नहीं उठाया। घरेलू उद्योग का कहना है कि प्राधिकरण को सहयोगी उत्पादकों द्वारा लाभ नहीं उठाए गए कार्यक्रमों की भी जांच करनी चाहिए । सीवीडी नियमों के नियम 7(8) के तहत यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्ष आवश्यक जानकारी प्रदान करने में विफल रहते हैं या जांच में बाधा डालते हैं, प्राधिकरण उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा कर सकता है। उपर्युक्त कई कार्यक्रमों को चीन सरकार द्वारा संचालित आवर्ती सब्सिडी योजनाओं के रूप में जाना जाता है और यूएसडीओसी जैसे अन्य जांच प्राधिकरणों द्वारा उनका प्रतिकार किया गया है।

xi. ताइवान के लिए गणना की गई सब्सिडी मार्जिन के संबंध में, घरेलू उद्योग का तर्क है कि प्राधिकरण को सब्सिडी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करते समय एक सुसंगत और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि कई अन्य के लिए विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद केवल कुछ चुनिंदा प्रतिपूरक कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना चाहिए। उद्योग ने व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं - जिसमें नीति दस्तावेज, विश्व व्यापार संगठन की अधिसूचनाएं और अन्य अधिकार क्षेत्रों के निर्धारण शामिल हैं - जो विभिन्न ताइवानी सब्सिडी कार्यक्रमों के अस्तित्व और प्रतिपूरक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इन कार्यक्रमों को ताइवान सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, जिससे उनके अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया है। हालाँकि, प्राधिकरण ने केवल कुछ सीमित कार्यक्रमों के विरुद्ध ही कार्रवाई की है, बिना यह बताए कि समान स्तर पर मौजूद अन्य कार्यक्रमों को बाहर करने का कानूनी या साक्ष्य संबंधी औचित्य क्या है।

xii. ताइवान के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा असहयोग किए जाने तथा जांच अवधि (पीओआई) के दौरान आयात में पर्याप्त वृद्धि के मद्देनजर, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे काउंटरवेलिंग ड्यूटी नियमों के नियम 7(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा करें। इसमें (ए) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करना या (बी) चीन पीआर के लिए गणना किए गए अवशिष्ट मार्जिन को बढ़ाना शामिल है।

xiii. घरेलू उद्योग सब्सिडी वाले आयातों से होने वाली क्षति और क्षति के खतरे पर पुनः जोर देता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

260. एनआईपी की गणना में 22% आरओसीई को अपनाने के संदर्भ में, यह प्राधिकरण की मानक प्रथा के अनुसार है और प्राधिकरण नोट करता है कि वर्तमान मामले में अपवाद बनाने और इसकी प्रथा से विचलित होने के लिए कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है।

261. कई इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति आयात के कारण नहीं बल्कि कुछ अन्य कारकों के कारण है क्योंकि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट जारी है। इस संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि उन्होंने क्षति के मापदंडों के साथ-साथ गैर-आरोपण के मापदंडों की भी पूर्वगामी पैराग्राफ में विस्तार से जांच की है। इसलिए, संक्षिप्तता के लिए उन्हें यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

262. विभिन्न इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि देश में आयात मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण होता है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग-आपूर्ति का अंतर शुल्क न लगाने का आधार नहीं हो सकता, जैसा कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एनओसीआईएल लिमिटेड बनाम भारत सरकार के मामले में भी माना है।

263. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों और उसकी स्थिति पर पक्षकारों के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के साथ-साथ वर्तमान निष्कर्षों के पूर्वगामी पैराग्राफों में सी.वी.डी. नियमों के अंतर्गत उसकी स्थिति की विस्तार से जांच की है।

264. जनहित के प्रस्तुतिकरणों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्हें व्यापक जनहित का आकलन करना आवश्यक है, जिसमें अपस्ट्रीम उद्योग, घरेलू उद्योग के साथ-साथ उपयोगकर्ता उद्योग भी शामिल हैं।

265. दोहरे उपायों से संबंधित मुद्दे के संबंध में, प्राधिकरण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9बी(1)(ए) के तहत निहित दायित्व को नोट करता है, जो डंपिंग या निर्यात सब्सिडी की समान स्थिति की भरपाई के लिए एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग दोनों शुल्क लगाने पर रोक लगाता है। इस प्रावधान का उद्देश्य दोहरे उपाय से बचना है - *यानी* , एकल आर्थिक विकृति (*यानी* , निर्यात सब्सिडी के कारण निर्यात मूल्य में कमी और उसी कमी को फिर से डंपिंग मार्जिन के तहत कैप्चर किया जाना) की भरपाई के लिए ओवरलैपिंग शुल्क लगाना। इसलिए, सिद्धांत के लिए यह जांचना आवश्यक है कि क्या संबंधित सब्सिडी को पहले से ही डंपिंग मार्जिन में शामिल किया गया है, जिससे समायोजन की आवश्यकता हो।

266. प्राधिकरण ने कम शुल्क नियम के अनुसार, केवल क्षति मार्जिन की सीमा तक ही निश्चित शुल्क लगाने की सिफारिश की है। इसलिए, घरेलू उद्योग को हुई क्षति से अधिक कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

267. प्राधिकरण ने नोट किया कि पक्षों ने तर्क दिया है कि यूएन कॉमट्रेड से निर्यात मूल्यों पर निर्भरता, कम पारिश्रमिक पर वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधानों के लिए सब्सिडी मार्जिन की गणना के लिए एक बेंचमार्क के रूप में उचित नहीं है। यूएन कॉमट्रेड व्यवस्थित रूप से संकलित और व्यापक रूप से स्वीकृत व्यापार डेटा प्रदान करता है, जो उत्पाद श्रेणियों और समय अवधि में पारदर्शिता और स्थिरता प्रदान करता है, और उचित बाजार मूल्य के एक उचित संकेतक के रूप में कार्य करता है। सत्यापन योग्य इन-कंट्री बेंचमार्क की अनुपस्थिति में, यूएन कॉमट्रेड निर्यात मूल्यों का सहारा लेना डब्ल्यूटीओ न्यायशास्त्र के अनुरूप है और एलटीएआर मामलों में सब्सिडी मार्जिन की गणना के लिए एक पद्धतिगत रूप से ठोस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त, अन्य इच्छुक पक्षों में से किसी ने भी सब्सिडी मार्जिन की गणना के लिए सहायक साक्ष्य और तर्क के साथ कोई अन्य विश्वसनीय बेंचमार्क प्रदान नहीं किया है।

268. प्राधिकरण ने नोट किया है कि कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि उन्होंने कुछ प्रतिपूर्ति कार्यक्रमों के तहत कोई लाभ नहीं उठाया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राधिकरण ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सब्सिडी मार्जिन की गणना करने के

लिए सहकारी उत्पादकों द्वारा प्रदान की गई जानकारी और प्रतिक्रियाओं पर भरोसा किया है। जहां उपयुक्त हो, प्राधिकरण ने सीवीडी नियमों के नियम 7(8) के तहत उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है। उस सीमा तक, जहां उपयुक्त हो, सब्सिडी मार्जिन को विधिवत समायोजित किया गया है।

269. ताइवान सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों और गैर-सहकारी उत्पादकों के लिए गणना किए गए मार्जिन के संबंध में, प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक खंड में अपनी टिप्पणियों को विधिवत संबोधित किया है। इसने वर्तमान निष्कर्षों के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में सीवीडी नियमों के तहत कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनशीलता की विस्तार से जांच की है।

270. प्रोफार्मा IV-ए में निहित क्षति डेटा को इतनी देरी से बदलने के लिए विभिन्न इच्छुक पक्षों के आरोपों के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि प्रोफार्मा IV-ए में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए परिवर्तन सत्यापन के दौरान पहचाने गए सुधारों के कारण हैं, जो प्रकृति में बहुत छोटे हैं और समग्र क्षति मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए परिवर्तन वर्तमान जांच में क्षति मूल्यांकन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं। प्राधिकारी ने अद्यतन डेटा को रिकॉर्ड में लिया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के उद्देश्य के लिए उस पर भरोसा किया है।

271. विभिन्न सब्सिडी कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनशीलता के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने वर्तमान निष्कर्षों के पूर्ववर्ती पैराग्राफों में सी.वी.डी. नियमों के अंतर्गत कार्यक्रमों की प्रतिसंतुलनशीलता की विस्तार से जांच की है।

272. विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों को रिकॉर्ड में नहीं लिए जाने के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि सभी पक्षों के निवेदनों को विधिवत रूप से ध्यान में रखा गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि ई.के.सी. और के.आई.पी.एल. ने भी ई.आई.क्यू. दाखिल किया है, जिस पर विधिवत रूप से विचार किया गया है।

273. कई हितबद्ध पक्षों ने, जो जांच में पंजीकृत भी नहीं हैं, इस विलम्बित चरण में पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि डी.ओ.पी.पी. की लागत उनके अंतिम उत्पाद लागत का 30-40% है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि, सबसे पहले, ऐसे विलंबित निवेदनों को स्वीकार करना उचित नहीं है, विशेष रूप से वे जो नए तथ्यात्मक दावे पेश करते हैं, क्योंकि इससे अन्य हितबद्ध पक्षों के अधिकारों पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर भी, प्राधिकरण ने इन प्रस्तुतियों की समीक्षा की है और पाया है कि उपयोगकर्ताओं ने अपने लागत ढांचे में डीओपीपी के हिस्से का दावा मात्र किया है, तथा इसके वास्तविक प्रभाव का कोई परिमाणीकरण नहीं किया है।

ठ. निष्कर्ष

274. सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों तथा उनमें उठाए गए मुद्दों और रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों की जांच करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

275. प्रतिपूरक शुल्क जांच शुरू करने के लिए आवेदन टेक्नोवा इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

276. आवेदक सीवीडी नियमों के नियम 2(बी) के तहत एक पात्र घरेलू उद्योग है और भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसका है। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए आवेदक घरेलू उद्योग है।

277. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है।

278. पीयूसी के दायरे में तीन प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें शामिल हैं:

i. थर्मल प्लेटें
ii. बैंगनी प्लेटें
iii. सीटीसीपी/ यूवी सीटीपी प्लेट्स

279. चीन जन.स. और ताइवान की सरकारें पी.यू.सी. के उत्पादकों को अनुदान, कर लाभ, तथा वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान के रूप में अपर्याप्त पारिश्रमिक पर सब्सिडी प्रदान कर रही हैं।

280. पिछले वर्ष की तुलना में भारत में विषयगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। एंटी-डंपिंग शुल्क के अस्तित्व के बावजूद भारत में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। ऐसे आयातों में कटौती की जा रही है और घरेलू उद्योग की कीमतों पर इसका निराशाजनक प्रभाव पड़ रहा है। कम कीमत वाले आयातों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना पड़ा है।

281. मूल्य में कटौती और दमन के परिणामस्वरूप नकारात्मक लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल हुआ है।

282. घरेलू उद्योग को भौतिक क्षति का खतरा है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

i घरेलू उद्योग की कीमतें संबद्ध आयातों से दबावग्रस्त एवं कम पाई गईं।

ii संबद्ध देशों के उत्पादकों ने कम कीमतों पर बिक्री जारी रखी है।

iii विषयगत देशों के साथ-साथ विषयगत देशों के सहयोगी उत्पादकों के पास अधिशेष प्रयोज्य क्षमताएं।

iv चीनी उत्पादकों को ब्राजील, दक्षिण कोरिया, ताइवान और अमेरिका से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर व्यापार सुधारात्मक उपायों का सामना करना पड़ रहा है।

283. ये आयात घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत से कम कीमत पर भारत में आए हैं।

284. प्रतिपूरक शुल्क लगाना जनहित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:

i उपयोगकर्ता उद्योग की लागत पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य है जो उपयोगकर्ता खंड के आधार पर 0.5% से 1.5% की सीमा में है।

ii चूंकि घरेलू उद्योग ही संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र बड़ा विनिर्माता है, इसलिए घरेलू उद्योग के विनिर्माण परिचालन पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव अपस्ट्रीम उद्योग पर भी पड़ेगा।

iii व्यापार सुधारात्मक उपाय देश में आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, बल्कि आयात और घरेलू निर्माता के बीच समान अवसर सुनिश्चित करते

हैं। एक व्यवहार्य घरेलू उद्योग यह सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता उद्योग पूरी तरह से आयात पर निर्भर न हो।

iv प्रतिपूरक शुल्क का अधिरोपण केवल घरेलू उद्योग को हुई क्षति की सीमा तक ही होगा, अर्थात जांच अवधि के लिए गणना की गई क्षति मार्जिन। इसलिए, शुल्कों का समानांतर अधिरोपण कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, बल्कि अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण हुई क्षति की भरपाई करता है।

ड. सिफारिशों

285. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातक देशों की सरकारों, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों को सब्सिडी, क्षति और कारण संबंध के पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

286. यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि सब्सिडी, क्षति और उनके बीच कारण संबंध के सकारात्मक सबूत हैं, प्राधिकारी का विचार है कि विषयगत देशों से पीयूसी पर प्रतिपूरक शुल्क लगाया जाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकारी नीचे वर्णित रूप और तरीके से विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात पर निश्चित प्रतिपूरक शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। प्राधिकारी ने अपने अंतिम निष्कर्ष एफ.सं. 7/20/2023-डीजीटीआर दिनांक 28.09.2024 के तहत विषयगत वस्तुओं के संबंध में समानांतर सूर्यास्त समीक्षा जांच में एंटी-डंपिंग शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। अनुशंसित सी.वी.डी. का समायोजन, जहां अपेक्षित हो, नीचे शुल्क तालिका के स्पष्टीकरण में प्रदान किया गया है। इसके अलावा, जबकि प्राधिकरण ने निर्यात सब्सिडी को उचित रूप से हिसाब में लिया है।

287. प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए सब्सिडी के मार्जिन और क्षति के मार्जिन में से कम या उसके बराबर निश्चित प्रतिपूरक शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। प्राधिकरण ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि पीयूसी पर पहले से ही एंटी-डंपिंग शुल्क लग रहा है। तदनुसार, निर्यात आकस्मिक सब्सिडी मार्जिन (तालिका पैरा 190 में दिए गए) का सब्सिडी मार्जिन में समायोजन, जहां उपयुक्त हो, प्रदान किया जाना चाहिए।

288. तदनुसार, इ्यूटी तालिका के कॉलम संख्या 7 में उल्लिखित निश्चित प्रतिकारी शुल्क (नीचे संगत स्पष्टीकरण के साथ पढ़ें) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक/ उपशीर्षक/ टैरिफ आइटम	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.0000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0.74	वर्ग मीटर	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्ग मीटर	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	फ़ूजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कंपनी लिमिटेड	0.38	वर्ग मीटर	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	0.58	वर्ग मीटर	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	हुआंगशान जिनरुइताई प्रौद्योगिकी।	0.43	वर्ग मीटर	यूएसडी

6	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	चोंगकिंग हुआफेंग प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड	0.63	वर्ग मीटर	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रमांक (1) से (6) तक के अलावा कोई भी उत्पादक	1.16	वर्ग मीटर	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	कोई अन्य देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	1.16	वर्ग मीटर	यूएसडी
9	-वही-	-वही-	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	0.21	वर्ग मीटर	यूएसडी
10	-वही-	-वही-	ताइवान सहित कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	0.21	वर्ग मीटर	यूएसडी

ढ. आगे की प्रक्रिया

289. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी